छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षोडश सत्र**

सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023

(फाल्गुन 22, शक सम्वत् 1944)

[अंक 06]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023

(फाल्गुन 22 शक सम्वत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

राष्ट्रकुल दिवस का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय :- जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तदनुसार, आज सोमवार, दिनांक 13 मार्च को "राष्ट्रकुल दिवस" पर राष्ट्रकुल देशों ने "forging a sustainable and peaceful common future" (फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एण्ड पीसफुल कॉन फ्यूचर) अर्थात् " स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना" को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश शासन के अधीन रहे एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के 56 स्वतन्त्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परम्पराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह, राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार, भाईचारा, आपसी एकता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय " स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना" के मूलमंत्र को मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने में अपने मानवीय कर्तव्यों के उत्तम निर्वहन का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

समय :

11.02 बजे

निधन का उल्लेख

श्री सोहन पोटाई, पूर्व सांसद लोकसभा के प्रति शोकोद्गार

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि लोकसभा के पूर्व सांसद, श्री सोहन पोटाई का दिनांक 09 मार्च, 2023 को निधन हो गया है।

श्री सोहन पोटाई का जन्म 29 अप्रैल, 1958 को ग्राम-बाबू दबेना, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। उन्होंने एम.ए. समाजशास्त्र तक की शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1998 में तथा तद्न्तर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1999, 2004 तथा 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे लोकसभा की रेल सम्बन्धी समिति, सूचना और प्राद्योगिकी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति सहित अन्य समितियों के सदस्य रहे। उनकी सामाजिक उत्थान तथा रचनात्मक कार्यों में विशेष अभिरूचि थी।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आदरणीय सोहन पोटाई जी के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहुत काम किया है। 9 मार्च को उनका निधन हुआ है। वे ग्रामीण परिवेश से आते थे। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चार-चार बार कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा गये। क्षेत्र के विकास के लिए संसद के सभी समितियों में जहां-जहां उनकी उपस्थिति रही, वे हमेशा अपनी बात रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वे सम्पूर्ण बस्तर के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। हम लोगों ने यह देखा कि जब वे राजनीतिक रूप से सांसद नहीं रहे, तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में ट्रायबल फोर्स का लीडरशीप किया। ना केवल अकेले बस्तर में सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यहां की बैठकों में उनके साथ हम लोगों का सम्पर्क होते रहा है, राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आदरणीय सोहन पोटाई जी काफी एक्टिव थे, अपने समाज के उत्थान के लिये लगातार प्रयासरत् रहते थे, उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र में, विशेष रूप से बस्तर के क्षेत्र में एक आदिवासी नेतृत्व के आधारस्तंभ थे । हम यह मानकर चलते हैं कि यह अपूरणीय क्षति है । मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 मार्च को श्री सोहन पोटाई जी का निधन हुआ । वे कांकेर लोक सभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री सोहन पोटाई जी 12 वीं लोकसभा, 13 वीं लोकसभा, 14 वीं लोकसभा और 15 वीं लोक सभा के सदस्य हैं । वे लोक सभा के महत्वपूर्ण कमेटियों के मेंबर रहे हैं और बस्तर में एक मुखर आवाज के रूप में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे । किसान पृष्ठभूमि के नेता थे, बस्तर के सुदूर गांव के रहने वाले थे, चाहे वह सदन हो या सड़क, सोहन पोटाई जी वहां के आदिवासी भाई, वनवासी भाई और आम जनता की जो पीड़ा है, उसके प्रतिबिम्ब बनकर वह सदन में अपनी बात को बड़ी मुखरता के साथ मे रखते थे । भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन पार्टी से अलग हुये उसके बाद भी, वे वहां की लोगों की आवाज को, बड़ी दबंगता के साथ में सड़क में उठाते रहे हैं, अनेक आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जैसा जुझारू नेता मिलना मुश्किल है । एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे, जुझारू थे, जब तक रहे, वह सक्रिय रहे हैं । मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, उन्हें विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को और स्नेहीजनों को इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन सिंह मरकाम ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय सोहन पोटाई जी का जाना बस्तर के लिये, आदिवासी समाज के लिये अपूरणीय क्षति है । जब तक जिये एक शेर की तरह जिये, बस्तर के विकास के लिये, आदिवासी समाज के विकास के लिये, प्रगति के लिये लगातार लड़ते रहे हैं । उन्होंने अपने केरियर की शुरूआत एक पोस्टमेन की नौकरी से की है । उस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो मिलते थे । उनके मन में हमेंशा यह रहती थी कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, सांसद बनना चाहता हूँ, बस्तर के विकास के लिये, मैं बस्तर की आवाज दिल्ली में बनना चाहता हूँ । चार बार के सांसद रहे और सांसद कार्यकाल में भी हमेंशा अपनी बात प्रमुखता से संसद में रखते थे । अध्यक्ष महोदय, उनके जाने से हमें अपनी कमी महसूस होती है । आप आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदिवासी समाज के हक और अधिकार की बात हमेंशा करते रहे हैं । चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, बस्तर के जल, जंगल, जमीन के मुद्दे हों या वन अधिकार पट्टे की बात हो, एक आवाज बनकर रहते थे । सोहन पोटाई जी हमेंशा आदिवासी समाज के प्रेरणा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, उनका जाना कहीं न कहीं प्रदेश के लिये क्षति है । मैं अपने दल की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, शत-शत नमन् करता हूँ । ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दु:ख की इस घड़ी में परिवारजनों को सहनशक्ति प्रदान करें । ऊँ शांति ।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जी बस्तर की एक बुलंद आवाज थे । अगर बस्तर के नेताओं में हम नाम लें तो बलिराम कश्यप जी के बाद बस्तर के

मुद्दों को उठाने वाले कोई व्यक्तित्व थे तो सोहन पोटाई जी थे, हमारे मित्र थे, मेरे तो पारिवारिक सदस्य जैसे थे । उन्होंने एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ा था, परन्तु उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बस्तर की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजा और जिसने अपना एक स्थान बनाया और बाद में उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के नाम से काम शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों की कठिनाइयों की, उनकी तकलीफों के लिये आवाज बुलन्द की। उनको अचानक कैंसर हो गया। वह पिछले छः महीनों से जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व, शायद उनका यह समय ऐसा नहीं था कि वह हमारे बीच से चले जाये परंतु वह हमारे बीच में नहीं रहे। हम प्रभु से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति मिले। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत-बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री शिशुपाल सोरी (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जी के आकस्मिक निधन से हमारा पूरा बस्तर और पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध है। वह आदिवासी समाज की एक प्रखर आवाज बनकर उभरे थे और जहां समाज की बात होती थी, वह किसी भी मुद्दे पर पार्टी के लीग से हटकर भी अपनी आवाज को बुलंद करते थे। उनका व्यक्तित्व एक निष्पक्ष और बिना किसी बात की परवाह किये बगैर सच्चाई को बोलने की एक आमादा होती है, वह उस पर आमादा थे। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती थी किंतु मैं समझता हूं कि यही उनकी ताकत थी कि किसी भी बात को निष्पक्षता के साथ आवाम के सामने रखना, इसीलिये उनको लोग इतना प्यार करते थे और इसीलिये वह संसदीय इतिहास में लगातार चार बार कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होते रहे। उनका जो गांव है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही आता है। उनका और हमारा पारिवारिक संबंध भी था। हम लोगों ने साथ मिलकर हमारे समाज के लिये हर मुद्दे में बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। वह जब सांसद थे, तब मैं प्रशासकीय सेवा में था, तब भी हम लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल था कि हम सामाजिक मुद्दे पर साथ आकर बस्तर के और समाज की आवाज को बुलंद करते थे। ऐसे व्यक्ति के आकस्मिक रूप से चले जाने से पूरे बस्तर संभाग को, हमारी पूरी जनजाति समाज को अपूरणीय क्षित हुई है। मैं भगवान बड़ा देव से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पोटाई जी चार बार सांसद रहे और संसद में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिये वह अनेक प्रश्न भी उठाते थे। हम दोनों साथी के रूप में थे। मैं उनका सहयोगी था, वह मेरे सहयोगी थे। हम एक ही जगह, नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे। उन्होंने आदिवासी समाज के लिये इतनी लड़ाई लड़ी। वह अपनी पार्टी की तरफ से भी हंगामा करने में

कम नहीं थे, वे साहसी थे। उन्होंने समाज में अच्छा नाम किया और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने में, यहां तक की आदिवासी समाज का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बने, उनकी लड़ाई में ऐसी भूमिका थी। मैं ऐसे साहसी व्यक्ति को धन्यवाद् भी देता हूं और श्रद्धांजलि भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सोहन पोटाई जी का व्यक्तित्व और कृतृत्व देखा है । उन्होंने एक दबंग नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यदि लोकप्रियता की बात करे तो एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा जीतने में दिक्कत आती है लेकिन वह लगातार चार बार लोकसभा का चुनाव जीते। उसके साथ ही उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर जल, जमीन और जंगल की आवाजें भी बुलंद की गयी। हमने उनकी सहजता और सरलता को भी देखा है। उनसे कोई भी मिलने के आये तो वह मिलने से कभी इंकार नहीं किये। उन्होंने अपने क्षेत्र में कभी यह एहसास भी नहीं कराया कि मैं एक सांसद हूं बल्कि एक बड़ा भाई और छोटा भाई का एक जो व्यवहार है उन्होंने अपने जीवन में निभाया है। समाज के लिए काम करने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने समाज को प्राथमिकता दी और हमेशा उन्होंने जीवन में उनके लिए संघर्ष किया। जब वह सांसद रहे तो काम करते रहे, जब वह सांसद नहीं थे तो भी वह काम करते रहे। पूरे प्रदेश का दौरा करके, आदिवासी समाज को लेकर चलने का काम किया। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। जो उनकी मूल सोच थी, जो शोषणमुक्त समाज की रचना करना है और उसके साथ में जो दलित, शोषित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, यह उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। निश्चित रूप से हमने सोहन पोटाई जैसे नेता को खोया है और यह अपूरणीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

वाणिज्यिक कर (आबकारी)मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सोहन पोटाई जी कांकेर से 4 बार सांसद थे। वह सांसद नहीं होने के बाद, हमारे सर्वआदिवासी समाज के अध्यक्ष थे। बस्तर की आवाज, आदिवासियों की आवाज चाहे सांसद के रूप में हो और सांसद होने के बाद भी जब वहां परिसीमन हो रहा था बस्तर लोकसभा क्षेत्र सामान्य होने जा रहा था। वह भारतीय जनता पार्टी में रहकर, उसी सरकार के खिलाफ लड़े कि यह सीट का बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं होगा, यह आदिवासी सीट रहेगा। अगर बस्तर लोकसभा संसदीय क्षेत्र आदिवासी के नाम से बचा है तो उन्हीं के कारण बचा है। उन्होंने उस क्षेत्र के लिए बहुत आन्दोलन किया। वह बड़े-बड़े नेताओं के साथ लड़े और आदिवासी सीट बचाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद जब उन्हीं की लड़ाई के कारण उनको टिकट भी नहीं मिली। वह कभी नहीं हारे। वह चार बार लगातार जीते और कभी चुनाव हारे नहीं। उन्हें टिकट नहीं

मिलने के कारण आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बने। वह लगातार प्रयास कर रहे थे सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासियों की आवाज बुलंद हो। हमारे ऐसे आदिवासी नेता के बीच में नहीं होने से आदिवासी समाज को बहुत दु:ख पहुंचा है। जब वह एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैं वहां भी गया था। रायपुर में मेरे आवास के बाजू में उनका मकान है मैं,उनसे लगातार मिलता रहा। लेकिन 7-8 महीने लगातार बीमार होने के बाद भी, मैंने उनको देखा कि आदिवासियों के प्रति उनका हौंसला और ताकत वैसा ही था। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। जब अभी भानुप्रतापपुर का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हमेशा चिन्ता रहती थी कि हमारे आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो यह कैसे होगा? वह उंगली के ईशारे से बात कर रहे थे और सब लोगों को राय दे रहे थे। मैंने इतनी हिम्मत करने वाले नेता को पहली बार देखा है, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं, उनको आदिवासी समाज की तरफ से और बस्तर की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। हम ऊपर वाले मालिक से यही निवेदन करते हैं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार को इस दु:ख को सहने की ताकत दे और मदद करे। इसी आशा के साथ हमने जो अपना आदिवासी नेता खोया है, यह हमें बहुत अखरा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोहन पोटाई जी जब अपने जीवन की शुरूआत की तो उन्होंने मेरे ब्लॉक विश्रामपुरी से पोस्ट ऑफिस की नौकरी से शुरूआत की। उस समय हम लोग छोटे-छोटे थे जब वर्ष 2013 में पहली बार विधायक बनकर आया तो उनसे राजनीतिक झड़प हुई। उन्होंने मुझे शाम को बुलाकर कहा कि आप अभी नये हो और यह राजनीति में चलते रहता है इसको आप माईंड नहीं करना। इस प्रकार से माननीय सोहन पोटाई जी लगातार एक अपने आप में इतिहास है कि चौथी बार, कांकेर लोकसभा से सांसद रहे और दिल्ली में हमारे बहुत से सांसद लोग जाते है, लेकिन पार्लियामेंट में अपनी बात को नहीं रख पाते, पर माननीय सोहन पोटाई जी ने बस्तर की आवाज, आदिवासियों की तकलीफ को दिल्ली के सांसद भवन में रखने का काम किया। इसलिए हम लोग बस्तर के पूरे आदिवासी समाज को उनके नाम से हमारा एक घमण्ड भी कहना चाहिए, उनकी आदिवासियों के लिए जो आवाज थी, वह एक दंबग नेता के रूप में सामने आये । अपनी कोई भी बात हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, समाज के हितों के लिए भी उन्होंने काम किया। अभी कुछ सालों से वे आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। दिनांक 09 मार्च 2023 को उनका अचानक निधन हो जाने से हमारे पूरे आदिवासी समाज, बस्तर के लिए और राजनीतिक रूप से भी हमको बहुत क्षति हुई है। मैं इस मौके पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो दु:ख है उसको सहन करने की क्षमता दे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित।

(11.22 से 11.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11.30 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोण्डागांव को जिला निर्माण समिति, कोण्डागांव द्वारा आंबटित कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 698) श्री मोहन मरकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोण्डागांव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) को विगत 02 वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.1.2023 तक जिला निर्माण समिति, कोण्डागांव द्धारा कौन-कौन से कार्य, कितनी राशि के आबंटित किए गए? आंबटित कार्य किस-किस विभाग से संबंधित थे ? कार्य का प्रकार क्या था ? वर्षवार, कार्यवार ब्यौरा देवें । **(ख)** कंडिका " क " के अनुसार क्या कार्य के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पालन अथवा निविदा मंगायी जानी थी ? यदि हां तो उक्त कार्यों की निविदा किस अखबार में, किस दिनांक को प्रकाशित करायी गयी ? ब्यौरा देवें । **(ग)** कंडिका" ख " के अनुसार निविदा में किन-किन निविदाकारों ने मूल्य कथन प्रस्तुत किया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : **(क)** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोण्डागांव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) को विगत 02 वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.1.2023 तक जिला निर्माण समिति, कोण्डागांव द्धारा कार्य आबंटित नहीं किया गया है। **(ख)** उपरोक्त (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उपरोक्त (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो जानकारी जानना चाहा था, उसका उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि क्या

कोण्डागांव जिला निर्माण समिति के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोण्डागांव, नोडल एजेंसी निर्धारित है? यदि हाँ तो कब से?

श्री अजय चंद्राकर :- मरकाम जी, जब उत्तर आ गया है तो संतुष्ट होकर बैठ जाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, उत्तर में ही स्पष्ट है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट। उस दिन आसंदी ने मोहन मरकाम जी के प्रति बड़ी सदाशयता दिखाई। उनके आधा भाषण को पूरा मान लिया गया। यहां से कोण्डागांव गये तो कलेक्टर ने अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं कर सकते कह कर वहां से भगा दिया। [xx][1] वह दोनों जगह लटक गये। वह न इधर के हुए, न उधर के हुए।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तुम्हारे पास सही खबर तो नहीं रहता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या भरोसा है। मरकाम जी, न इधर के रहे, न उधर के रहे, फिर क्या बचा, यह बताईये?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को वह दो बार [xx] बोले, उसको विलोपित कर दीजिये। एक तो वह [xx] नहीं हैं। वह हमारे अध्यक्ष हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- [xx] तो इसलिए कहना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हटाने में लगे हैं और आपके पड़ोसी बचाने में लगे हैं। तो वह [xx] ही हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वह [xx] नहीं हैं।

श्री अरूण वोरा :- भैया, आपको दूसरों के घर की चिंता क्यों रहती है? आप अपनी चिंता कर लो न। 15 साल में 15। अब कितने? अब कितने?

श्री अजय चंद्राकर :- आजकल आपको भारी उत्तेजना हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल है। माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग अपने नेता प्रतिपक्ष को तो नेता मानते नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जो प्रश्न पूछा है। उन्होंने आर.ई.एस. विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य आवंटन के बारे में प्रश्न पूछा है। दो एजेंसी एक साथ काम नहीं कर सकती है। चूंकि वह नक्सली क्षेत्र है और शासन के लिए आदेश है कि इसके लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। आदेश की कॉपी भी आपके प्रश्न के उत्तर में लगा है। बिना निर्माण समिति के द्वारा कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि नोडल अधिकारी, अध्यक्ष के रूप में

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

या समिति के रूप में नामजद कर सकता है तो कलेक्टर ने आर.ई.एस. के ई.ई. को नामजद किया है। आपने प्रश्न किया है कि आर.ई.एस. को नोडल अधिकारी के रूप में काम दिया है क्या? इसलिए निरंक बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जिस अवधि का प्रश्न पूछा है, आपने 3 साल का आपने पूछा है, उसमें आपके कोण्डागांव में लगभग 69 करोड़ रूपये का 424 काम हुए हैं और यह इसमें लगभग 340 भवनों का काम है और 84 सामग्री क्रय व विभिन्न प्रकार के काम हैं। इस प्रकार के काम वहां पर संपादित किए गए हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि आर.ई.एस. निर्माण एजेंसी है। यह भवन बनाती है। आर.ई.एस. ने लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि सप्लाई का काम किया है। मतलब आर.ई.एस. कब से सप्लाई का काम करने लग गई है? मैं यही जानना चाहता हूं कि आर.ई.एस. कब से सप्लाई का काम कर रही है?

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, आपकी सरकार में सब संभव है।

श्री मोहन मरकाम :- आर.ई.एस. निर्माण एजेंसी है, वहां तक तो ठीक है, मगर सप्लाई का काम आर.ई.एस. भी करने लगी है, मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- भूपेश है तो भरोसा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा लगा, अजय जी ने नारा लगाया कि भूपेश है तो भरोसा है। मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) यह पूरा प्रदेश की जनता कहती है।

आपने प्रश्न किया है कि विभाग कब से सप्लाई कर रही है? मैंने फिर से जवाब दे देता हूं कि दो एजेंसी एक साथ काम नहीं कर सकती। वहां निर्माण समिति नोडल एजेंसी है, जिसके भारसाधक के रूप में आर.ई.एस. के ई.ई. को दिया गया। उसके द्वारा यह कार्य कराया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोण्डागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? क्या उक्त अधिकारी को किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है ? यदि हां तो वर्तमान में किन-किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है, अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है ? उक्त अधिकारी कोण्डागांव जिले में कितने वर्षों से है क्योंकि वही 5-6 विभागों को संभाल रहा है । जो बातें आ रही हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काम के सिलसिले का प्रश्न था । कौन-कौन अधिकारी कितने-कितने पद में है, मैं इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिला चूंकि आप भी उसी जिले से आते हैं । डी.एम.एफ. राशि का जिस ढंग से स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है । लगभग 7 करोड़ रूपए कागजों में यानी सप्लाई का काम किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप उसका

नाम उजागर क्यों नहीं करना चाहते हैं और किस-किस विभाग में वह व्यक्ति पदस्थ है ? और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है और सबसे बड़ी बात आप आर.ई.एस. को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं । वह सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है तो क्या इसकी विधानसभा की समिति से जांच करायेंगे और क्या दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि लगभग 7 करोड़ रूपए डी.एम.एफ. के पैसे का इन्होंने स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया है, क्या विधानसभा की समिति से इसकी जांच करायेंगे ? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- बलौदाबाजार में 30 करोड़ है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है । आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है, आपको तत्काल यहीं घोषणा करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- तत्काल घोषणा नहीं, तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, त्यागपत्र दे देना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का उत्तर आ रहा है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति भरोसा नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बार-बार खड़े होते हैं । एक आदमी खड़े होकर बोल सकता है । सौरभ जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पार्टी का सरकार के प्रति भरोसा नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सरकार के प्रति भरोसा नहीं है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सत्ताधारी पार्टी का विधायक और प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बोले तो तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । आप लोग शांत रहिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश में डी.एम.एफ. फंड का जिस तरीके से स्वार्थपूर्ण बंटवारा हो रहा है, लूट हो रही है, कमीशनखोरी हो रही है और माननीय मोहन मरकाम जी ने जो प्रश्न उठाया है । इस पर तत्काल सदन की जांच कमेटी से जांच होनी चाहिए । आज कमेटी गठित करने का आदेश दे दें ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. फंड के पैसे का पता अभी तो चल रहा है लेकिन 15 सालों तक डी.एम.एफ. फंड का पैसा कहां गया, आज तक किसी को पता नहीं चला है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आप 15 साल को छोड़िए, अभी की बात करिये न । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- नहीं-नहीं, मैं सच बात बोल रहा हूं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, वोरा जी उत्तर आने दीजिये । आपकी बात आ गयी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न लगाया है, मामला बड़ा गंभीर है । हम तो अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने गंभीर मामले को उठाया है और हमने कहा न कि जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे दी गयी है । माननीय मोहन मरकाम भाईसाहब ने जो पूछा है कि क्रय विभाग के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी मैं फिर से कह रहा हूं कि निर्माण समिति के द्वारा किया गया है नंबर एक ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जांच समिति की बात की है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पूरा उत्तर आने दीजिये न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर आने दीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आदरणीय मरकाम साहब ने पूछा है कि वहां कौन अधिकारी है अरूण कुमार शर्मा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर । सत्यनारायण शर्मा जी ने भी बोला, आप क्यों चौंक रहे हैं ? (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह वोरा है कि शर्मा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अरूण कुमार शर्मा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर । आपने कहा कि कौन-कौन से पद में हैं ? यह आर.ई.एस. के प्रभार में भी है और पी.एम.जी.एस.वाई. के प्रभार में भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, नारायण चंदेल जी ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंभीर मसला है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह आपका अंतिम है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा आरोप लगाया है कि लगभग 7 करोड़ रूपए की जो सप्लाई हुई है उसमें बहुत ज्यादा स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है । क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल साहब आप बोलिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- एक-साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या विधानसभा की कमेटी से जांच करायेंगे और क्या दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी और मोहन जी दोनों का आप एक-साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो निर्माण एजेंसी है, क्या निर्माण एजेंसी को सप्लाई क्रय करने का अधिकार भी है ? और अगर

उसको अधिकार है तो माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं कि 7 करोड़ रूपए का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है तो क्या मंत्री जी उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बृजमोहन जी को पहले प्रश्न का अधिकार है। जी हां। अधिकार है। चूंकि ये आप ही के समय का निर्देश है। मैं इसे पूरा पढ़कर नहीं सुनाउंगा। उसको अधिकार है और कलेक्टर को यह अधिकार है कि जिसको भी वह नोडल बनाना चाहे, वह बनाये। उसी के तहत् यह आदेश हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, आदरणीय मरकाम साहब कह रहे हैं कि पूरा 7 करोड़ का स्वाथपूर्ण बंटवारा हुआ है। उपाध्यक्ष जी, अगर ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ का इस तरीके से स्वाथपूर्ण बंटवारा हुआ होगा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी से प्रश्न किया है। इसकी जांच करानी है तो मैं यहां राज्य स्तर के अधिकारी भेजकर इसकी जांच करा दूंगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, नारायण चंदेल जी। मरकाम साहब हो गया। उत्तर आ गया। वे जांच करा देंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उस व्यक्ति ने पूरा स्वाथपूर्ण बंटवारा किया है, उसके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया। जांच का आदेश हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- आप विधान सभा की समिति से जांच कराने की घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं। आप विधान सभा की समिति से जांच कराने की घोषणा करेंगे। हम लोग वहां के 3 विधायक हैं, जिसमें से एक तो विधान सभा उपाध्यक्ष हैं। हम 2 विधायक हैं। हम 2 विधायकों को उस समिति का सदस्य बनाने की घोषणा करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह कमेटी भी घोषित कर दें।

श्री मोहन मरकाम :- हम उस जिले में 3 विधायक हैं। 2 विधायकों को उस समिति का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वे आज कितने भयमुक्त होकर बोल रहे हैं। पहली बात।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या होकर?

श्री धर्मजीत सिंह :- भयमुक्त। आपने अधिवेशन में फोटो लगाया नहीं। आपने बयान दे दिया है कि वे हटने वाले हैं। सरगुजा से बनने वाले हैं। अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे तो और कैसा प्रश्न पूछेंगे? (हंसी) इसलिए आप कृपा करके धड़ाधर जवाब दीजिए और उनकी भावना का सम्मान करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, जहां तक विधान सभा की कमेटी से जांच कराने का बात है, 7 करोड़ का मसला है और 3 साल की खरीदी की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके लायक छोटा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, मैंने छोटा नहीं बोला। मैंने कहा कि 3 साल की खरीदी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत जवाबदारी से यह प्रश्न किया है, उन्होंने कहा भी कि बहुत जागरूक जिला है। वहां के विधान सभा उपाध्यक्ष हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। अगर माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं राज्य स्तर के अधिकारी से जांच कराने का निर्देश जारी कर दूंगा (मेजों की थपथपाहट) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल निर्देश नहीं, मैं एक महीने का टाइम लिमिट कर देता हूं और यह समझ लीजिए। चूंकि यह तो बहुत पुराने कार्यकाल के पूरे मसले हैं। एक महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल साहब।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समिति से जांच कराने में क्या परेशानी है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी ने इसी प्रकार डी.एम.एफ. के मामले में जांजगीर का भी मामला आया था, उसमें भी कहा था। तो डी.एम.एफ. में तो लगभग 50 प्रतिशत का भ्रष्टाचार हो रहा है, यह जगजाहिर है और ऐसे गंभीर मामले में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे की बर्बादी हो रही है तो आपसे चाहेंगे कि माननीय सीनियर सदस्य मोहन मरकाम जी बोल रहे हैं। आप विधान सभा की समिति की घोषणा कर दें और वे बोल रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है। आप इसके लिए एक समिति बना दें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो क्या, उसमें क्या आपत्ति है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भी उसी जिले के हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की समिति से जांच कराने में क्या आपत्ति है?

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया। चलिए, नारायण चंदेल साहब। वे जांच करा देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा साहब, प्रश्न आने दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, अपने नेता की बात सुन ही नहीं रहे हैं। उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मंत्री के सामने क्या हैसियत है? वे जांच की बार-बार मांग कर रहे हैं कि सदन की समिति बनाकर जांच करा दें। मंत्री जी, इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, जांच होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी जिले से आते हैं। माननीय सदस्य ने आपका नाम भी लिया। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सदन की समिति से जांच करवाने में आपत्ति क्या है?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- भइगे, जा बहिर्गमन कर दे। (हंसी)

<u>गोधन न्याय योजना में गोबर का विक्रय</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 555) डॉ. रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने के बाद अब तक कितने विक्रेताओं से कितनी मात्रा में गोबर की खरीदी शासन द्वारा की गई है? जिलेवार बताएं? कितनी राशि का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया गया है? (ख) कितने गोबर विक्रेताओं से एक लाख से अधिक मूल्य का गोबर क्रय किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) गोधन न्याय योजना प्रारंभ से 15 फरवरी 2023 तक कुल 352522 विक्रेताओं से 1,05,50,682.51 क्विं. गोबर की खरीदी गोठान समिति के माध्यम से की गई है। गोबर विक्रताओं को राशि रू. 21101.37 लाख का भुगतान किया गया है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र †[2] अनुसार है। (ख) 1575 गोबर विक्रेताओं से एक लाख से अधिक मूल्य का गोबर क्रय किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है, वह गोधन न्याय योजना से संबंधित है और गोबर खरीदी से संबंधित है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। एक तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉ. रमन सिंह जी का प्रश्न है और नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारे विद्वान सदस्यों का गोधन न्याय, गोबर खरीदी और गौठान पर प्रश्न लगा है। सौरभ जी का भी लगा है। रजनीश भाई साहब का भी लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोबर, गोधन न्याय का बहुत सम्मानपूर्वक प्रश्न करना। पहले दिन से माननीय अजय चन्द्राकर जी बहुत व्यंग्यात्मक प्रश्न लगातार कर रहे थे। अब इसकी महत्ता को समझ लीजिए। आप गंभीर प्रश्न करिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- आप गंभीरता से उत्तर देना । मैंने उत्तर में जो फीगर आए हैं उनको देखा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । प्रश्नांकित अवधि में खरीदे गए गोबर

[2] † परिशिष्ट "एक"

से कितने क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, गो-काष्ठ एवं सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है तथा इससे कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? खाद की खराब गुणवत्ता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, प्रश्न काफी डिटेल में है, इसलिए उत्तर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बता दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न टोटल गोबर खरीदी के बारे में है । योजना प्रारंभ होने से लेकर 15.02.2023 तक जो गौठान स्वीकृत हुए हैं उनमें लगभग 4 लाख, 45 हजार पंजीकृत पशुपालकों से, लाभान्वित पशुपालक 3 लाख, 28 हजार से गोबर खरीदा गया । आपका मूल प्रश्न था कि 1 लाख से ज्यादा राशि किनको दी गई है ? लेकिन आपने टोटल गोबर खरीदी और राशि के भुगतान के बारे में प्रश्न किया है । 105.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और कुल 211 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह तो आ गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रश्न तो उसी के ऊपर है । इसके आगे उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट की क्वालिटी की शिकायत के बारे में पूछा और कहां कुछ पूछा है ? फिर आप ही प्रश्न दोहरा दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं । प्रदेश में गोबर खरीदी हेतु कितने गौठान समिति तथा कितनी गोधन खरीदी केन्द्र संचालित हैं । यही बता दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जब मैं इसी को पढ़ रहा था तो बृजमोहन जी ने टोक दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे बहुत सम्मान से पूछ रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उतने ही सम्मान से मैं उत्तर दे रहा हूं । उपाध्यक्ष जी, टोटल गौठान 10, 687 उसमें से गोबर क्रय 9,560 गौठानों में हो रहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- एक प्रश्न और । माननीय आप यह बता दीजिए कि खरीदे गए गोबर से कितने लीटर पेंट का निर्माण किया गया है । आप बता रहे थे कि इसकी पोताई हो गई, उसकी पोताई हो गई । आपने बताया है कि 1575 विक्रेताओं ने एक लाख से अधिक का गोबर बेचा है, ठीक है । उन्हें अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? यह दोनों प्रश्न एक साथ है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक लाख रूपए से अधिक भुगतान जिन लोगों को हुआ है, इसमें 33 डेयरी, 9 गौशाला, 1533 पशुपालक हैं । पहला नाम है प्रेम आर्या, ममा जानथन ना ?

श्री पुन्नू लाल मोहले :- हां हां, मोरे क्षेत्र के हे, मुंगेली के हे ।

श्री नारायण चंदेल :- नाम झन पढ़ ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- 1 लाख से ज्यादा वाले तैं पूछेस ना ।

श्री नारायण चंदेल :- फीगर बता दे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- फीगर । इसमें महावीर...।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि चौबे जी ने बहुत दुहाई दी है कि गोबर खरीदी में यह हो गया और बहुत पैसा दिया गया है । 2020 से अभी तक आपने जितना बताया है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं । ओकर हिसाब लगाएंव तो 6 रूपया प्रतिदिन आथे । मनरेगा के एक दिन के 200 रूपए भुगतान होथे अउ एकर प्रतिदिन के भुगतान 6 रूपया के हिसाब से होए हे । एमा संशोधन करने के या नवा बनाए के हे जेखर से ओला रोजी मिल जाए, गोबर के अतना पइसा मिल जाए । 6 रूपया प्रतिदिन मा छत्तीसगढ़िया ला ठगे गे अउ छत्तीसगढ़िया के पेट भरने वाला नइ हे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, ये 23वें, 24वें नम्बर पर माननीय रजनीश जी का प्रश्न है उसी को लेकर धरम भइया ने यह प्रश्न कर दिया कि 6 रूपया प्रति दिन के हिसाब से गौपालकों को मिल रहा है, जिन्होंने गोबर का विक्रय किया है । अरे श्रीमान्, वह 3 किलो गोबर बेचकर रोज 6 रूपया कमाता है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है । जब मर्जी तब गोबर ले जाता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ओ गाय ह ना जब मर्जी होथे तब गोबर करथे, नहीं ते नई करय। गौठान समिति में नियमित रूप से आथे, एकाध बार चेक करे बर गे हस। चेक करे बर नई गे हस । ओखर रजिस्टर ला जा के देखबे। कईसनहा चंदी आत हे, दूध कस चंदी गोबर के ।

श्री रामकुमार यादव :- गरवा, बछरू के गोबर करै के टाईम टेबल नई रहाय गा, बबा।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न किया था कि यह जो एक लाख रूपए से अधिक जो सेल किए हैं, उनको टोटल कितनी राशि मिली है। इसकी टोटल मात्रा 15.63 लाख क्विंटल है। इसका मतलब लगभग 30 करोड़ रूपए है। टोटल 211 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ है। उसमें यह जो 1533 लोग हैं, उनको 30 करोड़ रूपए भुगतान हुआ है जिसमें गौशाला भी शामिल है। माननीय डॉ. साहब ने जो प्रश्न किया है, उनकी काउंसटेंसी का सबसे बड़ा राजनांदगांव का गौशाला भी शामिल है। इसमें महावीर गौशाला भी शामिल है। सारे लोगों को डेयरी का जो काम था, जिसको घाटे का काम मानते थे...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज भी एक साथ गौशाले का गोबर नहीं बेच रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं लिस्ट बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप एक साथ नहीं खरीद रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी एक साल से क्यों नहीं खरीद रहे हैं, उसको दिखवा दूंगा। लेकिन महावीर गौशाला को लगभग 10 लाख 42 हजार रूपये का पेमेंट हो चुका है। अभी एक साल से नहीं खरीद रहे हैं, मैं अभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा। जब हम ऐसी योजना बनाएं हैं तो चलना चाहिए। उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपने पूछा ना...।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गाय और भैंसों से गोबर खरीदा गया है, यह बताएंगे ? (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं और प्रश्न कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्वाईंटेड प्रश्न पूछिए। यह कोई प्रश्न थोड़ी होता है। प्रश्न ऐसा नहीं होता है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जब ले ये गोधन न्याय योजना चलत हे ना ये विपक्ष के साथी मन के दिमाग मा पूरा गोबर भर गे हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, ये गिनती करे बर जो बनाय गे हे उसमें इनको लेकर जाईए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उपाध्यक्ष जी, भुगतान बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां भुगतान के बारे में पूछ लीजिए। अब कितने गाय, भैंस बोलोगे तो कैसे होगा ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनको गिनती करने के लिए भेजा जाए। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मुंगेली में 7 डेयरी का भुगतान नहीं हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, भुगतान के विषय में पूछ लीजिए। मंत्री जी बता दीजिएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने जो प्रेम आर्या का नाम लिया, उनका नाम है। शर्मा का भुगतान नहीं हुआ है, यादव का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सी डेयरी का भुगतान नहीं हुआ है। वे लोग 300 गायों का गोबर बेचते हैं। वैसी पूरा प्रदेश का भुगतान का बता दीजिए। भुगतान कहां-कहां पर नहीं हुआ है और कितने गाय और भैंस हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, भुगतान के संबंध में बताईए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- भुगतान से संबंधित है तो आप भी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- भुगतान से संबंधित है और गोबर से संबंधित मेरा भी प्रश्न लगा है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन दिल्ली में एक ठन प्रस्ताव कर देव। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ छोटा-छोटा दो प्रश्न कर रहा हूं। एक तो गोबर बेचने के क्या नियम हैं और गोबर कौन बेच सकता है ? दूसरा, मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि

67 प्रतिशत का उपयोग हुआ है, 33 प्रतिशत का नहीं हुआ है। जितना गोबर का भुगतान हुआ है, उसमें सरकार को कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, भुगतान और नियम बता दीजिए। इसके बाद आप तैयार रहिए। इसमें लगभग सब प्रश्न आ गये हैं। अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरे मामा जी हैं। उन्होंने भुगतान के बारे में प्रश्न पूछा है। यह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर 15 वें दिन गोधन न्याय योजना का भुगतान होता ही है। अगर मुंगेली जिले में शेष है..।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सिर्फ चार लाईन....।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उसको...। तोर हो गे ना। दूसरा, रजनीश जी ने प्रश्न किया। रजनीश जी के प्रश्न तक का उत्तर तो आयेगा नहीं। वह नंबर जायेगा नहीं। उन्होंने पिछले प्रश्न का हवाला दे करके 67 प्रतिशत के बारे में पूछा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, तब गोबर से वर्मी कम्पोस्ड, सुपर कम्पोस्ड के परिवर्तन का जो रेशियों था, हम लोग 42 से 44 प्रतिशत मानते थे, लेकिन 2 साल योजना चलाने के बाद हमारी जो विशेषज्ञों की टीम है, उन्होंने कहा कि 33 से 34 प्रतिशत से अधिक इसमें खाद नहीं बन सकता। इस कारण आदरणीय रजनीश जी ने जो प्रश्न किया है, वह जो हुआ है, उतनी कमी इसलिए पाया गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- भुगतान करेंगे क्या, भुगतान के बारे में बताईए ?

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी। अब यह प्रश्न समाप्त हो गया। आप प्रश्न कीजिए।

<u>विधानसभा क्षेत्र पामगढ अंतर्गत संचालित आंगनबाडी केन्द्र एवं भवन</u>

[महिला एवं बाल विकास]

3. (*क्र. 596) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, कितने आंगनबाडी केन्द्र भवन विहिन या किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31-01-2023 तक कितने नये आंगनबाड़ी भवन बनाये गये हैं? केन्द्र का नाम, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत 359 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 85 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 18 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहिन व 50 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में

संचालित किये जा रहे हैं। केन्द्रवार जानकारी संलग्न[3] प्रपत्र अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31-01-2023 तक नये बनाये गये आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी भवनों की संख्या निरंक है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से जो प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में कुल 359 आंगनबाड़ी केन्द्र है और 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जिसमें से लगभग 167 भवनविहीन है तो मैं माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहूंगा कि 167 मतलब लगभग 50 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं तो इसके क्या कारण हैं और विभाग की ओर से इसके लिए क्या प्रयास किये गये हैं? मेरा पहला प्रश्न यह है और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 तक एक भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं किया गया है तो मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहूंगी कि हमने लगातार पत्र के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी जर्जर और नवीन आंगनबाड़ी भवन हैं, उन्हें बजट में शामिल करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इसके क्या कारण हैं कि वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2022-2023 तक इनके कार्यकाल में इन्होंने एक भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या उपलब्ध करा दी है और जो वर्ष 2022-2023 में एक भी भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो इसके लिए केन्द्र से कोई बजट नहीं आया है इसलिए वर्ष 2022-2023 में एक भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं किया गया है और पूर्व में कुछ भवनों की स्वीकृति हुई है। उनमें से कुछ अपूर्ण हैं और कुछ का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार ने भी अब इसका रेट 12 लाख रूपये कर दिया है इसके कारण नहीं हुआ है। हम हमारे प्रदेश से या जिला पंचायत से इसके लिए इस्टीमेट देते हैं। हम 8 लाख रूपये मनरेगा से देंगे और 2 लाख रूपये 15 वित्त से देंगे। 1 लाख रूपये केन्द्र सरकार और 1 लाख रूपये राज्य सरकार देगी। इसलिए अभी इसके वित्त और इस्टीमेट के लिए के लिए इसको भेजा गया है। उसके बाद से जो स्वीकृति हुई है उसका निर्माण भी कराएंगे और जिसकी स्वीकृति नहीं हुई है उसके लिए हम केन्द्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि यहां राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं उसकी स्वीकृति के लिए हम पत्र लिख रहे हैं और अभी राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दे दी है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने की स्वीकृति मिली है या आपने अभी

[3] परिशिष्ट "दो"

अपने जवाब में कहा कि कुछ कार्य स्वीकृत हैं और कुछ कार्य अधूरे हैं तो मैंने अपने प्रश्न में आपसे यह भी पूछा था कि कितने आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो रहा है और कितने अपूर्ण हैं, लेकिन आपने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी है तो आप मुझे इसकी सूची भी उपलब्ध कराइये और यदि केन्द्र सरकार राशि नहीं देती है तो क्या राज्य सरकार आंगनबाड़ी भवन नहीं बनाएगी ? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है इसलिए इसमें केन्द्र और राज्य दोनों का 50-50 प्रतिशत हिस्सा होता है। पहले यह 80-20 प्रतिशत था, उसके बाद 60-40 हो गया और अभी यह 50-50 प्रतिशत हो गया है तो इसमें दोनों सरकार की स्वीकृति होती है और इसमें दोनों सरकार की 50-50 प्रतिशत राशि होती है। स्वीकृत भवनों में से 53 भवन अभी अपूर्ण हैं। केन्द्र सरकार ने इसके लिए 12 लाख रूपये का इस्टीमेट भेजा है और हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। जैसे ही राशि की व्यवस्था होगी, उसके बाद हम भवन निर्माण का कार्य चालू करवा देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- बृजमोहन जी, आपका नाम नहीं पुकारे हैं।

<u>विभाग में संविदा नियुक्ति की जानकारी</u>

[जल संसाधन]

4. (*क्र. 678) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल संसाधन विभाग में वर्तमान में उपअभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता पद पर कितनी-कितनी संख्या में सेवा निवृत्त अधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति दी गयी है, सेवा निवृत्त अधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति देने का क्या नियम है ? (ख) विगत दो वर्ष के दौरान नियमित पद पर पदस्थ नियमित अधिकारियों को हटाकर/स्थानांतरण कर उनके स्थान पर कितने संविदा नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों को पदस्थ किया गया है, पदवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) क्या संविदा नियुक्त किसी अधिकारी को वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार भी दिया गया था? यदि हाँ तो किस-किस को ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जल संसाधन विभाग में वर्तमान में दिनांक 01.03.2023 की स्थिति में 02 उप अभियंता, 16 सहायक अभियंता, 03 कार्यपालन अभियंता, 06 अधीक्षण अभियंता एवं 0 मुख्य अभियंता पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-9/1/2012/1-3, दिनांक 17 जनवरी, 2013 के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा नियुक्ति दी जाती है। (ख) विगत 02 वर्ष (2021 एवं 2022) में संसाधन विभाग में नियमित पद पर पदस्थ किसी भी नियमित अधिकारी को हटाकर/स्थानांतरण कर उसके स्थान पर संविदा नियुक्त अधिकारी को पदस्थ नहीं किया गया है। (ग) संविदा पर नियुक्त निम्न

अधिकारी को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार थे:- 1. श्री रामास्वामी नायडू, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, 2. श्री अशोक कुमार तिवारी सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, 3. श्री आर.पी. शुक्ला सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, 4. श्री एल.एल. देवागंन, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या संविदा कर्मचारियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने के निर्देश है ? यदि निर्देश नहीं है तो आपने जिन 4 अधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये हैं, क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? छत्तीसगढ़ में कितने सब इंजीनियर, कितने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, कितने सीनियर इंजीनियर, कितने चीफ इंजीनियर के पद रिक्त हैं और उनमें से कितने पद स्वीकृत हैं, कितने फील्ड में हैं और कितने ऑफिस में हैं ? आप मुझे यह बता दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी स्वयं जल संसाधन विभाग के मंत्री रहे हैं। विभाग में क्या स्थिति है, इसको वह स्वयं समझते हैं और दूसरी बात यह है कि आप जिन 4 अधिकारियों की बात की, निश्चित रूप से उनको वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये थे, लेकिन उसके बाद उनके वित्तीय अधिकार वापस ले लिये गये थे। मैं आपको उसकी तारीख भी बता दूंगा और आदेश की कॉपी भी दे दूंगा। जहां तक रिक्तियों का सवाल है, 400 इंजीनियर...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार क्या उनके पास वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार हो सकते हैं और यदि उनके पास ये अधिकार नहीं हो सकते हैं तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसने उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिये ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई आवश्यक नहीं है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक भर्ती का सवाल है तो इस सरकार के कार्यकाल में 100 असिसटेंट इंजीनियरों की भर्ती हो चुकी है और 400 सब इंजीनियरों की भर्ती अंतिम चरण में है। माननीय, यह आरक्षण का मसला है आप हमारी मदद कीजिए। यह छत्तीसगढ़ के नवजवानों के हितों का सवाल है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि कितने पद रिक्त हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- भैया, आप लोग 15 साल तक भर्ती ही नहीं किये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। हजारों पद खाली हैं। पूरा सिंचाई विभाग बंद हो जाएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सही है। लो बताओ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/XII, दिनांक 19 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2003

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/XII, दिनांक 19 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2003 पटल पर रखता हूं ।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2008/20-2 (3), दिनांक 20 सितम्बर, 2022

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2008/20-2 (3), दिनांक 20 सितम्बर, 2022 पटल पर रखता हूं ।

(3) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार:-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 08 फरवरी, 2018

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 28 जून, 2021

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20/2016/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-18/2016/18, दिनांक 30 मार्च, 2022 तथा

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-18/2016/18, दिनांक 29 अगस्त, 2022

पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ही नहीं, वरन् भारत के संसदीय इतिहास में छत्तीसगढ़ में अद्भूत घटना घटी है । माननीय राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के तहत साल में प्रथम सत्र के पहले दिन अभिभाषण देते हैं । हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के खिलाफ आपको विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, उसमें अभिभाषण की जो अंग्रेजी प्रति है और राज्यपाल महोदय को जो हिन्दी प्रति दी गई है, उसमें अंतर है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह घटना आपके कार्यकाल में घट रही है, आप सुनिए । जो हिन्दी प्रति दी गई है, उसे आप सादर अनुरोध करके मंगा सकते हैं । इसमें पूरे इंग्लिश की कंडिका में एक ही जगह आरक्षण के बारे में उल्लेख है, वह यह है-My government is committed for providing the benefits of reservation in government service and professional course to the members of schedule caste, scheduled tribe and other backward classes as per law. पूरी कंडिका में आरक्षण के बारे में इतनी ही बात कही गई है, जो विधान सभा के रिकार्ड में है । मैंने हिन्दी की कॉपी लगाई है, जो वितरित हुई है । जो आरक्षण का लाभ देने हेतु कटिबद्ध है, से आगे इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं शैक्षणिक संस्था में (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से विधान सभा में पारित किया गया है, जो अनुमति हेतु विचाराधीन है । ये यह वाक्यांश राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की वितरित कॉपी में है, उन्होंने जो मूल अभिभाषण पढ़ा है, वह उसमें नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय राज्यपाल महोदय को जो हिन्दी कॉपी दी गई है, उसमें भी यह बात नहीं है, जो इसमें लिखी है । हमने सूचना का अधिकार लगाया है, लेकिन आपको यह अधिकार है कि उनकी कॉपी को लाकर आप अवलोकन कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, आप बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने अपनी बात बात रख ली, आपकी बात आ गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, यह संवैधानिक संकट की स्थिति है और इसमें तत्काल चर्चा होनी चाहिए । ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक दृष्टि से माननीय राज्यपाल जी के साथ में Fraud किया गया है और उस Fraud में [XX][4] कि राज्यपाल जी ने जिस भाषण को स्वीकृत नहीं किया । देश के संसदीय इतिहास में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह सरकार क्या कर रही है ? कानून को तोड़ना, संविधान का अपमान करना, राज्यपाल जी का अपमान करना, राज्यपाल जी ने जिस अभिभाषण को स्वीकृति नहीं दी, उस अभिभाषण की प्रति यहां पर बांटी गई है। यह क्या हो रहा है ? इस प्रकार से हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारा विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार को तोड़ा गया है। हम तो चाहेंगे कि इससे महत्वपूर्ण विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए ...।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- इतना क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं भाई। इतना जोर से मत बोलो हम लोग डर जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा का सत्र राज्यपाल जी की अनुमति से आहुत होता है, अधिसूचना जारी होती है। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ते हैं। अगर उनके अभिभाषण में ही सरकार फ्राड कर दे, राज्यपाल जी के अंग्रेजी अभिभाषण में तीन लाईनें लिखी हुई हैं, परन्तु हिन्दी अभिभाषण में 15 लाईनें लिखी हुई हैं। अगर सरकार राज्यपाल जी के माध्यम से ऐसा फ्रॉड कार्य करेगी तो इससे बड़ी अवमानना की बात दूसरी नहीं हो सकती है। हम तो चाहेंगे कि जो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, उसके ऊपर तुरन्त चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा का इससे दूसरा बड़ा काम और नहीं हो सकता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने उसमें आरक्षण के सम्बन्ध में लिखा है। क्या ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा का इससे दूसरा बड़ा काम और दूसरा नहीं हो सकता है। माननीय राज्यपाल जी ने विधानसभा मे पढ़ा कुछ और है और हमको बांटा कुछ दूसरा गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आप लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हो ? आरक्षण का विरोध कर रहे हों क्या ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, बैठिये, बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आरक्षण का विरोध कर रहे हो ?

[XX][4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- जो अभिभाषण सदन के सदस्यों को बांटा गया है, यह सरकार ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। इनकी बात आने दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, उसमें आरक्षण के सम्बन्ध में ही लिखा गया है। क्या ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ? उसमें आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। आरक्षण का विरोध करते हो, शर्म करो।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- बिल में साइन होना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है। सदन की कार्यवाही रोककर विशेषाधिकार हनन पर चर्चा कराई जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आरक्षण का विरोध करोगे तो सड़क पर खड़ा होने नहीं मिलेगा, शर्म करो।

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां जिसको पढ़ा नहीं गया, उसको ये लोग छाप दिए हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये शिवरतन शर्मा जी, आरक्षण का विरोध करोगे तो भाटापारा के सड़क में खड़े होने के जगह नहीं मिलेगी तेरे को, ध्यान रखना।

उपाध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में अपनी-अपनी बात आ रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये क्या हो रहा है ? ये धमकी दे रहे हैं, मंत्री जी धमकी दे रहे हैं। यह शून्यकाल हमारा विषय है। (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आरक्षण का विरोध मत करो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं, आप लोग अपनी-अपनी बात रखिये।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल साहब ने यहां अपना अभिभाषण पढ़ा। उस अभिभाषण में जो शब्द थे, वे शब्द और हमें यहां जो प्रति दी गई है, वे शब्द अलग हैं। राज्यपाल जी ने 42वें नंबर की कण्डिका पढ़ा और हम सभी सदस्यों को जो प्रति वितरित किया गया, वह गलत है। यह भारत के प्रजातान्त्रिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि यहां पर कुछ पढ़ जा रहा है और हमको जो प्रति दी जा रही है, वह अलग है। हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आरक्षण के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपनी बात बताईये।

श्री सौरभ सिंह :- आप राज्यपाल जी से असत्य बोलवा रहे हैं।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- विपक्ष ने राज्यपाल जी का अपमान किया है। उन्हें अभिभाषण पढ़ने नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप लोग बैठिये। नेता जी बोल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि हम विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं। लोकसभा में देश के लिए कानून बनता है। एक मिनट, मुझे बोलने दीजिये। यह आरक्षण का विषय नहीं है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप आरक्षण का विरोध करोगे तो बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- इनकी बात आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विधानसभा है। गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। जब हमारा बजट सत्र प्रारंभ होता है तब माननीय राज्यपाल जी विधानसभा को वर्ष में एक बार इस सदन को संबोधित करते हैं। (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- उन लोग तो उनके अंग्रेजी बोलने का विरोध कर रहे थे । (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग तो विरोध ...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तो सुनने का मौका ही नहीं दिया। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- राज्यपाल का सम्मान तक नहीं किये...(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल बात है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो उनको पढ़ने के लिये दिया गया था, दूसरी कापी थी । यहां पर जो बंटवाया गया है, दूसरी कापी थी । मूल बात यह है । इस प्रकार का फ्राड पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी विधान सभा में आज तक नहीं हुआ है । हमने विशेषाधिकार की नोटिस दी है, पहले आप उस पर चर्चा करायें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन के अवमानना की नोटिस दी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक विषय नहीं है, जिम्मेदारी तय करने का विषय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह पूरी विधान सभा का अपमान है कि राज्यपाल जी पढ़े कुछ और हम डिस्ट्रीब्यूट कुछ और करें, इससे बड़ा फ्राड नहीं हो सकता, इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता । राज्यपाल जी अधिवेशन के लिये सत्र में बुलाते हैं ...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में कहावत हे...। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सुविधाओं का ख्याल रखा गया था.... । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दोषियों के ऊपर कार्यवाही होना चाहिये...। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इसकी जांच की घोषणा करिये ...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित ।

(12.11 से 12.48 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक गंभीर विषय उठाया है। जिससे पूरे सदन की अवमानना हुई है और राज्यपाल जी के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने जो भाषण पढ़ा है, वह अंग्रेजी में अलग है और हिन्दी में अलग है। यह एक गंभीर विषय है। शायद यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सदन में पढ़ा कुछ जाता है और वितरित कुछ किया जाता है। राज्यपाल जी सदन के सर्वोच्च हैं, उनके दस्तखत से ही अधिसूचना जारी होती है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में ही ऐसा फ्रॉड कर दिया जाए। यह शायद सदन के बाहर होता तो 420 का केस लग जाता। हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर संज्ञान लेकर अभी चर्चा करवाएं, इससे ज्यादा गंभीर और कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता है। हम आपसे इस बात का आग्रह करते हैं कि आप इस पर चर्चा करवाएं।

<u>छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग एवं सभा की अवमानना की सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग एवं सभा की अवमानना की सूचना दिनांक 13.03.2023 को मुझे प्राप्त हुई है, जो मेरे समक्ष विचाराधीन है। प्राप्त सूचना मैं स्पष्टीकरण हेतु शासन को भेजकर वस्तुस्थिति से यथासंभव अवगत कराऊंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि सत्र की समाप्ति के ..।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं भेज रहा हूं। हम बात कर लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप इसमें घोषणा कर दें कि सत्र की समाप्ति के पहले शासन का स्पष्टीकरण आ जाये। इससे ज्यादा गंभीर कोई दूसरा मामला नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- आ जायेगा, आ जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत विनम्र आग्रह है। आप हमसे ज्यादा सीनियर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाषण बदला जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ले ना, भई गे ना।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिये यह गंभीर मामला है। यह नजीर बन जायेगा, विपरित स्थिति बन जायेगी, यह असंवैधानिक स्थिति बन जायेगी। इसमें समय-सीमा तय कर दीजिये। सत्रावसान के पूर्व शासन की रिपोर्ट आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। आ जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से एक मसला उठाना चाहता हूं। मैं यहां अपनी भावना बहुत दु:ख के साथ व्यक्त कर रहा हूं कि दो दिन पहले बिलासपुर के सिवरेज के गड्ढे में एक लड़का आदित्य वैष्णव, जो 17 साल का था, वह गिरकर मर गया। सिवरेज की शुरूआत 2008 में 180 करोड़ की लागत से हुई थी। उसको 24 माह में बनना था। उसमें 400 करोड़ रूपये खर्च हो गये लेकिन आज तक वह सिवरेज का काम पूरा नहीं हुआ है। सिवरेज बिलासपुर के लिए अभिशाप हो गया है और इन 14 सालों में 12 लोग मरे हैं, 62 लोग घायल हुए हैं। इस बच्चे की मौत सिवरेज कंपनी की लापरवाही के कारण हुआ है क्योंकि 40 फीट के गड्ढे के किनारे न तो कोई वॉल बनाया गया, न कोई रेत की बोरी रखी गई, न कोई इंडीकेशन दिया गया। वह बच्चा बाहर से अपने मामा गांव में आया था। वहां पर वह जाना नहीं और उस गड्ढे में अनजाने में जाकर गिर गया। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि ऐसे तो हम लोग मामले उठाते रहते हैं, पर संज्ञान में कोई नहीं लेता। आप इसको संज्ञान में लीजिए। बिलासपुर की 4 लाख जनता को सिवरेज के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है कि उन सिवरेज के अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो और बिलासपुर के कलेक्टर और कमीशनर को बोला जाए कि पूरे शहर में घूमकर जहां-जहां भी सिवरेज के गड्ढे हैं, उनको उसकी सेफ्टी के परफेक्ट इंतजाम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह मांग करता हूँ कि उस मृतक परिवार को 10 लाख रूपये का मुआवजा देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिवरेज जी का जंजाल हो गया है। मैं इसी विधान सभा में बोला था कि वहां न तो सिवरेज से पानी जाएगा और न अमृत मिशन में पानी आएगा। सिर्फ वहां लोगों की मौत हो रही है। इस मामले में लोग बली चढ़ रहे हैं। इसलिए यहां माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। आप आज ही निर्देश जारी करिये कि जहां-जहां बिलासपुर के सिवरेज के गड्ढे हैं वह या तो पाटे जाएं या बड़े-बड़े गड्ढों के किनारे सुरक्षा के इंतजाम किये जाएं। वहां पर आपके कर्मचारियों की ड्यूटी लगे और वहां सिवरेज कंपनी के जो भी अधिकारी है उसको तत्काल सिविल लाईन थाने या तोरवा थाने में बुलाकर, अंदर करिये। वह लोग इतना चढ़े बैठे हैं। पता नहीं, वह सिवरेज वाले क्या समझते हैं ? छत्तीसगढ़, बिलासपुर को अपनी जागीरदारी समझ लिये हैं। वहां 180 करोड़ रूपये का काम 400 करोड़ रूपये का हो गया और उसके बाद भी उनकी आनन्द खत्म नहीं हो रही है। हमारे बच्चे मर रहे हैं और यहां आप लोग बैठे हैं कुछ नहीं देख रहे हैं। सिवरेज वालों से इतनी दया क्यों है ?आप कड़क कार्यवाही करिये। मैं आपसे मांग करता हूँ कि बिलासपुर के किसी भी व्यक्ति की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अध्यक्ष

महोदय, आप उसको बचाने के लिए निर्देश दीजिए ताकि शासन के लोग कार्यवाही करें। वहां पर यह बहुत ही गलत तरीके से काम चल रहा है और हमारे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां अभी तक सिवरेज नहीं बना है। कई वर्ष हो गये हैं और वहां सिवरेज बनना तो है, पर 17 वर्ष के बच्चे आदित्य वैष्णव जी, वह मुंगेली विधान सभा सेतगंगा के हैं और वहां सिवरेज की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मैं मांग करता हूँ कि वहां सिवरेज में मरने वालों को 20-20, 10-10 लाख रूपये मुआवजा राशि दी जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से बिलासपुर में सिवरेज आया है वर्ष 2008 से अभी तक 15 साल हो रहे हैं। बिलासपुर में इन 15 वर्षों में लगभग दर्जनों मौतें हो चुकी हैं और इस परियोजना में न कोई सफलता मिल रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक प्रश्न लगाया था, उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब भी आया था। वहां 235 किलोमीटर की लाईन बिछायी गई है। वहां मात्र एक किलोमीटर हाईड्रोलिक टेस्टिंग हुई है यानी की उसकी टेस्टिंग भी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि यह योजना फेल है। एक 17 वर्षीय बच्चा जो कि हमारे क्षेत्र के निवासी बिहारी वैष्णव जी हैं वहां बिहारी वैष्णव जी का एक युवक बच्चा 17 साल का आदित्य वैष्णव खेल रहा था और उसे खेलते-खेलते पता नहीं था कि वहां पर गड्ढा है वह अपने मामा के घर आया था। यह तोरवा क्षेत्र की घटना है वहां पर वह गड्ढे में गिर गया, उसके सिर में बड़ी-बड़ी रॉड घुस गईं और वह वही सिवरेज के गड्ढे में तत्काल खत्म हो गया। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारे मुंगेली के मूल निवासी थे तो मेरा यह मानना है कि आपके माध्यम से इसको मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उस परिवार को शांति प्रदान करने के लिए मुआवजा जरूर दिया जाये और इस पर दोषी लोगों पर अवश्य ही कार्यवाही की जाये। मैंने इसके लिए ध्यानाकर्षण भी लगाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। कटघोरा में एक नौजवान पुलिस के सब इंस्पेक्टर को थाने के अंदर जाकर, उसकी हत्या कर दी गई। आज 3 दिन के बाद भी उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। इससे बड़ा कोई गंभीर मामला नहीं हो सकता। जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है इस प्रदेश में उनकी हत्या हो रही है और थाने के अंदर हो रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। हम चाहते हैं कि यहां पर इसके ऊपर चर्चा हो कि

आखिर, अगर हमारे पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं होंगे, उनकी हत्या हो जाएगी, उनकी किलिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी हत्या नहीं है यह टारगेट किलिंग है। यह कहीं पर ठेका लेकर किलिंग की गई है, रिवेंट पुल किलिंग की गई है और पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से मारे जाएंगे तो प्रदेश की सुरक्षा कौन करेगा ? आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं, आपसे इस बात का आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हड़ताल में हैं। बजट आ गया है, उनकी नियमितिकरण की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसलिए वह हड़ताल में हैं। हमने उसमें ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाया है। यह बड़े महत्व का विषय है। सारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। यह उनके भविष्य का सवाल है। आपसे अनुरोध है कि उसको स्वीकृत कर चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- जी। बिलासपुर के सिवरेज की स्थिति के संबंध में अभी माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है। मैं भी अक्सर उधर से आता-जाता हूं। माननीय मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप इसको संज्ञान में लें और उसकी जांच करायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, आप उधर से आते-जाते हैं तो आप भी थोड़ा सावधानी से आया-जाया करिये, क्योंकि जिस लहजे में आदरणीय धर्मजीत भैया ने मामला उठाया है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी का निर्देश है, विभागीय अधिकारियों को हम उसको संज्ञान में लेने का और ठीक करने का निर्देश जारी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्र जांच करायें, तत्काल जांच करायें। चलिये, ध्यानाकर्षण सूचना।

समय :
12.56 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) रायपुर जिले के कंडरा/बसोड़ परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर से बांस उपलब्ध नहीं कराया जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- मेरी अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

शासन एवं प्रशासन की लापरवाही से बांस के सामानों के पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े रायपुर जिले के 3 हजार से अधिक कंडरा/बंसोड़ परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है व इन सब को अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। वन विभाग के द्वारा बही खाताधारी कंडरा/बंसोड़ों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर बांस उपलब्ध नही कराये जाने के कारण इन्हे अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी वन

विभाग द्वारा इन परिवारों को पिछले चार सालों से किफायती दर पर एवं निर्धारित मात्रा में बांस उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कंडरा समाज के लोगों को विभाग द्वारा बही दी गई है, जिसमे 1 साल में 1500 बांस देने का प्रावधान है, परन्तु पिछले 4 साल में इन्हें इनके हक का बांस भी नही दिया गया। बीते साल अनेक परिवारों को विभाग ने 50 बांस तक उपलब्ध नही कराया। कंडरा समाज के रायपुर में 3 हजार परिवार निवासरत हैं, लेकिन 750 को ही कंडरा/बंसोड़ बही दी गई है। शेष परिवार लगातार बही की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगो पर सरकार कोई कार्यवाही नही कर रही है। अनेक मुखियाओं के निधन के बाद उनके नाम पर दर्ज बही भी उनके वारिसानों के नाम पर स्थानांतरित नही की जा रही है। कंडरा परिवारों को उनके बही में उनके हक के प्रतिवर्ष 1500 बांस नही दिये जाने के कारण ठेकेदारों से उन्हें कई गुना अधिक दर पर खरीदना पड़ रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते इन परिवारों के सामने पुश्तैनी धंधा बंद करने की नौबत आ गई है और इन परिवारों के सामने भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे इन लोगो में शासन एवं प्रशासन के खिलाफ भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य नहीं है कि शासन एवं प्रशासन की लापरवाही से बांस के सामानों के पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े रायपुर जिले के 3 हजार से अधिक कंडरा/बंसोड़ परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है व इन सबको अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह भी सत्य नहीं है कि वन विभाग के द्वारा बही खाताधारी कंडरा/बंसोड़ों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर बांस उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इन्हें अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह भी सत्य नहीं है कि पिछले 04 सालों से कंडरा समाज के लोगों को उनके निर्धारित मात्रा की बांस वन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, बार-बार गुहार लगाने के बाद भी इन परिवारों को विभाग किफायती दर पर बांस उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

वास्तविकता यह है कि राज्य के निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत सभी बसोड़ एवं परम्परागत रूप से बांध का सामान बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 1500 बांस तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। पिछले 04 वर्षो (वर्ष 2019 से 2022 तक) में रायपुर जिले के पंजीकृत बंसोडों को डिपो में उपलब्धता के आधार पर बांस का प्रदाय किया गया है।

यह सत्य नहीं है कि रायपुर में कंडरा समाज के 3 हजार परिवार निवासरत है, लेकिन 750 को ही कंडरा/बंसोड़ बही दी गई है, शेष परिवार लगातार बही की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वास्तविकता यह है कि रायपुर जिले में वर्तमान में 656 बंसोड़/कंडरा बही पंजीकृत है तथा वर्तमान में रायपुर जिले में कुल 24 बंसोड़ परिवार की नई बंसोड़ बही बनाये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन कर नई बंसोड़ बही प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यह भी सत्य नहीं है कि अनेक मुखिया के निधन के बाद उनके नाम पर दर्ज बही भी उनके वारिसानों के नाम पर स्थानांतरित नहीं की जा रही है, बल्कि वास्तविकता यह है कि बंसोड़ बही खाता धारक मुखिया के निधन उपरांत उनके वारिसानों के नाम पर बंसोड़ बही नामांतरण किया जाता है। वर्तमान में कोई भी नामांतरण का प्रकरण रायपुर जिले में लंबित नहीं है।

यह भी सत्य नहीं है कि कंडरा परिवारों को उनके बही में उनके हक के प्रतिवर्ष 1500 बांस नहीं दिये जाने के कारण ठेकेदारों से उन्हें कई गुना अधिक दर पर बांस खरीदना पड़ रहा है तथा वन विभाग के लापरवाही के चलते इन परिवारों के सामने पुश्तैनी धंधा को बंद करने की नौबत आ गई है और इन परिवारों के सामने भूखे मरने की स्थिति है। वास्तविकता यह है कि शासन द्वारा विशेष प्रयास कर अन्य वनमण्डलों से उपलब्धतानुसार बांस प्राप्त कर बंसोड़ों को बांस प्रदायित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि रायपुर वनमंडल में बांस के जंगल नहीं होने से बांस का उत्पादन नहीं होता परंतु अन्य वनमण्डलों से उपलब्धता के अनुसार बांस प्राप्त कर रायपुर के बंसोड़ों को दिया जाता है।

अत: उपरोक्तानुसार बंसोड़/कंडरा परिवारों को राज्य की निस्तार नीति के तहत उपलब्धता के आधार पर बांस प्रदाय किया जा रहा है एवं इन लोगों में शासन एवं प्रशासन के प्रति काई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मंत्री जी मेरे सभी आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं। 24 लोगों की बही बनना है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। 24 लोगों की बही बनने की प्रक्रिया कितने साल से चल रही है? आप स्वीकार कर रहे हैं कि 656 बंसोड़ हैं। इनको 1500 बांस प्रतिवर्ष मिलना चाहिए। आप जरा बता दीजिये कि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में इन 656 परिवारों को कितने बांस उपलब्ध करवाये गये हैं? एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी बात करते हैं। ये छोटे-छोटे गरीब लोग हैं, जिनको बांस 15 रूपये में मिलना चाहिए, उनको 200 रूपये में बांस खरीदना पड़ रहा है। मंत्री जी, मैं तो आपको सक्षम मंत्री मानता हूं। आपके जवाब में यह नहीं आना चाहिए कि रायपुर जिले में बांस की उपलब्धता नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभी मानते हैं। वह आलिम आदमी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप तो पूरे प्रदेश से कहीं से भी बुलाकर और बांस दे सकते हैं। बांस इनके लिए कांग्रेस के अधिवेशन के लिए झण्डों के लिए बांस उपलब्ध हो सकता है, परंतु बंसोड़ को बांस उपलब्ध नहीं हो सकता। ये गरीब हैं। यह लोग टुकनी बनाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अधिवेशन में बांस का उपयोग होता है, उसमें इनको आपत्ति है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जरा मुझे यह बता दें कि पिछले 4 सालों में 656 बंसोड़ों को 1500 के हिसाब से कितना बांस उपलब्ध होना चाहिए और आपने कितना उपलब्ध करवाया है और भविष्य में इनको 1500 बांस उपलब्ध हो, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री दलेश्वर साहू :- अग्रवाल जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप पिछले कार्यकाल का तुलना इस कार्यकाल से भी करवा लीजिये। आपने कितने बंसोड़ों को बांस दिया है? आप पूरे राज्य को ले लीजिये। आप मेरे विधानसभा को ले लीजिये। आपने जो रेसियो में दिया है, वही रेसियो में हम भी दे रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, अग्रवाल जी को बंसोड़ को बांस नहीं मिलने से ज्यादा तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ इस बात की है कि कांग्रेस के अधिवेशन में झण्डा के लिए इतना ज्यादा बांस क्यों उपलब्ध करवाया गया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह जानकारी चाही है कि कितने दिनों से यह मामला लंबित है तो यह दिनांक 18.02.2023 को सत्यापन के लिए गया है और सत्यापन के तुरंत बाद जो 24 नये परिवार हैं, इनको दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सरकार 2019 से लेकर अब तक बांस उपलब्ध कराने में असफल रही है। मैं जानता था कि आप यह प्रश्न करेंगे, इसलिए मैं 2017 से जानकारी लेकर आया हूं। वर्ष 2017 से 2018, 2019, 2020, 2021 तक की जानकारी आप चाहते हैं, लेकिन मैं 2017 से पढ़कर सुना देता हूं कि 2017 में 180 औसतन बंसोड़ परिवार को प्रदायित बांस की संख्या, 2018 में 196 और 2019 में 238 और 2021 में 89 यानि लगातार आपके समय में भी आप जितना प्रदाय करते थे, उससे कहीं अधिक वर्तमान समय में हैं। आपके समय में भी उपलब्धता के आधार पर दिया जाता था और वर्तमान में भी उपलब्धता के आधार पर दिया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम क्या करते था, उसका मेरा प्रश्न नहीं है। ये गरीब हैं, ये यहां के कारीगर हैं। तीज त्यौहारों पर टुकनी चाहिए, पर्रा चाहिए, परंतु इन गरीबों को 1500 बांस उपलब्ध नहीं करवाकर ब्लैक मार्केट में 200 रूपये में बांस क्यों उपलब्ध हो जाता है? इन गरीबों को बांस उपलब्ध क्यों नहीं होता? मैंने इन गरीबों को यह पूछा है कि यह जो 28 लोग हैं, इनका आवेदन कब से पेंडिंग है? यह तो मेरा प्रश्न लगने के बाद में आपने सत्यापन करने के लिये भेजा है । यह कब से पेंडिंग है ? या गरीबों के लिये सरकार नहीं है ? गरीबों के लिये विभाग नहीं है और कितने लोगों का आपके पास में 24 नहीं, आप तो बता नहीं रहे हैं । लगभग 1000 लोगों के आवेदन रायपुर शहर के और पेंडिंग हैं जिनके ऊपर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है । अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ का पूछूंगा तो

पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संस्कृति बांस के सामानों के ऊपर आधारित है और यदि उनको बांस नहीं मिलेगा, बाजार में कोई बांस की कमी नहीं है । ठेकेदारों को मिल जाता है, बाकी लोगों को मिल जाता है लेकिन आखिर इन गरीबों को बांस उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है ? और आप कब उपलब्ध करवायेंगे ? आप मुझे यह बता दें कि आप इनकी बही कब तक बनाकर दे देंगे ? और अगर आपके पास में जानकारी हो तो पूरे प्रदेश में कितने बंसोड़ों की बही बनना बाकी है और क्या उनको बांस उपलब्ध हो रहा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रायपुर जिले का है । यदि पूरे प्रदेश का चाहिए तो प्रदेश का भी दे दिया जायेगा और जहां तक आप यदि पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा है कि उपलब्धता के आधार पर और यदि बांस उपलब्ध होगा तो उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है । अब रायपुर जिले में बांस यदि उपलब्ध नहीं है क्योंकि रायपुर जिले में जंगल नहीं है और रायपुर जिले में जंगल नहीं होने से बांस खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर, रायगढ़ यहां से लाया जाता है और पूरा प्रयास किया जाता है कि समय पर इनको उपलब्ध हो जाये । हम लोग अधिक से अधिक देने का प्रयास करते हैं और बात रही कि कितने लोगों के आवेदन पेंडिंग हैं तो 24 लोगों के आवेदन पेंडिंग है । यदि उनके नाम चाहिए तो मैं वह भी बता दूंगा और आप यह जो बोल रहे हैं कि 1000 के आवेदन पेंडिंग हैं यह असत्य है, ऐसा नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो चाहता हूं कि ये बेचारे गरीब हैं । इन गरीबों को 1500 बांस अधिकतम प्राप्त करने का अधिकार है । यह नियमों में है तो क्या उनको 1500 बांस उपलब्ध करवायेंगे ? और जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके परिवार के लोगों को बही ट्रांसफर होना चाहिए उसके लिये आप जो बता रहे हैं न कि ये 24 आवेदन तो ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रक्रिया चल रही है, ऐसे 1000 से ज्यादा आवेदन हैं जिनके ऊपर में डम्प पड़े हुए हैं । आपके अलग-अलग रेंजर के पास में, अलग-अलग एस.डी.ओ. के पास में और उसकी जानकारी आपके पास है ही नहीं, वे रिकमंड करके नहीं भेजते क्योंकि ये गरीब हैं । ये पैसा देकर अपना काम नहीं करवा सकते तो क्या आप इन बंसोड़ जो हमारे यहां के यह मान सकते हैं कि शिल्पकार हैं, कलाकार हैं जो हमारे तीज-त्यौहारों के लिये सामान उपलब्ध करवाते हैं तो क्या इनको आप पर्याप्त मात्रा में बांस उपलब्ध करवाने के लिये कम से कम आपको यह जवाब नहीं देना चाहिए कि रायपुर रेंज में बांस नहीं है। प्रदेश के जिस रेंज में बांस है क्या आप वहां से बुलाकर इनको उपलब्ध करवायेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी में उपलब्धता के आधार पर है लेकिन फिर भी यदि इस मामले में इनकी चिंता है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक दें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण भले ही रायपुर जिले का है लेकिन यह समस्या पूरे प्रदेश की है । पूरे प्रदेश में बंसोड़ को जितना बांस मिलना चाहिए उतना बांस नहीं दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया कि रायपुर वनमंडल में बांस के जंगल नहीं होने से बांस का उत्पादन नहीं होता है । जहां बांस के जंगल हैं, मेरा जिला बलौदाबजार-भाटापारा है वहां भी समय पर लोगों को बांस नहीं मिलता है । आपने अधिकतम की बात की है कि अधिकतम 1500 बांस प्रदान किये जायेंगे । मैं आपसे केवल पाइंटेड प्रश्न कर रहा हूं कि अधिकतम की सीमा निर्धारित है तो क्या इसमें कुछ न्यूनतम की सीमा भी निर्धारित करेंगे ? आपने अभी जो वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक के आंकड़े बताये उसमें न्यूनतम में 20 परसेंट भी नहीं आ रहा है । कम से कम न्यूनतम हम 1500 है तो 50 परसेंट देंगे ऐसा कुछ निर्धारण करें । दूसरा जो है बसोड़ बही बनाने के नियम क्या हैं आप इसकी जानकारी दे दें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी में लिखा है कि 1500 अधिकतम । न्यूनतम इसलिए फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कारण यह है कि यदि उपलब्ध हो जाये तो जितना ज्यादा दे सकें उतना हमको दिया जाना चाहिए । अब नया बसोड़ बही बनाने की बात रही ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, पॉलिसी में लिखा है । आपने अधिकतम लिख दिया, आप कुछ तो न्यूनतम करिए । बसोड़ तो उसी पर डिपेंड करता है, उनका जीविकोपार्जन तो उसी से होता है तो आपको कुछ न कुछ न्यूनतम दर निर्धारण करना चाहिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम इसलिए निर्धारित नहीं हो सकता क्योंकि यदि उपलब्धता हो गयी । वन विभाग में बांस की कटाई, टिम्बर की कटाई के लिये कार्ययोजना बनती है । कार्ययोजना मंजूरी के बाद यदि नये जंगल खुलेंगे तो अधिक बांस आ जायेगा तो उनका जो हक 1500 का है तो आप क्यों मारना चाहते हैं ? आपको उसे न्यूनतम करने की जरूरत क्यों है ? इसलिए यदि मान लीजिए जितना अधिकतम हम दे सकें, उसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अधिकतम देंगे। दूसरा यह कि आवेदन मिलने के बाद नगर-पंचायत, नगर-पालिका या ग्राम पंचायत से उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन इस बात का होता है कि जो संबंधित परिवार है, वह बांस के जरिए अलग-अलग जो टोकरी वगैरह बनाने या बांस से जितनी भी चीजें बनती हैं, उसको बनाने का काम करता है क्या? सत्यापन के बाद फिर उसमें उसको देने की कार्यवाही होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी बांस की मांग है, उसकी तुलना में कितना उत्पादन होता है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 30 लाख व्यापारिक बांस का औसत रूप से प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। उपलब्ध बांसों में से ही बांस निस्तार डिपो से निस्तार दर पर तथा बांस उपभोक्ता डिपो से उपभोक्ता दर पर ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाता है।

कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत बांस ही बंसोड़ों के उपयोग योग्य होता है, क्योंकि बंसोड़ों को टोकरी आदि बनाने के लिए हरे तथा ताजे बांस की आवश्यकता होती है। राज्य में प्रतिवर्ष औसत रूप से 3527 पंजीकृत बंसोड़ों को प्रति परिवार 1500 नग बांस के हिसाब से 52 लाख 90 हजार 500 नग बांस की आवश्यकता है, परंतु राज्य में प्रतिवर्ष उत्पादित बांस में से बंसोड़ों को उपलब्ध कराये जाने योग्य ताजा एवं लंबा बांस की संख्या 15 लाख ही है, जो उन्हें प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है। जहां तक रायपुर जिले का प्रश्न है, रायपुर जिले में बांस का उत्पादन नहीं होता, फिर भी बंसोड़ों को अन्य वन मंडलों से प्राप्त कर आपूर्ति की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन आप अब अपने ध्यानाकर्षण को देख लें। आपका पूरा ध्यानाकर्षण रायपुर जिले के ऊपर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कितने बांस बंसोड़ों को उपलब्ध करवाते हैं। आपके 30 लाख बांस का उत्पादन होता है। 15 लाख पर उनका अधिकार है। 15 लाख में से बंसोड़ों को कितना उपलब्ध करवाते हैं, आप यह बता दें। मेरी जानकारी में 5 लाख बांस भी बंसोड़ों को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी में ही लिखा है उपलब्धता के आधार पर। अब एक-एक की अलग-अलग संख्या पूछेंगे। आपने रायपुर जिले का पूछा तो मैंने पूरा बता दिया। बाकी आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आपने बंसोड़ों के बही की जो कुल संख्या बताई है, वह 3500 कुछ बताई है । अगर पूरे प्रदेश में 3500 बंसोड़ हैं और 1500 बांस देना है तो उनकी डिमांड कितनी होगी?

श्री मोहम्मद अकबर :- आप केल्कुलेटर घूमा लीजिए न। मतलब अब यह संख्या भी हिसाब करके आपको थोड़े न बताउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उपलब्धता के आधार पर बांस उपलब्ध कराया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कितने बांस उपलब्ध हैं? और बंसोड़ों के लिए कितने करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख 9 हजार 993 बांस बंसोड़ों को दिये गये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और प्रश्न है। अब छत्तीसगढ़ में रायपुर का तो है और मुंगेली में भी बंसोड़ हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुंगेली का अगला ध्यानाकर्षण लाइए न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने कहा कि पंजीकृत बंसोड़ को देंगे। जो पंजीकृत नहीं हैं, सही में उनको आवश्यकता है और वही उनकी जीविका का साधन है। ऐसे लोगों को पंजीकृत कराकर क्या उन्हें भी उपलब्ध करायेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी आवेदन करेगा, कोई रोक नहीं है, लेकिन वह उस प्रकार का काम करना चाहिए। यदि बंसोड़ उस प्रकार का काम करेगा तो पंजीकृत करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा सा प्रश्न करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- एकदम छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीतियां कोई शाश्वत नहीं होतीं। संवैधानिक नहीं है। हम परिस्थिति के हिसाब से नीतियां रोज बनाते हैं, रोज बदलते हैं । छत्तीसगढ़ में नमक पैदा नहीं होता। हम गुजरात से नमक बनाते हैं आयोडाइज्ड नमक को। यह 35 सौ 5 हजार मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है, जितनी भी संख्या हम छत्तीसगढ़ या रायपुर जिले में होंगे, इसमें से अधिकांश लोग बी.पी.एल. के लोग हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में, मौखिक उत्तर में 3 बार लिखित उत्तर में आया कि उपलब्धता के आधार पर।, उपलब्धता के आधार पर। जब हम नमक 2 किलो देते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं, कहीं से भी मंगवाकर तो क्या इस नीति को बदलकर इतनी संवेदनशीलता दिखायेंगे? आप हमारी तुलना कर लें, हम यहां आ गये, चलिए हमने गलती की, यह हम मान लेते हैं, लेकिन यह गरीबों के लिए शासन 1500 बांस सुनिश्चित करने के लिए कोई नई नीति बनायेगा क्या?

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना बांस है, कितने बांस की मांग है । वह समस्या तो हमेशा रही है। लेकिन जितनी कम मात्रा में आप बांस दे रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि लोग पर्रा, सूपा, टोकरी, टोकरा बनाना बंद कर देंगे । छत्तीसगढ़ में बगैर इसके शादियां नहीं होतीं । आपकी सरकार संस्कृति की बहुत बात करती है । जब आप चीता, भालू और शेर बाहर से मंगा सकते हैं । मैं पढ़ रहा हूं चीता भी आएगा, भालू भी आएगा, शेर भी आएगा, लोमड़ी भी आएगी, लकड़बग्घा भी आएगा । तो कृपा करके मध्यप्रदेश के बालाघाट से बांस मंगवा लीजिए ना । सरकार का 1 लाख, 21 हजार करोड़ रूपया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, चीता बाहर से आ रहा है उसको विलोपित करा दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं मंगवा रहे हैं । पूरा देश सुनेगा तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह विदेशी चीता है, यहां तो लोकल चीता आने वाला है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जहां तक भालू का सवाल है तो अपने यहां ही भालू इतने ज्यादा है कि बाहर से लाने का सवाल ही नहीं है । इनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्क्त होती है मंत्री महोदय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुनिया ना महाराज जी । अगर कोई भालू मांगे तो आप मुफ्त में दो, घर पहुंच सेवा दो । मेरा आपसे यह कहना है कि दो साल पहले मैंने विधान सभा में दो-तीन बातें बोला था । आपके ही विधान सभा के मड़मड़ा गांव में 70 एकड़ का बांस का एक बहुत बड़ा बागीचा है । वह 25, 30, 40 साल पहले का है । वहां गांव वाले लाखों रूपए का बांस बेचते हैं, हरा बांस, कटंग बांस, बड़ा-बड़ा बांस । आपके प्लान में उसको भी तो जोड़िए कि हर गांव में जो वेस्ट लैंड पड़ा है वहां बांस का उत्पादन बढ़वा दीजिए । लोकल लेवल पर वह बांस सप्लाई हो जाएगा । अध्यक्ष जी, बंसोड़ों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा । मैं सिर्फ यह बोलना चाहता हूं कि बंसोड़ों की ज़िंदगी बांस के बर्तन बनाने पर निर्भर है । आप कृपा करके बालाघाट से बात कर लीजिए, अपने अफसर को भेज दीजिए । बालाघाट में बहुत बांस है । आप जितना बांस बोलेंगे उतना बांस छत्तीसगढ़ पहुंचेगा । रायपुर में बांस का उत्पादन नहीं होता है तब भी यहां बांस का भंडार लग सकता है । तो आप कृपा करके सदन के माध्यम से बंसोड़ों को आश्वस्त करिये कि अगर यहां बांस उपलब्ध नहीं है तो यह सरकार 1500 या 1000 के मान से सभी बंसोड़ों को बांस उपलब्ध कराएंगे । अब उसमें कौन कहेगा कि मैं बांस का काम करूंगा, कोई फर्जी तो बोलेगा नहीं । जो बांस का काम करता है वही आएगा । जब शेर, भालू आ सकता है तो बांस भी आ सकता है । यह मेरी मान्यता है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि पात्रता के आधार पर उनको अधिक से अधिक बांस उपलब्ध हो सके ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे दो मालिक ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गरीबों और निम्न वर्ग के लोग हैं । उनके लिए हमने ध्यानाकर्षण सूचना लगाई और आपने सदाशयता से इसको स्वीकार किया है क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का मामला है । माननीय मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए कि जो कंडोर हैं और जो बंसोड़ हैं उनको पर्याप्त मात्रा में बांस उपलब्ध करवाया जाएगा । माननीय मंत्री जी, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । आपको झंडा लगाने के लिए बांस की जरूरत पड़ी, बांस कहां से आया ? बंसोड़ों को उपलब्ध करवाया जा सकता है । मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपको आश्वासन देना चाहिए कि वन विभाग तत्परता से बंसोड़ों को बांस उपलब्ध करवाएगा, जिससे वे जीवन यापन कर सकें । अध्यक्ष जी, यह समाज के सबसे कमजोर तबके का मामला है इसलिए आप निर्देश दें कि उनको बांस उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे जीवन यापन कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, हम सब को पता है कि आपके घर का और उनके घर का दरवाजा मिला हुआ है । आप मिलकर भी सलाह-मशविरा कर सकते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो दुनो के घर तो मिले हे गा । दरवाजा एके जगह हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मड़वा के लिए बांस ब्लैक में मिल रहा है अध्यक्ष महोदय । सूपा, पर्रा सब ब्लैक में मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, गृहमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारगण के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें ।

सदन को सूचना

(1) स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 मार्च से 16 मार्च, 2023 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है । कृपया प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लें ।

(2) मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 को भी आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय :- सभा की सहमति से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा मंगलवार 14 मार्च, 2023 को भी होगी ।

श्री नारायण चंदेल :- धन्यवाद् ।

भोजन अवकाश की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 13 मार्च, 2023 से दिनांक 23 मार्च, 2023 तक भोजन अवकाश को स्थगित करने की सहमति सभा द्वारा दी गई थी ।

आज सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को प्रजापिता ब्रम्ह कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर विधान सभा मार्ग सड्डू रायपुर द्वारा दोपहर 1.00 बजे से ब्रम्हा भोज आयोजित किया गया है । अत: सभा की कार्यवाही दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाएगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं समझता हूं, सभा सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- समस्त माननीय सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर विधान सभा मार्ग सड्डू रायपुर द्वारा आज सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को दोपहर ब्रम्हभोज आयोजित है। आप समस्त सदस्य माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सुविधानुसार सम्मिलित होने का कष्ट करें। सत्यनारायण शर्मा जी।

(2) रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे का निर्माण गाईड लाईन के अनुरूप नहीं की जाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण), श्री कुलदीप जुनेजा, श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय , मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -:

छ.ग. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.01.2021 अनुसार किसी की निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। जबकि तेलीबांधा की निजी भूमि खसरा नंबर 227/1 एवं 227/8 के 3500 वर्ग फुट भूमि पर बिना अधिग्रहण किये नाला का निर्माण किया गया है। यह हल्का पटवारी के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पंचनामा दिनांक 07.01.2021 और अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के न्यायालय में भूमि त्यजन प्रकरण 202206111000204/अ-25 वर्ष 2021-22 में स्पष्ट है। दो और भूमिस्वामियों की भूमि एक्सप्रेस-वे में आई है, जिसका दो गुना एफ.ए.आर. और दो स्थान पर एन्ट्री देकर भूमि का त्यजन कराया गया है। लगभग 14 अन्य लोगों की भूमि का त्यजन अथवा दान भी अमलीडीह में एक्सप्रेस-वे के सर्विस रोड के लिए कराया गया है। विभाग एफ.ए.आर. देने में पक्षपात कर रहा है।

तेलीबांधा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस-वे **IRCSP 84-2014** की गाइडलाइन के तहत् बनाया गया है, जबकि **IRCSP 84-2014** की गाइडलाइन एक्सप्रेस-वे के लिए नहीं बल्कि हाईवे के लिए है, जबकि हाईवे की **IRCSP 84-2014** की गाईड लाइन पी.पी.पी. मोड से संबंधित है। हाइवे की गाईड लाइन पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

तेलीबांधा की निजी भूमि खसरा नंबर 227/1 एवं 227/8 के 3500 वर्ग फुट से लगा हुआ नाला जिस स्थान से बहते हुए एक्सप्रेस-वे के आरपार जा रहा था, उस स्थान पर वर्तमान एक्सप्रेस-वे में भी पाइप डालकर नाला पार करने की व्यवस्था की गई थी। बाद में उस पाइप को तोड़कर उक्त भूमि खसरा नंबर के सामने पुल को शिफ्ट किया गया है और प्राकृतिक नाले को इस नये पुल की तरफ डायव्हर्ट किया गया। डायव्हर्ट करने के लिए खसरा नंबर 227/1 एवं 227/8 की 3500 वर्ग फुट भूमि में खुदाई कर नाला का स्थायी निर्माण किया गया है। इससे भूमिस्वामी की निजी भूमि से होकर पानी पुल से उस

पार जा रहा है। भूमिस्वामी की 3500 वर्गफुट भूमि में स्थायी नाला बनाया गया है, इससे उनकी भूमि के सामने का कीमती हिस्सा अनुपयोगी हो गया। इस भूमि का त्यजन भी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के न्यायालय में कराया गया है, किन्तु अन्य भूमिस्वामियों की तरह इन्हें न तो मुआवजा दिया गया, न ही रास्ता दिया गया और न ही दोगुना एफ.ए.आर. दिया गया है।

सर्विस रोड में बेरीकेटिंग कर आम जनता का तथा सर्विस रोड किनारे स्थित निजी भूमिस्वामियों की सर्विस रोड पर एंट्री को बंद कर दिया गया है। विभाग के द्वारा तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में किये गये इस प्रकार के कार्यों से सर्विस रोड से लगे भूमिस्वामियों में काफी रोष और असंतोष व्याप्त है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे रेल्वे की छोटी लाइन की भूमि पर बनाया गया है। यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में किसी की निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। तेलीबांधा की निजी भूमि खसरा नंबर 227/1 एवं 227/8 के 3500 वर्ग फूट भूमि पर नाला का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त खसरा नं. के भूमि का त्यजन एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

विभाग द्वारा किसी की भी निजी भूमि का त्यजन एक्सप्रेस-वे निर्माण में नहीं कराया गया है, अत: एफ.आर.ए. देने की कार्यवाही विभाग से संबंधित नहीं है।

यह सत्य है कि अमलीडीह में सर्विस रोड निर्माण हेतु 11 निजी भूमिस्वामियों की स्वयं की इच्छा से जनहित में भूमि का त्यजन करने की कार्यवाही उनके आवेदन के आधार पर प्रारंभ हुई थी, परन्तु निजी भूमिस्वामियों द्वारा अमलीडीह सर्विस रोड में प्रवेश की मांग करने पर सर्विस मार्ग निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है। यह सत्य नहीं है कि तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे के संबंध में गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है एवं पक्षपात पूर्ण तरीके से किसी निजी भूमिस्वामी को एन्ट्री एवं दो गुना एफ.ए.आर. दिया जा रहा है।

यह सत्य है कि तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे छोटी रेल लाइन की भूमि पर IRC:SP:99:2013 के तहत नहीं, अपितु IRC:SP:84:2014 के गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। उक्त मार्ग छ.ग. राजपत्र प्राधिकार में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 471/दिनांक 30.10.2017 को एक्सप्रेस-वे (अभिव्यक्त राजमार्ग) घोषित किया गया है। यह सत्य नहीं है कि विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा है।

यह सत्य है कि तेलीबांधा में प्राकृतिक नाला के बहाव अनुरूप तकनीकी मापदण्डानुसार रेलवे की भूमि पर पुलिया का निर्माण किया गया है, नाला के प्राकृतिक बहाव को परिवर्तित नहीं किया गया है, न ही खसरा नं. 227/1 एवं 227/8 की भूमि पर नाला का स्थायी निर्माण किया गया है। उक्त नाला निर्माण के लिए विभाग द्वारा किसी प्रकार के त्यजन की कार्यवाही नहीं की गई है, परंतु राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक भूमिस्वामी ने स्वयं अपनी तरफ से आवेदन राजस्व विभाग को

प्रस्तुत किया है। अत: भू-स्वामी को मुआवजा, रास्ता एवं दो गुना एफ.ए.आर. देने संबंधी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

एक्सप्रेस-वे का निर्माण छोटी रेलवे लाइन की भूमि में किया गया है, पूर्व में भी रेलवे भूमि के किनारे स्थित निजी भू-स्वामियों का आवागमन/प्रवेश निषिद्ध था। एक्सप्रेस-वे निर्माण के गाइडलाइन अनुसार अनाधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए मार्ग की सीमा के दोनों ओर नियमानुसार बेरीकेटिंग कार्य किया जा रहा है। अत: यह कहना कि बेरीकेटिंग कर आम जनता का आना जाना बंद कर दिया गया है, उचित नहीं है।

तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे का निर्माण नियमानुसार किया गया है, अत: सर्विस रोड के भू-स्वामियों में आक्रोश और असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि नाला का निर्माण नहीं हुआ है। मैं वर्ष 2007, वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के गूगल के मैप से इसको प्रमाणित कर सकता हूं कि नाला का निर्माण हुआ है। मैं आपकी अनुमति से इसको सदन के पटल पर रख देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, नाले का निर्माण किया गया है। आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की है। मंत्री जी, मेरे पास इसका प्रमाण है। आप इसको दिखवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में बहुत सी गलत जानकारियां दी गई हैं। आप विधान सभा की जांच समिति बना दें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यह डॉक्यूमेंट है जिसमें इनके काम करने वाले ठेकेदार ने लिखकर दिया है कि हम इसका टेम्परेरी निर्माण कर रहे हैं और बाद में उसको परमानेंट नाला बना दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि उक्त मार्ग छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 471/दिनांक 30.10.2017 को एक्सप्रेस-वे (अभिव्यक्त राजमार्ग) घोषित किया गया है। यह वर्ष 2014 की आपकी जो गाइडलाइन है, यह नेशनल हाईवे के लिए है और पी.पी.पी. मोड के लिए है। आपने पी.पी.पी. मोड वाली सड़क नहीं बनाई और आप हाईवे की गाइडलाइन का रिफ्रेन्स दे रहे हैं। मेरा सीधा-सीधा सवाल यह है कि इनको कनेक्टिंग रोड, स्लिप रोड, सर्विस रोड पर नागरिकों को बराबर रास्ता देना चाहिए। अमलीडीह में 14 लोगों की भूमि का दान कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, वहां लोगों का आना-जाना बंद है। वहां की आबादी करीब 70,000-80,000 है। वहां पर छोटी-छोटी बस्तियां हैं, 15-16 कालोनियां हैं, वहां के लोगों को आने-जाने के लिए मार्ग देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक सेकण्ड।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची के पद क्रम-4 के उप पद-2 तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- जी, आप जारी रखिये।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सप्रेस वे के अंडरब्रीज के नीचे हर जगह सर्विस रोड़ बनी है । केवल लाविस्टा से लेकर उसके नजदीक के जो अंडर ब्रीज में सर्विस रोड़ नहीं बनी थी। भूमि अधिग्रहण करने की आपकी स्थिति नहीं थी इसलिए हम लोगों ने बात करके जमीन दान करवाया, अधिग्रहण करवाया । काम शुरू हो गया था, उसके बाद काम बंद करा दिया गया । मैं सर्विस रोड़ के बारे में कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपके विधान सभा क्षेत्र का मामला है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जी हां, मेरी विधान सभा क्षेत्र का है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.सी.ए.आर. की गाईडलाईन 2013 के अनुसार सर्विस रोड़ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कनेक्टिंग रोड़ है । आप इस पर इंट्री बंद नहीं कर सकते, आपने इसको बेरीकेटेड कर दिया इसलिए आपका कहना गलत है कि हम 2014 की गाईड लाईन के अनुसार बना रहे हैं । ऐसा आप बना ही नहीं सकते, वह नियम नेशनल हाईवे और पी.पी.पी. मोड के लिए है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हैं महाराज ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण की जांच विधान सभा की समिति से कराएंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई और समिति नहीं चलेगी ? विधान सभा के अलावा और कोई समिति चलेगी ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समिति से जांच करवा दीजिए, पूरा गलत हुआ है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समिति से जांच करवा दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समिति का काफी महत्व है । अभी सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि चूंकि रायपुर शहर का मामला है तो आपको

स्वयं संज्ञान में लेकर इसमें विधान सभा की समिति बना दें, जिससे कि रायपुर शहर के लोगों को इसका फायदा मिल सके ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जानकारियां गलत है। मैं आपकी अनुमति से सारे नक्शे, गुगल के मैप पटल पर रख देता हूं, जिसमें पूरा मामला साफ हो जाएगा । आप विधान सभा की समिति से जांच करवा लें, सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी । माननीय मंत्री जी, अधिकारीगण आपको गुमराह कर रहे हैं। आप स्थिति को देखिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी है । विधान सभा से किसी भी प्रकार की समिति बनाकर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य का यह कहना कि सर्विस रोड़ हो, उससे एन्ट्री हो । अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस-वे बनाया ही गया है कि लंबी दूरी चलनी है, उसमें बीच-बीच में एन्ट्री नहीं दी जा सकती । हम लोगों ने छोटी रेल लाईन के ऊपर एक्सप्रेस-वे बनाया है, रेल लाईन में जहां-जहां प्रचलित एन्ट्री थी, वहां हमने एन्ट्री दी है, पर हर व्यक्ति अपनी जमीन में एन्ट्री मांगे, कोई कॉलोनी बनाने के लिए एन्ट्री मांगेगे, कोई और कुछ करने के लिए एन्ट्री मांगेगे तो हम एक्सप्रेस-वे में एन्ट्री नहीं दे सकते क्योंकि एक्सीडेंट का सबसे बड़ा खतरा रहेगा । मैंने पूरी तरह से उत्तर दिया है, सभी उत्तर सही है, किसी भी प्रकार की समिति से जांच की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य पूरे कागज़ात लेकर बैठे हुए हैं, वे पटल पर रखना चाहते हैं तो उसकी जांच तो कराएंगे कि वह सही है या गलत है ? आप पटल पर रख दीजिए । जांच तो किसी न किसी माध्यम से कराना पड़ेगा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जी अध्यक्ष महोदय, सारे डाक्युमेंट्स जिसका जिक्र मैंने किया है, सभी को पटल पर रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप माननीय विधायक जी के डाक्यूमेंट्स की जांच करा लें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसी के आधार पर हम लोगों ने जांच की है, उसी के आधार पर उत्तर बनाया गया है । सर्विस रोड़ में जमीन वाले अलग से एन्ट्री मांग रहे हैं । उनको कैसे एन्ट्री दी जाएगी ? अगर बीच-बीच में इंट्री देंगे तो एक्सप्रेस-वे का मतलब ही क्या है ? फिर वह एक्सप्रेस-वे नहीं होकर मालवीय रोड़ बन जाएगी । अगर सभी के सभी उसमें से एन्ट्री लेंगे तो एक्सप्रेस वे बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नाले का निर्माण किया गया तो इन्होंने नाले को डायवर्ट कर दिया गया । नाले को डायवर्ट करके निजी भूमि का उपयोग कर लिया और जनता किधर से जाएगी । इसलिए सर्विस रोड़ बनती है ।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 सौ-4 हजार फीट प्राईवेट जमीन है, उसको ये लोग उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन गलत जानकारी दी जा रही है कि यह जमीन प्राईवेट नहीं है और मुआवजा नहीं दिया गया है । अगर एक्सप्रेस वे बना है तो सर्विस रोड़ बननी ही चाहिए । जब सर्विस रोड़ का काम आधा चालू हुआ, उसके बाद सर्विस रोड़ को बंद करा दिया गया । 60-70 हजार आम जनता को उस रोड़ से गुजरना है, बस्ती वालों को गुजरना है । ऐसे कई बस्तियों के घर हैं, जिनको निकलने का रास्ता नहीं दिया गया है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते । आप चलकर देखिए । अध्यक्ष जी, आप विधान सभा की समिति बनवाईए, आप साथ में चलिए और देखिए । ऐसे कई गरीबों के घर हैं, जिनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको लोक निर्माण विभाग ने किया है या किसी और विभाग ने किया है ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- यह जो भी सड़क निर्माण है, इसको लोक निर्माण विभाग ने किया है या किसने किया है, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिसने भी किया है, वह गलत किया है । अगर हम जनता की सुविधा के लिए बना रहे हैं और जनता को सुविधा नहीं देंगे । अपनी मनमर्जी से कोई अधिकारी आते हैं, पहले कुछ अलग बात करके जाते हैं, कोई नये अधिकारी आते हैं, वे कुछ अलग बयान दे देते हैं । अधिकारीगण ही एक दूसरे के अलग-अलग बयान में फंसते हैं । गरीब जनता की ऐसी कई सारी झोपड़ियां हैं, जिनका रास्ता बंद कर दिया गया है । वे अपने घर से नहीं निकल सकते । सर्विस रोड़ की बात है तो आपको सर्विस रोड़ सब जगह देना ही पड़ता है। दो-चार बड़े लोगों के घर हैं, उनकी एन्ट्री की बात करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी तो सर्विस रोड से निकलना है। आप उनका रास्ता क्यों बंद करेंगे ? आपको तो सर्विस रोड देना ही चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि 4-5 लोगों को परमिशन भी दिया गया है, तो उनको किस आधार पर परमिशन दिया गया है, माननीय मंत्री जी यह भी बतायें ?

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे जी, आप भी पूछ लीजिये। मंत्री जी एक साथ जवाब देंगे।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचम विधानसभा के 17वें सत्र तक जितने भी ध्यानाकर्षण आये, उन ध्यान आकर्षणों में यह एक ऐसा ध्यानाकर्षण है, जो तथ्यों सहित है। इस ध्यानाकर्षण में भाषण नहीं है। इसमें सारे तथ्य हैं, दस्तावेज लगे हुए हैं, लिखित रूप से सारी चीजें बताई गई हैं। चाहे नक्शा हो, चाहे एस.डी.एम. का आदेश हो, चाहे तहसीलदार का आदेश हो..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यहां तथ्यों को रखने के लिए बोल दिया हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिलकुल सही है कि हम एक्सप्रेस-वे में एन्ट्री नहीं दे सकते, हमने मान लिया। तो फिर हमको क्या अधिकार है कि आप निजी भूमि का

अधिग्रहण करें। हम क्यों निजी भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं ? वहां जाकर अधिकारियों ने खेल क्यों खेला ? किसी गरीब की जमीन जाकर क्यों ली ?

अध्यक्ष महोदय :- अरे (आश्चर्य प्रकट करते हुए) आप तो गरम हो रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये दस्तावेज सत्य है। इसमें लिखा हुआ है, एस.डी.एम. बोल रहा है कि हां, जमीन दान दिया गया है, इसका नक्शा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको नक्शा दिखा दूंगा कि नाला कहां से जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आप नक्शा मत दिखाईये।

श्री शैलेश पाण्डे:- और अब नाला कहां से जा रहा है ? नाला का बदलाव नक्शे में दिखाया जा रहा है, तथ्य दिखाये जा रहे हैं, उसमें एस.डी.एम. का आदेश है। चाहे कोई जमीन दान में देगा तो कोई भी आदमी अपनी जमीन मुफ्त में क्यों दान में देगा ? वह इसीलिए दान में दे रहा है कि सरकार उसकी मदद करेगी, अधिकारी उसकी मदद करें। अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को फंसाया, उनसे जमीन दान करवाई गई, उसको फंसाने के बाद, दान करवाने के बाद वहां एक्सप्रेस हाइवे बना दिया गया। उसके बाद अधिकारी स्थानान्तरित हो गये, लेकिन उन लोगों को रास्ता नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को रास्ता नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि जब माननीय सत्यनारायण शर्मा जी तथ्यों के साथ कोई बात रख रहे हैं तो इस पर अवश्य जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सरकार निर्णय करें और सरकार का जो भी निर्णय होगा, वह मान्य होगा। अगर आज यह मामला सदन में आया है, तो यहां माननीय मंत्री जी को सदन में घोषणा करनी चाहिए कि वह सदन से इस विषय की जांच करवायेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा भी उसमें आता है। मेरा आपसे निवेदन है कि विधानसभा की समिति बनाकर इसकी जांच करा दी जाये तो भी मामला है, वह सामने आ जायेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस रोड इसीलिए बनाई जाती है कि लोगों को सर्विस रोड के माध्यम से एन्ट्री मिले और आगे जाकर एक्सप्रेस-वे में आ जायें। लोगों की सुविधा के लिए सड़कें बनती हैं। लोगों को चलने के लिए रास्ता मिले, इसलिए सड़कें बनती हैं और पता नहीं यहां किस ढंग से काम हो रहा है। यह नेशनल हाईवे, पी.पी.पी. मोड में सड़क नहीं बनी है। यह शासन के पैसे से सड़क बनी है। आप 2014 का रिफरेंस दे रहे हैं। आप हाईवे की गाईड लाईन बता रहे हैं। जबकि सड़क 2013 की एक्सप्रेस-वे सड़क है। तो माननीय मंत्री जी, इसकी जांच कराईये। अध्यक्ष जी, मैं इसकी मांग करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर(नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इस समस्या का निराकरण है। वह निराकरण यह है कि 14 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे है और यह 14 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे 10 लाख की आबादी को क्रॉस करता है। जहां पर आबादी है, वहां नेशनल हाईवे में भी सर्विस रोड बनाई जाती है। तो आप उसमें सर्विस रोड बना दें। सर्विस रोड बन जायेगी तो पूरी समस्या का समाधान हो जायेगा। एक्सप्रेस हाईवे लोगों के चलने के लिए है, लोगों को चलने से रोकने के लिए नहीं है। पूरे शहर के बीच से कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं जाता है। एक्सप्रेस हाईवे आउटर से जाता है। इसलिए इसमें सर्विस रोड बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे रायपुर शहर के 10 लाख लोगों को रास्ता मिलेगा। आज के समय में यह रायपुर शहर की हॉट लाईन है। अगर यह बन जायेगा तो रायपुर शहर के ट्रैफिक की समस्या समाप्त हो जायेगी। इसलिए आप सर्विस रोड बनाने की घोषणा कर देंगे तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान हो जायेगा। अगर सर्विस बनाने के लिए सब लोगों को एफ.ए.आर. देंगे तो लोग तैयार हो जायेंगे। आपको मुआवजा देने की भी जरूरत नहीं है। सर्विस रोड बनाने से एक्सप्रेस हाईवे का उपयोग हो पायेगा। इसलिए इसके दोनों तरफ सर्विस रोड बना दें तो निश्चित रूप से, कुलदीप जुनेजा जी ने जो कहा कि हम लोग हल्ला सुनते हैं कि कुछ लोगों को परमिशन दे दिया है। अगर कुछ लोगों को परमिशन दे दिया गया है तो गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है ? वहां 100 से ऊपर झुग्गी-झोपड़िया हैं, बस्तियां हैं, जिनको निकलने, आने जाने में परेशानी होती है, वहीं पर घरों में काम करते हैं । आप माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि उसमें सर्विस रोड दोनों ओर बनाई जायेगी तो पूरी समस्या का समाधान हो जायेगा, इस बात का मेरा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शहर में एक वी.आई.पी. रोड भी बना है । पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा रोड कहीं देखने को नहीं मिला होगा । वी.आई.पी. रोड में तीन रोड हैं । दो तरफ सर्विस और एक तरफ बीच में, वहां इतने एक्सीडेंट होते हैं, हर आदमी कन्फ्यूज रहता है कि कौन से रोड से निकलें, लोगों को दिखाने लायें कि ऐसे भी हमारे शहर के अंदर में तीन वी.आई.पी. रोड हैं, उसको तो पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिये । जहां आदमी कन्फ्यूज रहता है, निकल ही नहीं पाता है। वी.आई.पी. रोड में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं । वहां पर भी तो आपने सर्विस रोड में एन्ट्री दिया है, जहां सारे शादी के बड़े-बड़े भवन और होटल हैं । जब उनको दे सकते हैं तो गरीब आम जनता वहां जाती है तो उनको भी सर्विस रोड बनाकर एंट्री देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी । सदस्य बहुत चिंतित हैं, कुछ समाधान निकालिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण का विषय है, ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उसका वक्तव्य मैंने अक्षरश: दिया । वरिष्ठ सदस्य माननीय सत्यनारायण शर्मा जी,

जैसा कि कह रहे हैं, उनके पास बहुत सारे रिकार्ड हैं, शैलेष पाण्डेय जी भी कह रहे हैं कि रिकार्ड है, जो वक्तव्य दिया गया है, उससे अलग हटकर उनके पास कोई रिकार्ड है तो जरूर मुझको दे दें, मैं अपने विभाग दिखवा लूंगा। दूसरा, एक्सप्रेस वे के बाजू में ....।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेना और जांच करा लेना, इसमें थोड़ा अंतर है । (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं अपने विभाग के रिकार्ड से मिलाकर जानकारी दे दूंगा, जो प्रमाण हैं, वह बोल रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैं जानकारी दे दूंगा । जितने रिकार्ड आज हमारे पास है, उसके हिसाब से मैंने जानकारी दी । अब रही सवाल सर्विस रोड की है तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई बड़ा रोड फोरलेन, हाईवे, सिक्स लेन कुछ भी बनता है, सर्विस रोड का प्रावधान करके बनाते हैं, इसको सभी जानते हैं, लेकिन यह एक्सप्रेस वे छोटी रेल लाईन के ऊपर बना है, उसके बाजू में कहीं पर भी एक्सप्रेस वे के लिये, साईड रोड के लिये जगह नहीं थी, रेल्वे लाईन के बाजू में इतना जगह था, दोनों तरफ और छोटी लाईन सब को मिलाकर ही एक्सप्रेस वे की चौड़ाई करके बनाई गई है । अब रही सवाल अलग से सर्विस रोड बनाने की बात है, जो त्यजन किया गया है, दान किया गया है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ । अध्यक्ष जी, उन लोगों ने लिखा है कि हम अपनी मर्जी से इसको त्यजन कर रहे हैं, कोई भूमिका, मुआवजा नहीं लेंगे, लेकिन सर्विस रोड बनेगी तो यह मान्य होगा । यह सशर्त उन्होंने दिया है । सर्विस रोड बनाना हम शुरू कर रहे थे, वे लोग एंट्री मांगने लगे, तब हम लोगों ने सर्विस रोड बनाना बंद किया । जितने घर हैं, उसके लिये एक्सप्रेस वे में हम एंट्री खोलेंगे, एक्सप्रेस वे का मतलब क्या है, जितनी कॉलोनिया है, जितने घर है, जितने बंगले हैं, जितने रहवासी हैं, सब को हम एक्सप्रेस वे में एंट्री दे देते हैं तो एक्सप्रेस वे कह् हालत क्या होगी... (व्यवधान)

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय जी, बड़े बिल्डरों को रास्ता दिया गया है..(व्यवधान) उनके लिये एक्सप्रेस वे खोली गई है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- डायवर्ट किया गया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे में भी सर्विस रोड बनाई जाती है । रायपुर शहर के दोनों तरफ बनी है, मैं आपसे इसी बात का आग्रह कर रहा हूँ कि आप सर्विस रोड बना दीजिए, आपको एक्सप्रेस हाईवे में एंट्री देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि जहां-जहां पर कट्स हैं, वहां से लोग निकल जायेंगे। आप सर्विस रोड बना दीजिए, यह सर्विस रोड रायपुर शहर के विकास के लिये, रायपुर शहर के यातायात के लिये, रायपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो आज वह परिवहन समस्या है, यातायात की समस्या है । आपकी सर्विस रोड बन जायेगी तो आपको एंट्री देने की जरूरत ही नहीं है । जहां-जहां से कट्स है, वहां से निकल जायेंगे । आप सर्विस रोड के लिये प्रोविजन कर दें, सर्विस रोड आप पूरा गुढ़ियारी से लेकर और पूरा माना तक बना दें तो लोगों को सुविधा होगी

और सड़क के दोनो तरफ डेवलपमेंट होगा तो रायपुर शहर का विकास होगा, इसलिये सर्विस रोड अति आवश्यक है, सर्विस रोड आप बना दें, इस बात का आपसे आग्रह है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, हजारों की तादात में जनता वहां से निकलती है...। (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, बृजमोहन जी जो कह रहे हैं, एक अच्छा सुझाव है, उस पर मैं अपने विभाग में चर्चा करवा लूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, हम लोग पूरे देश में जाते हैं, सुपर एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस हाइवे बने हैं, हाइवे बने हैं, जहां पर भी गांव आते हैं, शहर आते हैं, सर्विस रोड बनी हुई है । आप सर्विस रोड इस पर बनाईये ना । सर्विस रोड बन जायेगी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने जो विषय उठाया है कि आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, आप किसी प्रदेश स्तरीय अधिकारी से जांच करवा लीजिए । आप विधान सभा की समिति से जांच नहीं करवाते हैं तो आप उसकी घोषणा कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी ।

श्री रामकुमार यादव :- नेशनल हाईवे बनाय हव, गरीब आदमी मन टैक्स दे-दे के मर जाथे । गड़करी जी ला बोल दव त ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने जो प्रपत्र लाये हैं, उनके नक्शे सब पटल पर रख दीजिए । माननीय मंत्री जी जांच करा लेंगे और उसका कुछ समाधान निकालेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- लीजिए पटल पर रख देता हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में, सर्विस रोड के बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बोला है कि समाधान निकालेंगे। जांच करायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह रायपुर शहर का गंभीर मामला है। 10 लाख की पॉपुलेशन है। उसके दोनों ..।

अध्यक्ष महोदय :- समाधान निकालेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बड़ी चिंता है। उसको तो इन्हीं लोगों ने बनाना शुरू किया था। तब तो आपने सर्विस रोड के लिये कुछ नहीं किया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कोई मुआवजा नहीं दे ...। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कई जगहों पर सर्विस रोड के लिये जगह नहीं है तो क्या हवा में बनायेंगे? कई जगहों पर रोड के लिये जगह नहीं है। इन लोगों ने सर्वे किया है, इन लोगों ने ही बनायी है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, अंतिम उत्तर दे दीजिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी जो खराब सड़क थी, उसको हमारी सरकार ने ठीक किया है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इनको साबाशी देनी चाहिए कि इनके समय की जो खराब सड़कें थी, उसको हमने ठीक कराया है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आरणीय मंत्री जी, उनके समय में सड़क खराब थी लेकिन कांग्रेस ने उसको ठीक किया, अच्छा किया। अब वह सड़क जनता के लिये बनी है तो उसकी सुविधा जनता को तो देनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुविधा देंगे ना, मना कहां कर रहे हैं। सर्विस रोड बनाने का काम इनका था। इन्होंने नहीं बनायी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, कई जगह सर्विस रोड के लिये जगह नहीं है। क्या हवा में सड़क बना देंगे ? कहां बनायेंगे बताईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप निर्णय करिये, मैं जगह दिलाऊंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, अपने समय में जगह क्यों नहीं दिलवाये ?

अध्यक्ष महोदय :- अगोरत रिहिस ना भैया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुम्हारा ही तो समय था। 15 साल का समय था, तब तो कुछ किये नहीं। वह भसक गया, उसको मंत्री जी ने बना दिया।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये फिर जमा कर दीजियेगा। मंत्री जी, अंतिम शब्द में कुछ बोल दीजिये।

श्री तामध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग जनता की सुविधा की दृष्किोण से ही बनाये हैं और जनता की सुविधा की दृष्टिकोण से आगे भी जो आवश्यक होगा, हम लोग उस पर चर्चा करके निर्णय लेते जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिये अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित।

(1.45 से 3.01 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
3.01 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री मोहन मरकाम
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री रामपुकार सिंह
5. श्रीमती इंदू बंजारे

समय :
3.02 बजे **अनुपस्थिति की अनुज्ञा**

श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर

उपाध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन, द्वारा मार्च-2023 सत्र में दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 24 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वास्थ्यगत कारण से मैं मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 24 मार्च, 2023 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य, श्री विद्यारतन भसीन को मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 24 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए?

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अनुज्ञा प्रदान की गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

3.03 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री चक्रधर सिंह सिदार

समय :

3.04 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) के पुरस्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री टी.एस. सिंहदेव जी।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टी.एस.सिंहदेव जी नहीं है। क्या इनको अधिकृत किया है ? या संसदीय कार्य मंत्री हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- इन्हें अधिकृत किया है।

(3) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023(क्रमांक 5 सन् 2023)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023(क्रमांक 5 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023(क्रमांक 5 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023(क्रमांक 5 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ।

समय :

3.04 बजे

वित्तीय विर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय :- अब वित्तीय विर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन वित्त मंत्री जी नहीं हैं, न वित्त सचिव हैं, न वित्त के डायरेक्टर हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यहां मैं नोट कर रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जो पूछ रहा हूँ। आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप इसी में आपत्ति लेते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यहां हमारे अधिकारी बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बैठे-बैठे व्यवस्था मत दीजिए न। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा शुरू करना है या 5-10 मिनट के लिए स्थगित करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप चर्चा शुरू करिये न। वह नोट कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोट करने का सवाल नहीं है। मुख्य बजट में चर्चा शुरू हो रही है। वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं। वित्त सचिव नहीं हैं, वित्त विभाग के कोई डॉयरेक्टर नहीं हैं। आप यह देखिये कि विधान सभा में क्या घट रहा है ? राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव में अधूरा छोड़कर चले गये और दूसरे दिन उसको आप ही की आसंदी से समाप्त मान लिया गया। आज स्थिति ये है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप चर्चा शुरू करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधान सभा की गरिमा का क्या होगा ? क्या विधान सभा की कोई गंभीरता है ? या बस औपचारिकता करना है तो गिलोटिन में पारित करवा दीजिए न और सरकार को छुट्टी दीजिए। यह बाहर में लंबी-लंबी बात करते हैं और अंदर में सामना करने की हिम्मत नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, अपने तरफ का क्या हाल है, यह भी देख लो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं विपक्ष में बैठा हूं। आप इस अंतर को समझो।

उपाध्यक्ष महोदय :- मुख्य सचिव, शासन अभी उपस्थित हैं, मंत्री भी हैं, चर्चा चालू करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोला न कि मैं चर्चा तो शुरू कर दूंगा। उसमें आपत्ति नहीं है। मैं तो जो बोल रहा हूं वह विधान सभा की गरिमा के लिए बोल रहा हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अगर आपकी स्पीच नहीं बन रही है तो इधर देखकर बात करिये तो बन जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी statesman हो गये हैं। वह विधान सभा से ऊपर हो गये हैं। वह कांग्रेस पार्टी की स्थिति में, कांग्रेस के नीति-सिद्धांतों से ऊपर हो गये हैं। विधान सभा में उनके बजट पर चर्चा हो रही है और उनको आंदोलन करने से फुरसत नहीं है। तो ऐसे वित्त मंत्री से प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी ? इस बजट में क्या गंभीरता है ? इसलिए मैंने कहा कि statesman हो गये हैं। उनकी जो स्थिति है, वह सबसे ऊपर है। विधान सभा में आज हमने उल्लेख किया था राज्यपाल के अभिभाषण तक ये सरकार बदल रही है। एक दिन आसंदी से व्यवस्था आती है कि राज्यपाल महोदय के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। एक दिन आपने ही व्यवस्था कर दी कि शांत माहौल में चल रहा है, उस दिन अनुमति दे दी गई कि आप राज्यपाल के खिलाफ बोल सकते हैं। आखिर विधान सभा में क्या हो रहा है ? आखिर विधान सभा की क्या गरिमा और गंभीरता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए कहा कि वह statesman हो गये हैं। इस देश में बहुत कम लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि माननीया सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और उनके नीचे रेहान गांधी जी हैं, उनसे

भी ऊपर उनकी हैसियत है। संवैधानिक दायित्वों के लिए भी, संवैधानिक शपथ लेने के बावजूद इसलिए यहां उपस्थिति जरूरी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीजें शुरू करता हूं। "रियाया खुश न हो जिसमें, हम ऐसी बादशाही को न पहले मानते थे और अब न तस्लीम करते हैं।" यह पंक्ति समझ में आई।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, सुन रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए सुन भर लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी लाईन बोलता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन्हीं भर को नहीं, किसी को समझ आया, पूछ लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको तो कोई बात समझ नहीं आयेगी। आप किस्मक के भरोसे हो न। "ये बात याद रखें इस दौर में, खोटा सिक्का हर दफा चलता नहीं।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट में चर्चा शुरू कर देता हूं। कुल बजट 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ रुपये है, पूंजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36 प्रतिशत है। ब्याज ऋण भुगतान हेतु इसमें 6919 हजार करोड़ रुपये है। बजट का 5.69 प्रतिशत है। आर्थिक स्थिति पर मैं पहले बोल देता हूं। राज्य के चालू वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की तुलना में 8 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, किन्तु स्थिर भाव 2018-19 की तुलना में 3.07 प्रतिशत की कमी आई है। आपने कहा है कि स्थिर भाव में सभी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, सेवा तीनों क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि केन्द्र से अधिक है। कृषि क्षेत्र में आप आर्थिक सर्वेक्षण को देख लें। कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी वृद्धि दर घटी है। 2018-19 में 14.39 प्रतिशत था और 2019-20 में 1.89 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 में 3.57 प्रतिशत, 2021-22 में 5.27 प्रतिशत और 2022-2023 में 6.53 प्रतिशत है। साहब, आपको बधाई हो। मुख्य बजट की चर्चा में आप अपनी गंभीरता देख लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव 11-12 या 2018-19 में 16.29 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.83 प्रतिशत की कमी आई है एवं 86 प्रतिशत की कमी आई है। फिर इन्होंने बिंदु क्रमांक 27 एवं 169 में लिखा है कि प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 12.60 प्रतिशत अधिक बताया गया है। मेरे पास में वित्त सचिव का स्मृति पत्र रखा है। वित्त सचिव के स्मृति पत्र में वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 2021-22 का 24.91 प्रतिशत है, जो इस प्रदेश के ऊपर लगभग 1.1 लाख 14 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हुआ है। जब हमने पिछले बार बताया था। आगे पढ़ेंगे तो बोले कि 11-12 के बाद से हम कर्ज लेते रहें और हमने इन तीन सालों से कर्ज नहीं लिया है। दो सालों में आपने इतना कर्ज ले लिया है जो 15 साल से दस गुना और आगे है। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 33 हजार 898 रूपये है जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत की वृद्धि बताया गया है। यह केन्द्र सरकार से

अपनी तुलना करते हैं। अभी मैंने बताया कि सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में यह केन्द्र सरकार से आगे हैं तो केन्द्र सरकार का जो प्रति व्यक्ति आय है, वह 1 लाख 97 हजार रूपये है जो कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय से 63 हजार ज्यादा है अर्थात् 32 प्रतिशत अधिक है। अब प्रति व्यक्ति आय की कमी की बात है। जो अर्थशास्त्री हैं। मैं तो अर्थशास्त्र को ज्यादा नहीं जानता हूं। एस.जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्र की कमी के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी है, यह माना जाता है। भारत सरकार से जब तुलना करते हैं तो केन्द्र सरकार में सेवा क्षेत्र से income लगभग 60 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में यह एस.जी.डी.पी. मात्र 33 प्रतिशत या उससे भी कम है। केन्द्रीय करों में इस बार 45 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होना बताया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त सचिव के स्मृति पत्र में कुछ चीजें बता देता हूं। इन्होंने जो income बताया है। केन्द्रीय करो में 45 प्रतिशत है, बाकी अपने income है, जिसका स्त्रोत मैं बताऊंगा। लेकिन वित्त सचिव के स्मृति पत्र में जो चीज है, वह पूंजीगत प्राप्तियां 15 हजार 500 करोड़ जो इस साल प्रस्तावित है जो विगत चार वर्षों से निरंतर कमी आ रही है। कमी कैसे आ रही है कि वर्ष 2019-2020 में अनुमानित पूंजीगत व्यय 13.32 प्रतिशत था, जो घटकर वास्तविक अनुमान आया, वह 10.43 प्रतिशत रहा । वर्ष 2020-21 में 14.44 प्रतिशत था, वास्तविक में यह घटकर 11.41 प्रतिशत हुआ । वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14.25 प्रतिशत था लेकिन वास्तविक में यह घटकर 12 प्रतिशत हो गया । अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 17 प्रतिशत पूंजीगत व्यय एक आदर्श माना जाता है । आगे जब बातचीत करेंगे तो इस बजट में कुछ भी नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रावधानित बजट में महालेखाकर स्टेट फायनेंस ऑडिट के अनुसार विगत् 4 वर्षों में जितना बजट प्रावधान किया गया था उसमें से 20 प्रतिशत राशि अर्थात् लगभग 20 हजार करोड़ रूपये खर्च ही नहीं किया गया । (माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में प्रवेश करने पर) माननीय मुख्यमंत्री जी आईये, आपका सदन में स्वागत है । खर्च ही नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त...।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अजय जी कहां आना है ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैंने तो आपका स्वागत किया । आपको तो मैंने स्टेटमेन कहा । सबसे ऊपर, विधानसभा से भी ऊपर, अपने दल से भी ऊपर, आपके नेताओं से भी ऊपर ।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, फिर से दोहरा दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- संवैधानिक दायित्व से अधिक आपके लिये आंदोलन ज्यादा जरूरी था ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आंदोलन के कारण देरी नहीं हुई, वहां सारे लोग थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, जब मैंने चर्चा शुरू की ।

श्री भूपेश बघेल :- आप कृपा करेंगे तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर लूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- (श्री रविन्द्र चौबे की ओर देखते हुए) उनका चेहरा क्यों बिगड़ रहा है ? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वैसे तो हर साल परंपरा रही है कि हर साल आमंत्रित करते हैं और विभिन्न सत्रों में हम लोग जाते भी रहे हैं । पिछले समय भी गये थे और इस समय भी निमंत्रण मिला था, हम लोग वहीं गये थे और जहां तक जो लंब ब्रेक हुआ । माननीय सदस्य लोग बाद में पहुंचे, मैं वहां पहले ही पहुंच गया था । मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आंदोलन के कारण से लेट नहीं हुआ क्योंकि आप अपने मन से ही तर्क-वितर्क करते रहते हैं तो आप उसके लिये स्वतंत्र हैं लेकिन कृपा करके यह मत कहिए कि मुझे आंदोलन के कारण से विलंब हुआ । मैं पहले ही आ गया था और जैसे ही हुआ, चूंकि सब साथी थे धरम भैया भी थे, बृजमोहन जी थे सब लोग साथ में थे । सब साथ में ही आये । इसमें भी आपको आपत्ति है तो फिर आप तो स्वतंत्र है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो समझता था कि आपका नियंत्रण बहुत है करके । अभी भी समझता हूं भई, मैं एक ही घटना में अपना मत नहीं बदलता लेकिन न तो आपके वित्त सचिव थे और न आपके वित्त डॉयरेक्टर थे । जब मैंने चर्चा शुरू की तब मुख्य बजट की चर्चा में केवल 2 मंत्री थे ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- वह छोड़िए न, एक मंत्री पर्याप्त है भाई ।

श्री अजय चंद्राकर :- तोर जवाब देना हा भूल हे, जिंदगी में मैं हा डिरेल नइ हों । तें चिंता मत कर ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- [XX][5]

श्री अजय चंद्राकर :- अब मुख्यमंत्री आगे, सबके नंबर बढ़ही । अब सबको नंबर बढ़ाना है, अब सब खड़े होंगे ।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, आपने क्या कहा ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप कितना भी बोल लीजिये, आप कुछ नहीं बनेंगे ।

श्री अरूण वोरा :- आप मेरी बात तो सुन लीजिये । आपने स्वयं सुबह प्रश्नकाल में कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल भरोसा है । मैंने किस बात पर बोला ?

श्री अरूण वोरा :- तो आप भरोसा कीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने किस बात पर बोला ? बोलो न ।

श्री अरूण वोरा :- आप बजट पर भरोसा कीजिये ।

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- डी.एम.एफ. का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ, संसदीय समिति की जांच की मांग कर रहे थे तब मैंने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है ।

श्री अरूण वोरा :- अब आपकी भावना कैसी है, यह हम नहीं जानते हैं । आपकी भावना साफ होनी चाहिए, हम लोग तो साफ मन से सुनते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आजकल खड़े बहुत हो रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं बनेंगे ।

श्री अरूण वोरा :- मैं तो बन चुका हूं । वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष हूं। मुझे केबिनेट मंत्री का रैंक है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप कितना भी बोल लें, आप नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं बन पायेंगे । हमेशा कोई दूसरा ही रहेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- काश मुख्यमंत्री जी के आने के पहले यह गंभीरता दिखाते ।

श्री अमरजीत भगत :- कुछ बोले से पहिली सरदार जी लगाबे नहीं तो दिक्कत हो जाही ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वित्त सचिव का स्मृति पत्र वर्ष 2023-24 के पृष्ठ-50 को आप देखियेगा कि निर्माण कार्यों के अनुसार व्यय की राशि या प्रशासकीय स्वीकृति 8 माह में 22 प्रतिशत ही खर्च की जाती है । मैं विगत् 4 सालों का पढ़ दूंगा । खर्च की जाती है अर्थात् अगले 4 महीने में 80 प्रतिशत राशि व्यय करनी है, अब उसमें निर्माण की गुणवत्ता और जितनी बात आज इन्होंने आज बजट में कही है तो यदि वित्त सचिव के स्मृति पत्र आप कहें तो मैं वर्षवार पढ़ दूंगा, इसमें यह लिखा है । अभी मैं वर्ष 2022-23 में अलग-अलग विभाग का पढ़ देता हूं, एक को उदाहरण के तौर पर पढ़ देता हूं । यह सिंचाई विभाग का है 2431 करोड़ में 544.49 करोड़ यह दिनांक 15.11 तक व्यय हुआ था । इसी प्रकार इसमें सभी वर्किंग विभाग का है तो यह बजट फिर पूरी तरह चुनावी है क्योंकि शुरूआत के 8 महीने जब चुनाव होगा तब तक 12 प्रतिशत खर्च होगा और आखिरी 4 महीने में जो खर्च होगा और आखिरी 4 महीने में जो खर्च होंगे तो यह बताइए कि वह किस तरह से होंगे? कैसे होंगे ? मोहन मरकाम जी प्रश्नकाल में बता रहे थे न । दूसरा, 6 माह बाद आचारसंहिता लग जायेगी। 12 प्रतिशत ही व्यय किया जायेगा। जो मैं बोला कि चुनावी बजट ही माना जाएगा। अब कुल प्राप्तियों की तुलना में जो कुल व्यय है, उसकी जो कमी है वास्तव में बजट के सिद्धांत के विपरीत है। ये इकॉनामिक्स माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पेशल इकॉनामिक्स है, क्योंकि यहां जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कहें, वही सत्य है। वही कानून है। वही नियम है। अब वह कैसे है, जब बिंदुवार बजट में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताउंगा। वित्त सचिव के स्मृति पत्र के हिसाब से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में कुल 86 हजार 349 करोड़ रूपए हुआ था। इसके बावजूद कुल व्यय 85 हजार 338.04 करोड़ ही किया गया, जिसमें 511.19 करोड़ रूपये कम खर्च किया गया। जो मैंने बताया कि बजट के मूल सिद्धांतों के

यह खिलाफ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक सिद्धांत है। वह स्टेट मैन हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं। वह सबसे ऊपर हैं। अब कर जहां-जहां से मिलते हैं, लिखा हुआ है। राज्य वस्तु कर से, केन्द्रीय वस्तु कर से, लेकिन मैं जिन-जिन से प्राप्ति हुई, असली चीज बताना चाहता हूं। माननीय सत्तू भैय्या अभी बिहार से घूमकर आये हैं। कमेटी, कमेटी, कमेटी एण्ड कमेटी और अभी एक और कमेटी बनेगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई है। डॉ. प्रीतम सिंह के प्रश्न के उत्तर में था। वह कैसी कमेटी है? कितनी बैठक हुई है? इस साल 6 हजार 700 करोड़ रूपये की दारू बेची गई। शराब के पैसे पर चलने वाली यह शराबी सरकार है। गंगा जल पीकर ये तर्क देते हैं। हमने इसके लिए गंगा जल पीया, इसके लिए पीया, उसके लिए नहीं पिया। [XX] जनता का वोट लिया है, जनता का आशीर्वाद लिया है, लोकतंत्र में भरोसा है, अपने कथन पर विश्वास है तो करके बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, ते का-का पीथस, तेला बता दे। ते का-का पीथस, तेला बता दे।

श्री रविन्द्र चौबे :- सब जानते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, ते काकर पीये हस।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि शराबबंदी होगी। ये कहें और नहीं कह सकते तो साहब फिर मैं बता देता हूं कि आप दिन में सपने देखना बंद कर दें। दिन में बहुत सपने हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा बजट के बिंदुओं पर आता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैय्या, कुछ बताए नहीं कि कहां गये थे आप?

श्री अमरजीत भगत :- कुछ बोल रहे हैं, सुन लो। अजय भाई, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे उन्हें 45 हजार करोड़ रूपये की आमदनी शराब से हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा करिए, केवल सोनपुर जिले में वहां आदिवासी हैं। आप वहीं जाकर राजनीति करिए। वहां बहस करिए। सीट खोज लीजिए, नगर अंबिकापुर से। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहां जाकर बहस करिए। यहां की विधान सभा की बात करिए न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरू हुआ नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की कल्पना से। आज का मेरा 7वें नंबर में एक प्रश्न था। मैं माननीय चौबे जी के ऊपर आरोप नहीं लगाता।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धरम भैय्या, थोड़ा दूसरी सीट में बैठ जाएं। भाव-भंगिमा में थोड़ा सा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरी प्रेक्टिस है। मैं अमितेश शुक्ल जी के साथ भी बैठ चुका हूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये गरूवा क्या है? गरूवा में क्या किया है? गौठान, गौठान बोलते हैं। इन्होंने गौठान बनाया ही नहीं है। गरूवा के लिए

यह किया है, लिखा है। मनरेगा में गौठान नाम का शब्द नहीं है। चारागाह विकास है। मैं पूछने वाला था कि क्या टी.एस. है? क्या मापदंड है? क्या प्रक्रिया है? कर किसमें-किसमें खर्च करोगे और माननीय कृषि मंत्री जी किसी गौठान में मुझे चारागाह दिखा दें। वो जगह बताएं, वहीं जाउंगा। वो जहां बताएंगे, वहीं जाकर देखेंगे । चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं । देखेंगे, कहां पर चारागाह है ? घुरवा में, डी.एम.एफ. से भी घुरवा बना है । घुरवा में क्या बना है भाई ? घुरवा कैसे बनता है, क्या टी.एस. है, क्या मापदंड है ? इसीलिए मैंने कहा कि माननीय भूपेश बघेल जी ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, पिछले समय में डी.एम.एफ. से स्वीमिंग पूल बनता था । अब कम से कम स्वीमिंग पूल कहीं नहीं बन रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाड़ी, बाड़ी में भी मनरेगा से खर्च हुआ है । बीज वगैरह बांटे उसको तो वे भी भी स्वीकार कर चुके इतने बीज कहीं नहीं बंटे । लेकिन मनरेगा से बाड़ी में क्या काम हुआ है यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मेरे पास भी बाड़ी है । डी.एम.एफ. से बाड़ी में क्या खर्च हुआ है ? मैं आपको परिशिष्ट दिखा दूंगा । उस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलूंगा । जितने पैसे खर्च हुए हैं ईमानदारी से पढिये, वह पैसों की लूट है। भ्रष्टाचार नहीं है, लूट है लूट । इस सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता है, जनता के पैसे का थोड़ा सा भी दर्द है तो मैंने उस दिन भी कहा था कि थर्ड पार्टी असेसमेंट करवा लें कि लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है । उपाध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल विकसित हुआ जो इसमें लिखा है । चार वर्षों में जो पहला नम्बर आया है 16,415 करोड़, 9 हजार के हिसाब से बांटे, समझ रहे हैं ना । यदि भाग दें तो उसमें 73 हजार हेक्टेयर होता है, उस पैसे को आप 9 हजार से भाग दे लो तो इन्होंने पूरा पैसा किसानों को नहीं दिया है । इन्होंने जो बोला है उसी में, इतने लाख हेक्टेयर इसमें लिखा है । गणित के विशेषज्ञ इधर बैठे हैं, ये लोग कम्प्यूटर में, मोबाइल में निकाल लें । इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है । सभी किसानों को 9 हजार भी नहीं मिला है । अब दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब इधर बैठते थे तो इनका प्रिय नारा था 37 लाख किसान हैं वे कहां चले गए । 40 लाख 10 हजार किसान, छत्तीसगढ़ पूछता है अब बाकी कहां गए ? उसके बारे में भी बता देता हूं । आपने 2019 में पहले साल धान खरीदा 18 लाख, 43 हजार, 370, इनपुट राशि जो आपने आयोजित की वह 5 हजार 627 करोड़ । फिर खरीफ में, अभी मैं केवल धान की बात कर रहा हूं, कोदो, कुटकी, राहर जिसमें आदान राशि देंगे उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं । उसमें दिया गया है या नहीं उसको जोड़ोगे तो और कम किसानों को पहुंचा है । अब 20 लाख, 59 हजार 68 किसान हैं तो किसान बढ़ गए लेकिन 2020 में आदान राशि हो गई 55 हजार 53 करोड़ । किसान बढ़ गए, राशि घट गई । अब एक साल पीछे चलता है इसलिए 2021 का चल रहा है । 23 लाख, 99 हजार, 604 में अब तक, 52 हजार 35 रूपया मानी 52 हजार, 5 हजार 235 रूपए । यानी किसान बढ़ रहे हैं, राशि घट रही है और यह कहते हैं कि 9

हजार दे रहे हैं । अब मैं आपको बता दूं कि 40 लाख किसान हैं । आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ेंगे तो सब में आजीविका में 80 प्रतिशत ही लिखा है । किसान बढ़ रहे हैं तो भी 80 प्रतिशत निर्भर हैं । यानी चार साल से 80 प्रतिशत ही फिक्स हैं । किसान कम रजिस्टर्ड थे तो भी 80 प्रतिशत, ज्यादा थे तो 80 प्रतिशत और 40 लाख हो गए तो भी 80 प्रतिशत । उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मॉडल में मैं बाद में बात करूंगा । गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना में 2 अरब रूपए से ज्यादा का गोबर खरीद लिया गया । आज के प्रश्न के उत्तर में जितना बनाया गया है उससे कम बिका है । इसको प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है कि वह कितने दिन उपयोगी होगा, कितना काम करता है, कितने दिन उसकी उर्वरक शक्ति होती है? वह मॉडल ऐसा है कि आपने बरसात में किसानों को तीन-तीन बोरा जबर्दस्ती पकड़ाया।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- कोई जबर्दस्ती नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- बरसात में कोई गोबर खाद नहीं पलाता। कृषि मंत्री जी, बहुत अच्छे किसान हैं। ऐसा कैसे करते हैं, मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो वह नारा है। गोधन न्याय योजना में सीधे-सीधे घपलेबाजी को छोड़ कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 17 दिसंबर के बाद जांच होगी, इसमें सब जेल जाएंगे। मैंने उस दिन कहा था।

(मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- जांच होगी, 17 दिसंबर के बाद नई सरकार आएगी, मैं तब की बात कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सरकार आएगी तब ना।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग किसानों से कितनी खरीदी करते थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- हां बिल्कुल बिल्कुल। यह बोल रहे हैं ना, हमको कोई वनवासी बोले तो हम उसका मजा बताएंगे । बजट बुक में वनवासी छपा है, वे पढ़ लें। कवासी लखमा जी जो बाहर में खड़े होकर इधर उधर बोलते हैं ना कि वनवासी कोई बोलेंगे तो देखेंगे। आपकी सरकार ने इसमें वनवासी लिखा है। हिम्मत है तो आप इनका क्या करोगे, खड़े होकर बताईए।

श्री शिवरतन शर्मा :- बता-बता।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भैया, खड़े होकर बोल देना।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, वनोपज, लघु वनोपज संघ के लिए 20 करोड़ रूपये दिया है, बजट कुछ नहीं है इसलिए बोला कि छात्रवृत्ति दी नहीं है, बीमा दी नहीं है, 2 साल से उसकी प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रूपए दिया है। वह 20 करोड़ रूपए तो देना ही था, बजट नया क्या हुआ है ? कोदो, कुटकी खरीदी, मुख्यमंत्री जी का मॉडल है। तेंदूपत्ता के लाभांश से खरीदी जाएगी। आप संग्राहकों के लाभांश से अध्ययन कर लीजिएगा। यदि उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी तो तेंदूपत्ता संग्राहकों के लाभांश

से की जाएगी। यह आप पढ़ लीजिएगा। राजीव गांधी कृषि मजदूर योजना, इसमें कौन सर्वे करता है, कितना सर्वे किया, कितना आवंटन हुआ, इसको भगवान जानते होंगे, आप जानते होंगे ? मैं तो आज तक नहीं जानता, आप बताईएगा, कैसे सर्वे होता है ? माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी नहीं बोलेंगे तो अपने डिमांग मांग में बोल दीजिएगा। मैं बेरोजगारी भत्ते क्रम से पढ़ रहा हूं, बेरोजगारी भत्ता 148 और 8 नंबर में है।

श्री कवासी लखमा :- आपकी सरकार ने क्या किया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- हिम्मत है, इसमें वनवासी लिखा है। अपने केबिनेट के खिलाफ कुछ कर सकते हो ? बोल सकते हो कि बस बाहर में बोलना आता है।

श्री कवासी लखमा :- अब आप मत बोलना।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2500 रूपया, अभी इसी सत्र में 3 मार्च की प्रश्नोत्तरी के हिसाब से 18 लाख 19 हजार 126 बेरोजगार हैं। अब 250 करोड़ रूपया में यह 8.33 लाख लोगों को देंगे। फिर मैंने कहा....।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अजय भाई, हाथ हटा लीजिए ना, जहां डाले हो वह ठीक नहीं है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझे जितना भी डिरेल कर लें, मैं होने वाला नहीं हूं। आपके गुरूदेव सामने बैठे हैं, वे आज हाथ नहीं उठायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बेरोजगार कहां जाएंगे ?

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, यह जो केन्द्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसका हिसाब बताईए ? हमारी छत्तीसगढ़ सरकार तो रोजगार देने में अग्रणी हैं और उसके साथ-साथ 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट, वोरा जी क्या है, आप यहां चिंता कर रहे हो, आपके तीन छत्तीसगढ़िया सांसद कहां हैं, जो छत्तीसगढ़ की चिंता करे ? राज्यसभा में तीन छत्तीसगढ़िया सांसद बनाये हो ना। आप भी वही बात करेंगे तो वे राज्यसभा में क्या बात करेंगे ? जो काम यहां का है, यहां करिए और जो काम वहां का है, वहा रखिए। मुझे लगता है (व्यवधान) भरोसा नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उनकी आवाज को दबा दिया जाता है।

श्री अरूण वोरा :- कौशिक जी, आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसको मेरे समय में मत जोड़िएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, टोका-टाकी ना करें, बहुत लंबी सूची है।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, क्या है, कैसे है, उसके सिद्धांत में आप 139 की चर्चा मांग लीजिए, समझ रहे हो ना। जो माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय बोले ना, वह तीन लोग हैं, जो यहां से गये हैं, यहां से पेंशन तनख्वाह लेते हैं। आप उनको लिखकर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर साहब चलिए, आप फिर उनको भड़का रहे हो।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- लेकिन जो आर.एस.एस. है, वह मंदिर में मुसलमान जोड़े की शादी क्यों कराने लग गये, भैया ?

श्री अजय चंद्राकर :- ते जा के सरस्वती शिशु मंदिर में दादागिरी कर। (हंसी)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- तोर अनुसरण करत हंव। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- शिक्षित बेरोजगारों को 148 नंबर में दूसरा एक कॉलम है, 40 हजार युवकों को 10 करोड़ दिया जाएगा। भाई, क्या दिया जाएगा ? स्कील का काम तो चल ही रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, रश्मि जी जो बोल रही हैं उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 50 हजार रूपये का प्रावधान किये। एक सुधाकर बोधले नाम के व्यक्ति थे। जब वह 25 हजार रूपये था तो वह अपनी सरकार, अपने विभाग का कमीशन मांगने के लिए महासमुंद में धरने में बैठे थे। उनको कलेक्टर जाकर हाथ-पैर जोड़कर उठाये कि आप उठिये, इससे हमारी फजीहत हो रही है करके । अब तो यह 50 हजार रूपये हो गया है और यह कमीशन का काम है इसलिए अब तो पूरे 33 जिलों में लोग बैठेंगे। वह मैडम हंस रही हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि सुधाकर बोधले धरने में बैठे थे या नहीं बैठे थे और यह पूरे जांच में आया है कि कौन-कौन कमीशन खाया और क्या-क्या लिया। अब तो इसमें कमीशन और ज्यादा हो गया है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- लिस्ट होही तो दे देबे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नगरीय क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के। एक लाइन में यह है कि नगरीय विकास के लिए 1 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है तो यह तो कटमनी और तोलाबाजी वाला विभाग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को विशेष रूप से समर्पित करते हुए एक उदाहरण बता देता हूं कि इस विभाग में वी.आई.पी. चौक से पं. दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्ति (थाना) तक एक सड़क बन गई। आज तक यहां प्रश्न लगाने के बावजूद कोई नहीं बता रहा है कि वह सड़क किसने बनाई। अब यह क्या उत्तर दिये हैं कि वह राजमार्ग जाने। राष्ट्रीय राजमार्ग जाने कि इसको किसने बनाया है। इससे पहले यह उत्तर आता था कि हमने टेण्डर किया, नहीं आया, यह हुआ, नहीं हुआ। टेण्डर की प्रत्याशा में बिना नियम-कानून के। वह माननीय मुख्यमंत्री जी के

क्राऊन प्रिंस हैं। वलीवाहत तो आपके पीछे बैठते हैं। आपके क्राऊन प्रिंस ने यह हिम्मत की है। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद रहेगा, वह क्या नहीं कर लेगा? क्या नहीं कर लेगा?

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, आप आशीर्वाद ले लिया करो।

श्री अजय चंद्राकर :- अब मैं आपको स्मार्ट सिटी भर का एक उदाहरण बता देता हूं। अमृत मिशन कांग्रेस के लोगों का अमृत पीने का माध्यम है। अभी यह बता रहे थे कि गड्ढे में गिर गये थे। दूसरी बात, बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण को देखने के लिए तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी 38 बार गये। वह जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। यह पेपर में आया है। वह 38 बार उसको देखने गये तो मैं वर्तमान चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार उसको देख कर आ जाएं कि उसकी क्या हालत है ? 38 बार देखने के बाद वह कैसे बना है और उसमें कितना खर्च है ? वहां कितने लोग आते-जाते हैं और वहां पर क्या होता है ? मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार उसको देखकर आ जाएं। अब 15 नंबर में रिपा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-1 करोड़ रूपये दिया जाएगा। रिपा मतलब, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, कोई लोन की व्यवस्था नहीं, कोई स्टेट गारंटी की व्यवस्था नहीं और हम 146 शहर में इसको 1-1 बनाएंगे। इसके लिए हम 1-1 करोड़ रूपये देंगे। 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। आज व्यवस्था है और जब तक इसकी प्रशासकीय स्वीकृति, नियम-निर्देश बनेंगे, तब तक कोलिंग हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उनसे मेट्रो मांगे हैं। आप उसके लिए एकाध रूपया डाल देते। आप बोलते हैं कि आप कंपनी बनाएंगे। आप पी.एस.यू.एल. बोलते हैं। आप संयुक्त उपक्रम बनाएंगे, सर्वे करवाएंगे और भारतीय रेल से आग्रह करेंगे। आप इसमें कुछ तो देते। क्या है कि हम छत्तीसगढ़ के लोग कुछ नहीं समझते। अच्छी बात है। यदि मेट्रो लिखने से मेट्रो चल जाएगी तो आप और लिख लीजिए कि हम ड्राइपोर्ट बनाकर जलपोत भी चलाएंगे। हम वेनिस की तरह यहां से नहर से परिवहन करेंगे। लिखने में क्या जाता है ? आप लिख दीजिए। आप रिवाइज कर दीजिए। आप घोषणा कर देंगे तो छप जाएगा। जब आप राज्यपाल के अभिभाषण को बदल सकते हैं तो इसको भी बदल दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप 5 साल तक रतनजोत से गाड़ी चलवाये थे न।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- वह भी राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम साहब की गाड़ी को रतनजोत से चलाकर बताये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया, आप लोग अपनी सीट से बात कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यहां पर मेट्रो चलाओगे। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सड़के के दोनों किनारे रतनजोत का पेड़ है वह न काम का है और न काज का है और उससे बच्चे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अकलतरा में दूसरा कौन है ? अभी आप रमन सिंह बन गये हैं ? पहले आप यह बताइये कि आप रमन सिंह जी की कुर्सी पर क्यों कब्जा किये हैं ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्य मंत्री जी, आप [XX] बनाना और [XX] बनाना बंद कीजिए। यहां बस नहीं चल रही है और आप यहां मेट्रो चलवाएंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप रतनजोत को हटवा कर कोई इमारती लकड़ी लगवाइये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप हर बात में खड़े हो जाएंगे। तेहा 4 साल में ओतके सीखे हस। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- तो धीरे-धीरे सीखत हन न।

श्री कुलदीप जुनेजा :- चंद्राकर जी, जनता 15 साल से आपको बना रही थी। जनता ने आप लोगों को बना दिया और अब जनता ने हम लोगों को मौका दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या आपको अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है ? क्या आप उनकी फोटो, तस्वीर नहीं देखे हैं ? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमको हमारे यहां मेट्रो चलाना है आप हमारी मदद कीजिए। आप उनकी काबिलियत पर शंका कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो पत्र की कॉपी पटल पर रख दीजिए । खाली हवा-हवाई बात करते हो । हवा-हवाई बात मत करिए, पटल पर रख दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- फोटो देखे या नहीं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बस नहीं चला पा रहे हैं, मेट्रो चलाओगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो देखा है या नहीं देखा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर की सड़क नहीं बना पा रहे हो, रायपुर का गड्डा नहीं भर पा रहे हो और मेट्रो चलाओगे ? हवा-हवाई बात करते हो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों का बनाया हुआ पुल हर साल भसकेगा, कैसे करोगे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- देश में बुलेट ट्रेन चला रहे हो तो हमें कम से कम मेट्रो चलाने दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप दुर्ग में रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दुर्ग जिले में ही रहते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भाई, डीजल नहीं मिलेगा खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से । बाड़ी कहां गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जांच करवा लो, जिसकी गलती होगी, उसको सजा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, अपना भाषण चालू रखें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप रतनजोत की बात बार-बार करते हैं । आप सवा चार साल से सरकार में हो । अगर गलत हुआ है तो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, यह बता दीजिए । इसमें आपकी क्या सेटिंग है ?

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री थे और मैं भी विधान सभा का सदस्य था । डॉ. रमन सिंह जी ने कहा था कि मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आजतक मेट्रो नहीं चल पायी है । अभी मुख्यमंत्री जी ने नया रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो चलाने की घोषणा की है, उसका स्वागत है । आपने जो घोषणा की थी, वह आजतक पूरी नहीं हुई, केवल कागजों में लिखने के लिए घोषणा करते हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- रतनजोत का एक भी फल नहीं फला ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वोरा जी, बैठिए । मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बृजमोहन भाई कह रहे थे कि आप सड़क नहीं बना पाये । आपने एक फ्लाई ओव्हर बनाया है । हम इधर से मरम्मत कराते हैं, उधर भसक जाता है । हम उधर मरम्मत कराते हैं, इधर भसक जाता है । इतना कमजोर फ्लाई ओव्हर क्यों बनाये हैं, आप बताईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी बताता हूं ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा में मंत्रियों को जो रूम आवंटित हुआ था, वह जोगी जी बनवाये थे, उसी समय का रूम बना हुआ था । आप लोग 15 साल शासन में रहे, लेकिन 15 सालों में आपने मंत्रियों के लिए कक्ष नहीं बनाया । हमारी सरकार आने के बाद हमने मंत्रियों के लिए नया कक्ष बनवाया। आपने कुछ नहीं किया और बड़ी-बड़ी बात करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्रियों के लिए कक्ष बन गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी कक्ष बन गया ना ? जीर्णोद्धार हो गया। वह बड़ी उपलब्धि है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे दो, अपना कार्यालय मत बनाओ, अपना घर मत बनाओ ।

संसदीय सचिव (कृषि मंत्री से सम्बद्ध) (सुश्री शकुन्तला साहू) :- प्रधानमंत्री आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री कवासी लखमा :- आपने उस दिन नहीं सुना क्या ? प्रधानमंत्री आवास के लिए 3230 करोड़ रूपए दे रहे हैं, उसका सर्वे करने जा रहे हैं । अगर जरूरत होगी तो आपके लिए भी बना देंगे । हमारे सरकार द्वारा बनाए गए भवन में रहोगे तो ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंडिका 21, 39, 40 और 41 को मैं रोक देता हूं, दूसरा कागज पढ़ता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज तैयारी नहीं होएहे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, स्कूल खोलना मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं ।

श्री गुलाब कमरो :- स्कूल खोलना मतलब यह है कि आपने बस्तर में जो स्कूल बंद कर दिया था, उसको भूपेश सरकार ने चालू किया है । इसको स्कूल खोलना कहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, स्कूल खोलना मतलब यह होता है कि उसका Curriculum क्या है, उसका Extra Curriculum क्या है, उसकी Faculty कैसी है, उसके Equipment कैसे हैं ? आपने आत्मानंद स्कूल खोला, उसके लिए बजट रख दिया और उसमें आपने आजतक यू डायस (यू-डीआईएसई) का नम्बर नहीं लिया है, जो शिक्षा देखते हैं, वह समझ जाएंगे कि यू डायस क्या होता है ? आपने आजतक नहीं बताई या उस स्कूल के ब्रोशर में हमने नहीं पढ़ा या यह एक Extra Curriculum *Activities* होगी, संगीत शिक्षक, पेंटिंग शिक्षक की भर्ती हुई है, कोई तबला वादक की भर्ती हुई है । रंग रोगन पोत दिया गया और Deputation से शिक्षक जुटा लिए गए और कह दिया गया कि English School है। यह भी कहा गया कि यह दुनिया का सर्वोत्तम स्कूल है और आप उसे संविदा भर्ती में चला रहे हो।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आरक्षण बिल में साईन हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इस बारे में चर्चा करते तो हम भी समर्थन करते । आप कॉलेज खोल रहे हैं । अब जिस चीज को मैं देख रहा था, वह मेरे हाथ में है । मैं बजट की बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ देता हूं । इन्होंने जितनी बार नवीन मद मांगी है, एक-दो चीजों को छोड़ दें तो लगभग सभी चीजों में सेट-अप चाहिए । इसलिए उनको मैं पढ़ता नहीं, एक विषय को पढ़ देता हूं । चाणक्यपुरी में नया भवन चाहिए । अगर नई दिल्ली में तीन भवन हो जाएगा तो उसका सेट-अप चाहिए ही होगा । तहसील कार्यालय, अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण में नया सेट-अप नहीं लगेगा । राजिम पुन्नी मेला, यह सब नवीन मद में 10-12 प्वाइंट हैं । मुझे इसमें एक चीज पर आपत्ति है। आप मानसिक चिकित्सालय रायगढ़ और सरगुजा में खोल रहे हैं। हमने बोराई में खोला था। हमारा NIMHANS के साथ समझौता था कि इसको Center of excellence बनायेंगे। ये नवीन मानसिक चिकित्सालय खोलना चाहते हैं तो पहले बस्तर में खोल लें, जहां जवान स्ट्रेस में आत्महत्या करते हैं, जहां उनकी ड्यूटी है।

वाणिज्य मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर बोलेंगे तो कुरूद में भी खोल देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आगे आ रहा हूं। दूसरा पाटन या दुर्ग जिला में खुलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुम्हारी में जो स्मार्ट थाना बनवा रहे हैं, वहां स्मार्ट अपराध हो रहे हैं। सामूहिक आत्महत्या, सामूहिक हत्या, दिन दहाड़े गोली चालन हो रहे हैं। दो-तीन, चार-चार मंत्री होने के बाद पाटन अवसाद में क्यों है ? दुर्ग अवसाद में क्यों है ? वहां काउसिंग की जरूरत है। वहां मानसिक चिकित्सालय

खोला जाये। अभी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री नहीं हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चाणक्यपुरी में नया भवन बनाओगे तो वहां 2 सी.एम. suit बनाईयेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको यह भी पूछना चाहिए कि मानसिक चिकित्सालय के लिए सरगुजा को ही क्यों चुना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने सरगुजा को इसलिए चुना क्योंकि महाराज जी की मानसिक स्थिति तो मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी। अब तो उसकी बात ही मत करो। वह वलीअहद साहब आ गये। साहब, आप इस सरकार के वलीअहद हो और crown prince साहब बाहर हैं। जो दीनदयाल चौक से यहां तक सड़क बनवाये हैं, वह crown prince है, उनकी crown princee ज्यादा चल रही है। ध्यान रखना, वलीअहद साहब, आपको खतरा हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी, मितानीन, कोटवार, रसोईयां ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परन्तु मुख्यमंत्री जी जब आप अपना जवाब देंगे तो सरगुजा में मानसिक चिकित्सालय खोलने की जरूरत क्यों है, इसको जरा बता देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने उसकी मानसिक संतुलन खराब कर दी है। जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी घोषणा-पत्र में लिखे थे, उस पर एक चुटकीला चल रहा है। हम सफाई वाले काम छोड़कर बेरोजगार हो जाते हैं, इसमें 15-18 सौ मिलता है और बेरोजगार हो जायेंगे तो 2500 रूपया मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब असली चीज जितने भी छोटे अनियमित कर्मचारी हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, यह अपने आपको छत्तीसगढ़ियां सरकार कहती है लेकिन डोमीसाइल की परिभाषा नहीं बनाती, उनको नियमित करने का प्रावधान इस बजट में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लाईन सिंचाई योजना के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे आपसे एकदम अपेक्षा नहीं थी। आप आर्थिक सर्वे पढ़ लो। चार साल से 36 प्रतिशत, 36 प्रतिशत, 36 प्रतिशत लिख रहे थे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जादू है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो अधिकारी ऐसे बजट भाषण को लिखते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप 36 प्रतिशत, 36 प्रतिशत लिख रहे थे और आपने अचानक 38 प्रतिशत लिख दिया। तो आप यह बताईये कि आपने 4 महीने में क्या किया, जिसमें सिंचाई का रकबा 38 प्रतिशत हो गया। 10 लाख हैक्टेयर से 13 लाख हैक्टेयर कर दिया तो कैसे कर दिया ? आप ही की सरकार का आर्थिक सर्वे है, आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी और सिंचाई के लिए एक रूपये का भी बजट नहीं लिखा है और यह अपने आपको किसानों की सरकार बोलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका पशु चिकित्सा, डायल, पुलिस प्रशासन, विधि विधायी कार्य विभाग के लिए 3137 नवीन पद मांगा है। नैतिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बार-बार एलीगेट नहीं करता। आप तारीख बताईये कि आप इन पदों को कब तक भर लेंगे ? पुरानी कितनी भर्ती शेष है ?

आप क्या समझते हैं कि सिर्फ बजट में चार लाईन लिख देने से, इनके मेज थपथपा देने से छत्तीसगढ़ का भला हो जायेगा ? ये नारा लगा रहे थे। ये नारा लगाने और मेज थपथपाने के इक्यूपमेंट बन गये हैं, टूल्स बन गये हैं। आपने इनका व्यक्तित्व विकास नहीं होने दिया। आप ऐसी करो, आपने माननीय विधायकों की क्या स्थिति बनाई है ? ये फर्जी चीज में मेज थपथपायेंगे। आपने इसमें सेटअप मांगा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब हम लोग भर्ती करने निकलते हैं तो आप रोकते क्यों हो ? आप ऐसे काम क्यों करते हो जिससे, हमारी भर्तियां रूकती हैं ? आप हमारी क्यों मदद नहीं करते ? हस्ताक्षर नहीं हो पाता औरवहां एक चिट्ठी भी नहीं लगा पाते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, ऐसा है कि आप इस बात को अपनी अन्तरात्मा से पूछिये ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर साहब, 40 मिनट हो गये हैं और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ी देर चलने दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पी.डब्ल्यू.डी. के लिए बजट मांगा है। इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए बजट में बोला गया है। चार साल से पूंजीगत व्यय घटा है, यह मैंने बताया और पांचवे साल का अनुमान है। तो इसमें जो राशि लिखी है, वह 3896 करोड़ के हैं, बाकी सब लायबिलिटी है, यह नई चीजें हैं । बारिश लगने वाली है, एक-दो महीने में बारिश आ जायेगी, बजट पारित होगा, गवर्नर से आयेगा सरकार के पास जायेगा, फिर विभाग में जायेगा, फिर ई.ई. तक पहुंचेगा, फिर टेंडर लगेगा, फिर एजेंसी तय होगी, तब तक पोलिंग हो जायेगा, यह मेज थपथपाते ही रह जायेंगे बेचारे, यह इसी के लिये पैदा कर दिये हैं । संसदीय कार्यमंत्री जी ने हल्ला करने का ट्रेनिंग खूब दिया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिंचाई को बता दिया, अब आपको एक बात बता दूं, जो आप इंफोर्समेंट लॉ को ला रहे हैं, एकाध उदाहरण आप बता दो कि आपके पास कहीं बीज निरीक्षक है तो ? बीज का परीक्षण हुआ है तो आप एकाध बता दीजिए, जिनको आप बीज निरीक्षक मानते हैं ? किसी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सदन में बुला दीजिए ? आप तो बीज का परीक्षण करके मुझे बता दें, आप तो किसान की सरकार हैं, 1969 के एक्ट की भावना क्या है, मैं चाहता हूँ कि उसको सब को पढ़ने के लिये दें । आप क्या कर रहे हो, यह सामने आ जायेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां अलग-अलग प्रकार के लगभग 18 लाख कैटल हैं, आप दतरेंगा में एक क्यों बनवा रहे हो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में फार्म काम्पलेक्स के लिये पैसा मांगा है, मान्यता तो मिली नहीं है, उसी के कारण ही आप मांगे हैं । उसी के कारण मांगे हैं, कोई नई चीज नहीं की है । समझ रहे हैं ना ? बीज इन्फोर्समेंट लॉ में आपने स्वीकार कर लिया कि खाद बीज के एफिलियेशन जिसको एलडीएच से लेंगे । जितने की मान्यता आप लेंगे...।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप नहीं किये थे, उसी के लिये है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो मान्यता आप ले रहे हैं, कृषि में सिर्फ इतने ही बात का उल्लेख है ना, बहुत बड़े कृषि मंत्री हैं आप ? एक भी प्रोग्राम नया नहीं है । आपने तो स्वीकार कर लिया है ये क्या है,

तीनों युग में पाये जाते हैं, इतने को लिखने की भी जरूरत नहीं थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्फोर्समेंट लॉ भारत सरकार का एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है, किसानों को सुरक्षा देता है । एक भी बीज निरीक्षक बता देना, बीज के प्रमाणीकरण के लिये कैसा है, क्या है, रासायनिक कंम्पोनेंट कितना है, मैं मान जाऊंगा । कस्टम मिलिंग से संबंधित सी.एम.आर. में वृद्धि के लिये 1000 करोड़ रूपया, इसको रोक कर एक नीरज जी की एक कविता सुना देता हूँ-

नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची
कवियों ने निराला की कलम तक बेची
न जाने इस दौर में क्या-क्या न बिका
लोगों ने आंखों की शरम तक बेच दी

श्री राजमन वेंजाम :- आपके मोदी जी तो रेल्वे, एअरपोर्ट, एल.आई.सी. सब बेच रही है । आप इसके लिये नहीं बोल रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- पूरे देश को बेच दिया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोदी जी तो पूरे देश को बेचे हैं । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- मन ही मन मोदी-मोदी बोल रहे थे क्या । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपके लिये दो लाईन अर्ज है ।

दवा न दो अब अक्सीर मार डालेगी
हर एक तबीब की तकदीर मार डालेगी
जो आदमी किसी नागिन से बच गया
उसको तुम्हारे जुल्फ के रहगीर मार डालेगी
जरा संभल के मोहब्बत के ख्वाब देख ए दिल
ए ख्वाब को ताबीर मार डालेगी
मैं देखता हूँ उठता हूँ चूम लेता हूँ
कभी मुझे तेरी तस्वीर मार डालेगी

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- इंग्लिश में पढ़ो यार । यह नही जमा ना । इंग्लिश में पढ़ो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लोगों ने आंखों की शरम तक बेच दी, नीरज जी ने ऐसा क्यों बोला । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एक ठन मैं सुना देथंव ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कविता का ही जवाब देना चाहता हूँ । अगर देखना है कांग्रेस की उड़ान को देश में और प्रदेश में भूपेश की उड़ान को, तो आपको आसमान को और ऊंचा करना पड़ेगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- वोरा जी, व्यक्ति पूजा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। आप समझ रहे हो। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमर माननीय सदस्य हा शायरी मारिस हे।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, वह कांग्रेस की बात कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वह मेरा काम नहीं है। मैं बी.जे.पी. के पंचनिष्ठाओं को मानता हूं। मैं समाजवाद से कांग्रेस की ओर नहीं मिलता। मैं भाजपा में हूं और भाजपा में जिऊंगा, भाजपा में मरूंगा। इस लाइन को लिख लो। मैं समाजवाद से कांग्रेसी नहीं बनता।

श्री अरूण वोरा :- मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही...।

श्री संगीता सिन्हा :- हम आपको अपने में मिला भी नहीं रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चमचागिरी करके हित में नहीं जाता ।

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी के जो बात हे, तेकर से मोला ये लगिस हे।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, मैं चमचागिरी नहीं करता।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, इतना विचलित क्यों हो जाते हो ? आराम से बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी जो शब्द बोलिस तेकर से यह होथे। 'का कहत का होगे, [XX]' ई मन के। आने शब्द बोलथे (व्यवधान)।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 के कस्टम मिलिंग का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है । अभी वर्ष 2021-22 का सभी प्रकार का भुगतान अप्राप्त है। अभी वर्ष 2022-23 की तो कोई चर्चा नहीं है और दलाल गली-गली सक्रिय है। कोई डर नहीं है कि प्रदेश में क्या घट रहा है, देश में क्या घट रहा है। रेट तय है कि 20 रूपये में देना है। इतना रूपया देना है, यह गली-गली में शोर है और चोर कौन है, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे लेकिन पूरा प्रदेश जानता है। इसीलिये मैं बोलता हूं कि 1 हजार करोड़ रूपये में 20 रूपये के इंतेजाम से कांग्रेस का चुनाव निपट जायेगा।

श्री रामकुमार यादव :- नरेन्द्र मोदी कने जाकर कोनो चाय पियत हे, तेला नहीं देखत हवव टी.व्ही. में सब ला।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, फोर्टिफाइड राइस का भुगतान भी अप्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, हमने आई.टी. पॉलिसी बनाई थी। उस समय वह देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी थी। इस सरकार ने आई.टी. में कुछ नवाचार नहीं किया है। अभी माननीय ढांढ साहब को बनाये हैं। उसमें 30 लाख रूपये है, जिसमें 20 लाख गाड़ी का है, 10 लाख में और कुछ होगा। अभी सोचना शुरू करेंगे कि आई.टी. में कुछ किया जाये तो मैं तो एक सुझाव दे देता हूं कि किसी भी विश्व स्तरीय गौठान में, पाटन में होगा या साजा में होगा। वहां आई.टी. पार्क भी बना दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, हम तो दो सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर चुके हैं। लॉट निकालकर 5 गौठान सबको घुमा दीजिये। आपने कहा भी था कि हां करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को तो विनियोग में बोलूंगा, आज नहीं बोलता। जो आदमी जेल में है, भारत नेट की 200 करोड़ रूपये की पेनाल्टी चुप-चाप टाटा को वापस की। वह मुख्यमंत्री जी का विभाग है। यह आरोप है। ऐसा करेंगे तो जेल में नहीं जायेंगे। ई.डी. के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ई.डी. के खिलाफ क्यों प्रदर्शन है, वह विनियोग में बात होगी। आज बात नहीं करूंगा क्योंकि वह किसी डिपार्टमेंट में नहीं आती, बजट में नहीं आती। आज उस विषय को नहीं बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेकाहारा के 700 बिस्तर अस्पताल के लिये 85 करोड़ रूपये रखेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज यहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। बृजमोहन जी बैठे हैं, वह माननीय सरदार जी भी बैठे हैं। आपके पक्ष में बोल रहा हूं। आज की तारीख में मेकाहारा 1300 बेड का हो गया है। मैं आपका अभिनंदन करूंगा यदि वह बिल्डिंग नई बन रही है और वह 1300 बेड के लायक हो और आप 1300 बेड के लायक उसका सेटअप स्वीकृत करें। उसका इतना विस्तार हो कि यदि चार नये डिपार्टमेंट खुलते हैं तो उसमें उसके लिये भी जगह रहे।

श्री रविन्द्र चौबे :- चंद्राकर जी, आप कितना अच्छा बोलते हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री भी थे। अंबेडकर अस्पताल गरीबों का अस्पताल है। आपने 15 सालों में एक वार्ड नहीं बना पाया। (शेम-शेम की आवाज) हमको सलाह देते हैं। एक वार्ड नहीं बना पाये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अभी जाकर देखिये 5 वार्ड एकदम चकाचक बन गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं शिक्षा मंत्री भी था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नसबंदी कांड।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं स्कूल शिक्षा मंत्री भी था, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री भी था। मैं पहले क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहता था। पहले Faculty को कम करना चाहता था। उसमें यदि आप चर्चा मांगते हैं तो मैं उसमें आपको उत्तर दूंगा। आपने जो बोला उसको मैंने अभी स्वीकार कर लिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी कांड आपके ही शासन काल में हुए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन में 2 हजार करोड़ रूपये है। उसे 31 मार्च 2024 तक पूरा होना है। अब भारत सरकार ने तय किया था कि 74 लाख 20 हजार 564 राज्य सरकार ने उसमें कर दिया 42 लाख 23 हजार 324। कल परसो उसकी बैठक थी, उसकी कार्ययोजना संपादित हो गयी होगी। उत्तर आयेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनना जरूर पसंद करूंगा कि 2 हजार करोड़ लगेगा या ज्यादा लगेगा। क्यों ? क्योंकि 3 हजार 500 करोड़ का आपका सरप्लस बजट है आपको पूरा देना चाहिए। उसकी प्रगति कितनी है? मात्र 39 प्रतिशत । यह आप जादू से करेंगे। जैसे रात भर में खाण्डव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ बन गया था, पाण्डवों के लिए बना दिया गया था, वैसे

ही मुख्यमंत्री जी कुछ जादू लगायेंगे और 31 मार्च, 2024 तक पूरा नल लग जाएगा। हम लोग छत्तीसगढ़ में जादू देखेंगे।

समय :

4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आपको 53 मिनट हो गया। आप और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बजट को पढ़ रहा हूँ और आधा छोड़ दिया हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं केवल पूछ रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ। मैं पी.एम. कुसुम योजना के संबंध में कहना चाहूंगा कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों हेतु 46 करोड़ का प्रावधान है। अब यह दोनों भारत सरकार की स्किम है। आप रिफार्म करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। 3444 करोड़ रूपये का टेण्डर हो चुका है। एक योजना 110 करोड़ रूपये की है। आप मीटर बदलेंगे, रिफार्म करेंगे। इस हेतु 46 करोड़ का प्रावधान है। उसको वर्ष 2025-26 तक करना है तो "नौ दिन चले अढ़ाई कोस"। छत्तीसगढ़ में यह रिफार्म नहीं हो सकता। इसको यह देखिए कि कौन से गौठान, कौन से नरवा, कौन से घुरूवा में हो सकता है। एकाध जगह चेंज हो सकता है। आप यह मत समझे। केवल 10 प्रतिशत सरकार को देना है। 30 प्रतिशत कौन देगा। यह दोनों स्किम है, यह क्या है ? अब उसके बाद प्रश्नोत्तरी का बता रहा हूँ इसमें 56 हजार किसान तो ऐसे हैं जिसके आवेदन की औपचारिकता पूरी हो गई है 1 लाख, 32 हजार अस्थाई कनेक्शन हैं। आप किसान के पुत्र हैं समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आप उसका क्या कर रहे हैं? एक रूपया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 150 करोड़ रूपये इंतजाम करेंगे। मैंने इसके ढक्कन को खोला कि इससे फन वाला निकलेगा तो निकल गे ढोड़िया। हम सोचे रेहन कि गउंहा डोंगी निकली करके, किसान मन बर पइसा निकलही कहिके, ता निकलिस डोढ़िया। ओ ला फूंकेल तक नइ लगे। एक गांजा के नशा होथे। का हे वहू नइ होवत हे। इसमें क्या बताया जाए?

अब मैं वन में बोलना चाहूंगा। माई लीडर वली अहद, माई मरशिद, आलिम साहब, हाफ़िज साहब, मैं आपके लिए कितने लगाऊं? मैं आपका मुरिद आदमी हूँ। भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत आधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह नवाचार तो भूपेन्द्र यादव जी का है। इसमें आपका तो कुछ नहीं है। राजस्व में भी लीडार तकनीक है। वह भी भूपेन्द्र यादव जी का नवाचार है जिसको आपने अपनाया है। सरकार, आपको बता दूं कि आप भारत सरकार की एजेंसी से नहीं करवायेंगे, न इसमें आपका कुछ चलेगा। उसकी एजेंसी तय है।

इस कार्य हेतु 187 करोड़ रूपये का प्रावधान है और 187 करोड़ रूपये में 44 प्रतिशत जंगल में जो-जो सर्वे करना है उनको थ्री डी बनाना है, वह नहीं बन पाएगा। वह ज्यादा में बनेगा, उसको रिवाईज़ किया जायेगा। यह षड़यंत्र है। उसमें भी 40 करोड़ रूपये रखा गया है उसको भी रिवाईज़ किया जाये। आप उसे देख लीजिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ यह रिकॉर्ड में है।

अब मैं मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संबंध में बताना चाहूंगा। टूरा मन भागही जेला 6-6 हजार रूपया देना हे कथे। बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। अब काबर 6-6 हजार रूपया दिही तो वह नियम कानून ला मुख्यमंत्री जी बनाही। काबर दूसरा के चले नहीं। मैं जल्दी कर देथौ, बस एक दो लाईन अउ बोलहूं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कहना चाहूंगा। हमारा आन्दोलन है इसमें बड़ी बहस हो रही है।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह किसी की बात नहीं सुनेंगे। उस दिन इन्होंने कहा कि ई.डी. लोगों की सुनना है क्या ? माननीय पुन्नूलाल मोहले जी बहुत परेशान हैं। यहां हम इन तीन लोगों का ही सुनने आएं हैं। हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में स्वीकृत मकान 151 हैं। यह मैं विधान सभा की प्रश्नोत्तरी से बोल रहा हूँ। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, मेरे प्रवक्ता क्या बोलते हैं ? आपके प्रवक्ता क्या बोलते हैं, यह अलग बात है। चलिए हम दोनों में बैठते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में डिबेट करने के लिए आप किसी भी टी.वी. को बुलवाईये। द्वितीय वर्ष भारत सरकार का जो लक्ष्य है यह 6 लाख 48 हजार 867 है। राजय सरकार द्वारा 4 लाख 91 हजार मकान की कटौती कर दी गई। वित्तीय वर्ष में केन्द्र का लक्ष्य 7 लाख 81 हजार, 999 था, इसे राज्यांश के अभाव में निरस्त करना पड़ा। इस साल 79 हजार है। 79 हजार और 1 लाख 51 हजार के लिए आप जो बजट प्रावधान किया था 582 करोड़ रूपये, कुछ 800 करोड़ रूपये, फिर 200 करोड़ रूपये, 115 करोड़ रूपये का किया है। आप उसी को लिये हैं और आप बजट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत अब तक 08 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आप डिमाण्ड मांग में बोलेंगे तो आप यह रखिएगा कि कौन-कौन से वर्ष का 08 लाख 42 हजार 289 आवास पूरा हुआ है। हम जब थे, आप बोल रहे थे न कि आपने कुछ नहीं किया, मैं उसको स्वीकार कर लिया। मै तो बोला कि मैं क्षेत्रीय असंतुलन में लगा था। छत्तीसगढ़ एक नंबर में था।

श्री अमरजीत भगत :- उसमें से केन्द्राश कितना मिलता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पता करिये, मैं आपको आरोपित नहीं कर सकता। अब हमने वह विद्वान मंत्री को अवमानना की नोटिस दी है। उस दिन उन्होंने बोल दिया कि शहरी आवास मात्र 24 प्रतिशत पूरे हुए हैं, केन्द्र सरकार का पैसा नहीं मिला है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय भाई, आप आवास के बारे में जो बोल रहे हैं, आप भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, उसमें केन्द्र सरकार का कितना अनुपात आता था?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं और हम लोगों ने अवमानना की नोटिस दी है कि राज्य सरकार का साढ़े 400 करोड़ रुपये राज्यांश का उसमें बकाया है, उसी दिन के प्रश्न के उत्तर में है। मैंने माननीय मंत्री जी को दिखाया भी और उनको आग्रह किया कि ऐसा बोलने से रोकिये, विधान सभा की अवमानना हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- आप केन्द्र और राज्य का अंश तो पहले बता दीजिए। पहले आपके समय में कितना मिलता था, आप जब मंत्री थे तो केन्द्र का कितना अंश मिलता था और अभी कितना मिल रहा है? केन्द्रांश कितना मिलता था, उसको बताईये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बैठिये, बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सर्वे की बात कही। जो देश में census लागू हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कोई अलग census नहीं बनेगा। ये केन्द्रीय स्कीम है।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो दे नहीं रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 60-40 बोल दिया हूं न। अब यह जनता को घुमाने का तरीका है कि हम सर्वे करवायेंगे और इतने दिन में सर्वे हो जायेगा। क्या छत्तीसगढ़ के लिए census बदल दिये जायेंगे ? अगली जनगणना का census जिस दिन लागू होगा, उस दिन योजनायें बनेंगी और सबके लिए बनेंगी। यह संघीय व्यवस्था है। कोई एक राज्य के लिए अलग बात नहीं होती।

श्री अमरजीत भगत :- आप सही बात बता नहीं रहे हैं। आपके समय केन्द्र का अंश कितना रहता था और आज कितना अंश है ? इसको तो आप बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब शिक्षा में दो लाईन कहना चाहता हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हर चीज का नाम बदलना और कम करना आदत बना लिये हैं।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, अभी 13 लाख आवास बने हैं, आपने अपने कार्यकाल में कितने आवास बनाये, जरा बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका बोलने वाले की सूची में नाम है न ?

श्री अरूण वोरा :- है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपके मंत्री जी को कहा न कि इसमें दोनो कोई बहस कर लेते हैं। आपने सुना है या नहीं सुना है ?

श्री अरूण वोरा :- सुना।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपने मंत्री से पूछिये।

श्री अमरजीत भगत :- बनावटी आंसू वाली जो बात है न, पहले गरीबों के लिए आवास के लिए केन्द्र सरकार कितनी अनुदान देती थी और आज कितनी अनुदान दे रही है, यह तो बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय शिक्षा में सिर्फ दो कॉलम है। विश्व बैंक के समर्थन से चॉक परियोजना प्रारंभ की जा रही है। यह विश्व बैंक की वित्त पोषण के लिए आवेदन है। ज्ञान अर्थव्यवस्था संचालन के लिए, त्वरित शिक्षण के और परामर्श सेवाओं के लिए आय का हिस्सा लागू करने का इरादा रखता है, उस देश से इसका है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह कैसे होगा ? इसके योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेना है। अभी प्रक्रिया कहां तक हुई है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंसलटेंट नियुक्ति तक है। चुनावी साल है, बजट में थपथपाने के लिए लिख दिया है, 400 करोड़ की चाक परियोजना लायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, पूरे एक घंटा हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 10 मिनट में खत्म कर देता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप इसमें तो बताईये कि गरीबों के लिए केन्द्रांश क्यों घटा ? पहले कितना मिलता था और आज कितना मिलता है, यह तो बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। स्कूल की जतन हमेशा होता था। बाउण्ड्रीवाल के लिए पैसा रहता था। समग्र शिक्षा से, उच्चतर शिक्षा से पैसे दिये जाते रहे हैं। आपने नाम भर चेंज कर दिया। मुख्यमंत्री जतन योजना शुरू की जायेगी, इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आप सभी शिक्षा के अवयवों को जोडोगे, उसके कंटेन्ट मिलाओगे तो 500 करोड रुपये से ऊपर निकलेगा। इसमें एक भी नई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क आपका विभाग है। 4000 किलोमीटर है, जो 05 साल से ऊपर हो गई, इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज भी बदनामी के साये में आयेंगे। आपकी efficiency में प्रश्न चिन्ह लगेगा। चुनावी साल में आपने सड़क नहीं बनवाई, आप ही के कार्यकर्ता पकड़ेंगे। हम लोगों को तो कोई अपेक्षा नहीं है। 3500 करोड़ रुपये का बजट, टोटल डीफिसियेशन को छोड़ दें, पर रोजमर्रा के खर्चे के लिए आप सरप्लस हैं तो इसमें क्यों कटौती हो रही है ? 800 करोड़ रुपये में लगभग पूरा मेंटेनेंस हो जायेगा। अभी बढ़वा लीजिए। आपकी efficiency में तो प्रश्नचिन्ह नहीं लगेगा। अब ये अकादमी, ये बनेगी, वो बनेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी का प्रश्न था। एक भी अकादमी को पैसा नहीं, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी का चयन नहीं, एक नौकरी नहीं दी गई। अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट अभी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसमें अपना मत स्पष्ट कर देता हूं। आखिर ये खेल है। राष्ट्र में शामिल करना है । जापानी जूडो को शामिल करना है, जापान संषर्घ करते रहा, वह ओलंपिक में शामिल हो गया। बहुत सारे खेले 1896 से ओलंपिक शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक में 22 खेल से शुरू हुआ था, वह अब 100 खेल के आसपास हो गया है। 10 तरह की तैराकी शामिल हो गई हैं। आप

हमको कहते हैं कि छत्तीसगढ़ खेल के विरोधी हैं। हम कहते हैं कि हम समर्थक हैं। आप पित्तूल खेलवाते हैं। क्या नियम-कानून होगा, कौन संघ आयोजित करेगा, कैसे आयोजित करेगा, ब्लाक स्तर में होगी, जिला स्तर में होगी, फिर प्रदेश स्तर में होगी या स्कूल स्तर में होगी? ओपन होंगे, संघ के माध्यम से होंगे, उसके संघ बना दिये जाए, उसके माध्यम बना दिये, उसके चयन प्रक्रिया बना दिया जाए।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के लोग, बच्चे खेल रहे हैं, उनका भी यह विरोध कर रहे हैं। यह 15 साल तो कुछ नहीं कर पाये। एक तो आदिवासी लोग, बस्तर के लोग, सरगुजा के लोग, महिला, बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, उनका भी यह विरोध कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ का विरोध कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पित्तूल खेलवाते हैं, गिल्ली खेलवाते हैं। आप स्वयं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। आप छत्तीसगढ़ के इन खेलों को मान्यता देकर राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में आवेदन कीजिये और उन खेलों को प्रोत्साहन तब मिलेगा जब उनके विजेताओं को नौकरियों में आरक्षण देंगे तब आप तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, वह साकार होगा। अभी क्या हो रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, यह खेल के माध्यम से दूसरे चीज में निशाना साध रहे हैं। यह उस खेल में खेल हो चुके हैं और नारायण चंदेल जी उसमें बाजी मार दिये हैं। यह out of track हो गये हैं। इसलिए यह खेल का विरोध कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- हो क्या रहा है यह मैं आपको बता देता हूं। आपकी भावनाएं सही हो सकती है। 25 करोड़ रूपये आपने दी है, 21 करोड़ रूपये पूरक में दिया, 32 करोड़ रूपये आपने राजीव गांधी मितान क्लब को दिया, 72 लाख रूपये महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए दिया, फिर 70 लाख रूपये दिया गया, यह सारे सर्कुलर हैं। अब खेल के नाम पर कितने कैंप, कितने काम हो रहे हैं, यह खेलो इंडिया नहीं है, यह खाओ इंडिया हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा पढ़ देता हूं। यदि आप करना चाहते हैं तो वह व्यस्थित हो, यदि नहीं तो इसको गम्मत माना जायेगा। राजनीति इसी को कहते हैं। यदि हम व्यवस्थित नहीं करना चाहते। कोई भी आयोजन करवा रहे हैं। हम उदाहरण क्या देते हैं कि 69 साल की एक बुजुर्ग महिला ने जीता। भैया, जीता तो उसको पेंशन दे दो। आपने अच्छा किया है। हम कहां विरोध कर रहे हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि आप इसको व्यवस्थित करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यटन, संस्कृति को खोल लेता हूं, वाणिज्य एवं उद्योग को बंद कर लेता हूं। मैं आपको उद्योग विभाग में बता देता हूं। उद्योग में भी वृद्धि दर्शाये हैं। आपके जितने एम.ओ.यू हुए हैं। 6 में आंशिक रूप से काम शुरू हुआ है। जो एफ.डी.आई. आई है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख पढ़ा था, उसमें जो एफ.डी.आई. आई थी, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक राज्य प्रथम थे।

इंडियन एक्सप्रेस में एफ.डी.आई. में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। आप कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, आप कट मनी को रोकेंगे नहीं, आप उसके लायक माहौन बनायेंगे नहीं। एम.ओ.यू. में प्रति टन जो सौदा हुआ है, वह सभी जानते हैं। मैं आपको किसी भी उद्योगपति से मिलवा दूंगा। जितने टन हैं। एम.ओ.यू. में प्रति टन कितना पैसा देना पड़ा। उसमें सभी को बता देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं संस्कृति विभाग में एक बात बता देता हूं। मैं हृदय से एक लाईन में आपकी प्रशंसा कर देता हूं। आप खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफ कैम्पस खोलें। मैंने दो नये सब्जेक्ट चालू किया था, जिसमें थियेटर शुरू हो गया। बम्बई में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लड़के थियेटर से निकलकर चले गये। मैं आपको बता देता हूं कि फैकल्टी लाने भी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया था। जो आज का एनिमेशन सब्जेक्ट है, जितने आजकल कार्टून बनते हैं, उसको भी मैंने बजट में स्वीकृत किया था। ऑफ कैम्पस में उसकी फैकल्टी इतनी महंगी है कि हवाई अड्डा से उतर कर काई खैरागढ़ जाने को तैयार नहीं था, उस समय के विधायक और सांसद जो भी थे, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने विरोध किया कि हम ऑफ कैम्पस नहीं खोलेंगे, यह हमारी गरिमा का सवाल है। आपने हिम्मत दिखाई और एशिया के इंस्टिट्यूट में एक नये सब्जेक्ट आयेंगे, मैं यह एक ही चीज के लिए आपको बधाई दे देता हूं। अब आपने सिरपुर के लिए जो 5 करोड़ रूपये रखा है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मैंने बनाया था। आपने सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति की। मैं आपको बता देता हूं, सलाह दे देता हूं। वैसे आप तो स्टेटमेन हैं। आप सब सलाह से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी हिमाकत कर देता हूं कि पर्यटन को, सी.जी.एम.एस.सी. को, साडा को, यह सिरपुर वाले को पेशेवर हाथ में रखिये। राजनीतिक हाथ में मत रखिये । अटल श्रीवास्तव जी मेरे भी मित्र हो सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए । भाजपा से भी जो लोग थे, पुराने पर्यटन मंत्री जी सामने बैठे हैं । मैंने कहा था कि यह पेशेवर लोगों का काम है, पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है यह नीति बनाना लेकिन 5 करोड़ रूपये आपने दिये हैं । आपको मालूम है न कि आज तक संग्रहालय नहीं बन पाया । सिरपुर भी भारतीय पुरातत्व संघ की जगह में बसा है । 156 टिले हैं, 11 बौद्ध संघ ने खोदवाया था बाकी 27-28 हमने खोदवाया। आपने घुमाया, खोदवाया मुख्य रूप से था कि उसको रिहेबिलिटेट करें, हमने इंटेक के साथ समझौता किया था ।

संसदीय सचिव, लोकस्वास्थ्य मंत्री से संबद्ध (श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर):- अजय भैया आप सिरपुर के बार गे हओ गा ? 15 साल में के बार सिरपुर गे हओ ? भैया हा 4 साल मा 3 बार चल दिस ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब मैं हा ऐला ऐती के ओती बोल दूहूं ता गडबड़ हो जाही । विनोद तोला समझ मा नइ आये तें हा बईठ जा ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- मोला समझ में आथे, मोला तोर से सर्टिफिकेट ले के जरूरत नइ हे।

श्री अजय चंद्राकर :- नइ आए, तें हा बइठ जा ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- नइ-नइ । आप ला समझ में नइ आए ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा मैं बइठ जथओं चल ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- सिरपुर के उद्धार करे बर ना भैया हा 3-3 बार जा के आ गे हे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, टोका-टाकी न करें ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- आप 15 साल में एको बार नइ गे हओ । आप एक-बार राहूल गांधी जी के बात करत हओ, ओकर पहिली के बर जा के आ चुके हे, 3 बार ।

श्री अजय चंद्राकर :- होगे न ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- स्वत: सबो जगह घूमकर आये हे अकेला ।

श्री अजय चंद्राकर :- बोल डरेस न । माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड विरासत, विश्वविरासत वह बने । रिहेबिलिटेशन के लिये योजना बने ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं । अब इसके बाद आप पर्यटन में आदिवासी महोत्सव करवाते हैं, बढ़िया है । एक महोत्सव स्थापित हो रहा है, यह मान लें । मैंने सिरपुर महोत्सव शुरू करवाया था, आपने बंद करवा दिया । एक भी स्थापित महोत्सव छत्तीसगढ़ में नहीं है ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- भैया, तें हा फिर गलत बात बोले हस । कहां सिरपुर महोत्सव बंद होए हे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- मैं उसके उद्घाटन में गया था । (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- आप गलत उदाहरण पेश मत करिये न । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- एक बात बोल देता हूं कि यह अक्ल वाली बात समझ में नहीं आयेगी । (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- नहीं-नहीं, गलत बात मत बोलिए । असत्य मत बोलिए । सिरपुर महोत्सव अभी भी चालू है, चल रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यदि मैं उत्तेजित हो गया तो आप नये विधायक हैं, फंस जाओगे ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- हम तो बोल रहे हैं न कि चल रहा है करके ।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय भाषा बोलना सीखो । (ऊंची आवाज में बोलने पर) (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की विरासत और परंपरा इतनी समृद्ध है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अंदाज में इन्होंने बोला, वह अंदाज गलत है । (हंसी) नये सदस्य हैं और संसदीय सचिव हैं । चुनाव जीतकर आये हैं, वे अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे । इतना गलतबयानी कर रहे हैं कि आजतक वहां गये नहीं करके और 3 साल से तो वहां लगातार मैं जा रहा हूं ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषा उपयोग किया उसको विलोपित किया जाये । वे चुनकर आये हैं, नये हों चाहे पुराने हों । उनको डांटने का अधिकार नहीं है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- ये क्या शिक्षा दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या वहां के लिये कुछ कर रहे हैं, यही बता दीजिये । वहां जा तो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हम भी कर रहे हैं, पहले क्या हुआ है ? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- हां, आप ही कर रहे हैं । उसी को पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं तो उसको बता दीजिये न । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 चुनाव तो हम भी लड़ चुके हैं लेकिन जब इतनी जोर से बोलते हैं तो हमारी छाती भी धड़धड़- धड़धड़ करती है । (हंसी) इतनी जोर से किसी ने नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी समाप्त करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पुरखौती मुक्तांगन उसमें एक रूपये नहीं दिये । हम उसको विश्व का सबसे बड़ा खुला मानव संग्रहालय बनाना चाहते थे । आप कोरिया विरासत की महल की रेप्लिका बनवा रहे हैं उसको बताईये कि उसका छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है ? आप सोनाखान की रेप्लिका बनवाते, फांसी के फंदे की या उस कालकोठरी की जहां उनको रखा गया था तो मुझे समझ में आता । सरगुजा खंड में क्या- क्या होना चाहिए ? बस्तर खंड में क्या-क्या होना चाहिए ? मध्य खंड में क्या-क्या होना चाहिए ? छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कौन से खंड होने चाहिए ? छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में कौन-कौन से खंड होने चाहिए ? और यदि उनको खुला मानव संग्रहालय समझ में नहीं आता है तो मैं आपको डिमांड मांग में सुझाव दे दूंगा । यदि आप करना चाहेंगे क्योंकि मैं आपसे दुखी हूं । एक हिंदी ग्रंथ अकादमी खोले थे, आप छत्तीसगढ़िया का नाम लेते हैं । पूरे छत्तीसगढ़ के प्रकाशकों के लिये एक जगह नहीं है । ताला लग गया, ताला तोड़ने वाला भी पैसे में नहीं तोड़ पायेगा इतना मजबूत ताला वहां लगा है और अंत में पर्यटन की जहां तक बात है । माननीय हमारे

अकबर जी नया अभ्यारण्य खोल रहे हैं। पर्यटन की बात है। गृह मंत्री जी नहीं हैं। जितने अपराध हो रहे हैं। अपराधियों का नया अभ्यारण्य बन रहा है, आप क्यों कवर्धा में नया अभ्यारण्य बना रहे हैं? लॉ एण्ड ऑर्डर, सड़क की दुर्घटना रोकना, आत्महत्या को रोकना इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। लॉ एण्ड ऑर्डर में मैंने अभी ट्वीट किया है सेल्फी विथ गृह मंत्री। लोगों को पता चले कि गृह मंत्री है। जो सोता नहीं है, कुंभकरण की तरह है, जिसका कपाट बद्रीनाथ या केदारनाथ की तरह बंद नहीं रहते, वह जागृत है। 24 x7 एक्शन में है। दुर्भाग्य है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा भाई, प्रधानमंत्री सेल्फी ले तो अच्छी बात है। हमर गृह मंत्री हा ले लेहे तो अपराध होगे। कुछ भी बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह दुर्भाग्य की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने सूचकांक को आप देख लो, भारत देश की 15 प्रतिशत से ज्यादा जब खर्च हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के निर्माण में, विनिर्माण में सबसे बड़ी भूमिका भारत निभाएगा। स्वास्थ्य के सूचकांक में, आवास के सूचकांक में, जल-जीवन मिशन के सूचकांक में जो स्वतंत्र एजेंसियां कर रही हैं, उसे देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी अपने आपको छत्तीसगढिया कहते हैं। इस बजट में किस चीज में उसकी झलक दिखती है?

श्री अमरजीत भगत :- तोला शक हे का?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने सेट-अप बताया। पूंजी, कृषि के लिए क्या दिया है? बीज के लिए क्या दिया है? सिंचाई के लिए क्या दिया है? शिक्षा के लिए 2 लाइन है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना आएगी और चॉक योजना आएगी। 700 बिस्तर अस्पताल अभी तक दर्ज है। संस्कृति में तो बहस करना बेकार है। पर्यटन में बहस करना बेकार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- संस्कृति में नंबर वन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस प्रदेश में दोनों में यदि एफ.डी.आई. के लिए यदि वातावरण बनाना है तो उत्तरप्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार, दक्षिण की सरकार बड़े कंसल्टेंट नियुक्त कर रही हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर तक कैसे जा सकती है? ट्रिलियन रूपये तक कैसे जा सकती है? हम क्या स्रोत पैदा कर सकते हैं? हम यदि केन्द्र सरकार को कोसते हैं, एक राजनीतिक धर्म हो सकता है, लेकिन जो परिदृश्य है देश में कर संग्रह में जी.एस.टी. के बाद ..।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन हम भारत सरकार को देख रहे हैं कि 4-5 उद्योगपतियों को ही उठाने का प्रयास कर रही है। ऐसी आपकी व्यवस्था है। इस देश का भला नहीं कर सकता। इसे हम देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. लागू किया है। जी.एस.टी. लगता है तो पता नहीं रहता कि किसमें कितना लग रहा है? जी.एस.टी. लगता है तो किसी को पता नहीं रहता कि कितना प्रतिशत जी.एस.टी. लगा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इनसे शिक्षा नहीं चाहिए। ये अडानी और अंबानी को उठाने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार की तारीफ की बात कर रहे हैं। मिलियन और ट्रिलियन की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें हमको नवाचार करना होगा। सोचना होगा। विश्व की प्रतिभाओं को आमंत्रित करना होगा। उसके लिए वातावरण बनाना होगा। छत्तीसगढ़ महातारी की ये सेवा होगी। ये नहीं होगी कि गौठान समिति के अध्यक्ष को इतना रूपया। सोसाइटी के अध्यक्ष को इतना रूपया। मंडी के अध्यक्ष को इतना रूपया। राजीव गांधी मितान क्लब को इतना रूपया। ये रेवड़ी कल्चर। अब एक लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, हमने किसानों को दिया है, वह भी आपके लिए रेवड़ी है। सब चीज रेवड़ी है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने उसे रेवड़ी नहीं कहा। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मोबाइल और टिफिन की भी बात कर लीजिए। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- मोबाइल और टिफिन। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मोबाइल और टिफिन का क्या हुआ? (व्यवधान) चुनावी साल में मोबाइल बांटना, याद है या नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठ जाइए। अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप लोगों ने किसानों को क्या दिया? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने किसानों को पैसा दिया क्या ? एक भी बार दिया क्या? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, शांत हो जाइए। बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- स्वाथपूर्ण बंटवारा तो आपने किया। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने इस्तीफा दिया क्या? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इन्होंने कहा था कि किसानों को पैसा मिलेगा तो इस्तीफा दूंगा। आप इस्तीफा दिये क्या? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कर्जा माफ हुआ तो इस्तीफा दूंगा बोले थे आप। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय जी, अब मैं अपनी अंतिम बात बोलूंगा। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय जी, इनका टाइम पूरा हो गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यू पेशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। मोंटेक सिंह अहलूवालिया 10 साल तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। देश को जिन्होंने उदारीकरण दिया, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए जिसने खोला, ये सोना बेचने वाला देश आज सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक तौर पर और तात्कालिक रूप से फायदामंद हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वह राज्य दिवालिया हो जायेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं।

श्री कवासी लखमा :- एल.आई.सी. का क्या हो रहा है, उसको भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- एल.आई.सी. वालों का सब पैसा डूब गया। आप शिक्षा बांट रहे हो। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- उदारीकरण का साल तो बता दीजिए कि उदारीकरण कौन से वर्ष में हुआ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जिनका खून-पसीने की कमाई डूब रही है, उसे बताओ। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- पैसा डूबता जा रहा है, उसको बताओ। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जितने कर्जे वर्ष 2026-27 में मैच्योर हो रहे हैं..।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें। अब अनुमति नहीं दूंगा।

चलिए, श्री शैलेश पाण्डे जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, वर्ष 2026-27 में मैच्योर हो रहे हैं। जो आने वाली सरकार है, वह सिर्फ कर्जा पटाएगी, उसके लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है और न ही कोई नीति है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि पहले अपनी सरकार की बात कहूं या इनके [xx][6] का जवाब दूं। लगभग एक घंटा 20 मिनट तक [xx] बोला गया । पूरी रिकॉडिंग हुई ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी, शुरूआत तो ठीक से करो, [xx] नहीं असत्य बोलो भाई ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं सुधार करता हूं असत्य । असत्य बोला गया । उस असत्य में सब लोग हँस रहे थे, एक व्यक्ति सूट नया वाला सूट पहनकर आया ।

[6] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पांडे जी, आपके सच को हम लोग मानते है । आपने सरकार के सच को एकदम रख दिया कि रेट फिक्स होना चाहिए । हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं सच ही बोलता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप डायरेक्ट बात मत कीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपके घर चोरी हुई ना ? यह भी सच है ना ? चोर अभी नहीं पकड़ा गया ना ? आप चिंता नहीं करना अभी पकड़ा जाएगा । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी बढ़िया सूट बूट पहनकर आया । हमने क्या देखा कि वह यहां से फटा हुआ है, इधर से फटा हुआ है, जेब छोटी हो गई है, हम केवल यही देख पाए । हमने उस सूट की तारीफ नहीं की । हमने उस चरित्र की तारीफ नहीं की। हमने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया, हम केवल यही देखते रहे कि इसकी जेब फटी हुई है, इसकी पैंट की लम्बाई कम है, इसकी हाथ की लम्बाई कम है । यही सब बातें सवा घंटे से चल रही थीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, जैसे चार साल से बिलासपुर के गड्ढे आप देख रहे हो ना, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो ?

श्री शैलेश पाण्डे :- हम तो 4 साल से नहीं, 2008 से देख रहे हैं और मैं ही नहीं देख रहा हूं, पूरा विश्व देख रहा है । पूरा विश्व देख चुका है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या कर रहे हो चार साल से बता दो । चार साल से पाट पाए क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं ही नहीं देख रहा हूं, पूरा विश्व देख रहा है । वह जो दर्जनों आत्माएं जो यहां से सिधार कर ऊपर चली गई हैं ना, वे सब भी आपको देख रही हैं, पता नहीं आगे क्या-क्या होने वाला है ? उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है । उसका अपना सपना होता है, वह प्रदेश की स्थिति, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्रदेश की सामाजिक स्थिति, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश को कहां लेकर जाना है इन सबको देखकर बजट प्रस्तुत किया जाता है । आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में कोई आई.ए.एस. नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक किसान के बेटे ने 1 लाख, 21 हजार करोड़ का बजट पेश किया, यह बड़ी बात है (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री रामकुमार यादव :- वह भी बिना उधारी के ।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह कितनी बड़ी बात है । आज यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है । छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए गौरव की बात है कि इतना बड़ा बजट एक किसान के बेटे ने प्रस्तुत किया, यह छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात है (मेजो की थपथपाहट) । हमने 1 लाख, 21 हजार करोड़ का बजट पेश तो किया ना। यह कोई असत्य नहीं है । आपने 15 साल क्या किया था, आपने 15 साल बजट पेश किया, जो भी बजट पेश किया, आप 15 सालों तक बजट पेश किया । लेकिन आज जो बजट पेश हुआ जिस अनुमानित राशि का बजट पेश हुआ । क्या इससे पहले इतना बड़ा बजट पेश हुआ था ।

19 साल तक नहीं हुआ, आज 20वें साल में आपने किया । आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को गौरव दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- वही सदन अउ वही अधिकारी करे हे ।

श्री शैलेश पाण्डे :- ये आई.ए.एस. नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, वह किसान है । आज सदन में उन्होंने यह बजट पेश किया है तो इससे पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का मान बढ़ाया है (मेजो की थपथपाह) । मैं दूसरी बात पर आता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख, 21 हजार, 500 करोड़ का जो बजट पेश किया है उस बजट में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 17 प्रतिशत वृद्धि की है । यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है । आय के स्रोतों में 17 प्रतिशत की वृद्धि है तभी यह बजट प्रस्तुत हुआ है और जिसमें राज्य सरकार की 56 हजार 200 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हैं, केन्द्र सरकार की 49 हजार 800 करोड़ रूपए प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां 15,500 करोड़ रूपए है। इस प्रकार टोटल यह बजट 1 लाख 21 हजार करोड़ का है।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, वह पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है, 15 हजार करोड़ लोन है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपका नाम भी लिखा हुआ है, नंबर आएगा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम व्यय की बात करते हैं। हमारे आदरणीय सीनियर सदस्य ने बातें बताई। अगर राजस्व व्यय की बात करते हैं तो 84.64 प्रतिशत जो है, यह हमारा राजस्व व्यय है। यह हमारी जिम्मेदारी है। पूंजीगत व्यय लगभग 15.36 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय लगातार पिछले पांच सालों से लगभग 15 प्रतिशत के आसपास प्रस्तुत हुआ है। मैं यहां पर उल्लेखित करना चाहता हूं। आप पूंजीगत व्यय के पीछे पड़ गये। आप आडिटेड रिपोर्ट बताते रहे, आप हमारी आडिटेड रिपोर्ट बता रहे हैं, आप अपनी 15 साल की आडिटेड रिपोर्ट बताईए। आप कर क्या रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ? आप आडिटेड आंकड़ा अलग बता रहे हैं और अनुमानित आंकड़ा अलग बता रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, आप बनेंगे या हम बनेंगे, हम अनुमानित डाटा ही देंगे, आडिटेड डाटा बाद में पेश होता है। मैं आपका भी 15 साल का डाटा रख सकता हूं, मेरे पास डाटा है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। आपके समय प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपके समय छत्तीसगढ़ की डिमांड कुछ और थी, हमारे समय में छत्तीसगढ़ की डिमांड, मांग और जरूरतें कुछ और है। अगर हमारे देश में सबसे बड़ा कोई काम है, मैंने उस दिन भी राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा था, आज फिर उस बात को उल्लेखित करता हूं। हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई काम किया जाता था तो वह केवल खेती ही हुआ करता था। उस जमाने में खेती करने वाले व्यक्ति को उत्तम माना जाता था, नौकरी करने वाले व्यक्ति को निम्न माना जाता था, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को मध्यम माना जाता था। आज परिस्थितियां बदल गयी हैं, आज शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है। आज हर वर्ग शिक्षित हो चुका है, आज हर मॉ चाहती है कि उसका बेटा, कलेक्टर बने, एस.पी. बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यह बने, वह बने। लेकिन आज भी अगर

छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा व्यवसाय है तो वह व्यवसाय कृषि ही है। आदरणीय सौरभ भैया, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फीगर की बात करते हैं, अगर हम बाहर के देशों में इस बात को जाकर देखें तो विदेशों में किसान खत्म होते जा रहे हैं। वहां पर कृषि को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। कार्पोरेट कल्चर, अमेरिकन कंट्री और यूरोप कंट्री में कृषि प्रधानता को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है और जो स्कील वर्कर है या मजदूरी कह लीजिए, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन हमारे देश में यह नहीं हो सकता है। हमारा देश भौगोलिक रूप से भी दूसरा है, हमारा प्रदेश भी भौगौलिक रूप से दूसरा है। आज हमारे प्रदेश की जो जरूरत है, वह जरूरत कृषि पर ज्यादा है। आपने भी काम किया था, हम नहीं कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। हम अभी आपका आंकड़ा बताते हैं। आप हमारा आंकड़ा भी देख रहे हैं, हम आपका भी आंकड़ा बता रहे हैं। आपने भी कृषि पर ध्यान दिया लेकिन आपने उतना ध्यान कृषि में नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्यों किया, इसलिए किया, क्योंकि यह हमारी जरूरत थी, यह हमारे प्रदेश की जरूरत थी। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक रूप से यह आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं अभी आपको जी.एस.डी.पी. का आंकड़ा बताता हूं। अगर आप जी.एस.डी.पी. का आंकड़ा देखेंगे। वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार का जी.एस.डी.पी. 6.5 प्रतिशत, हमारा जी.एस.डी.पी. 6.65 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 में 7.2 प्रतिशत, हमारा 6.08 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत था, हमारा 5.32 प्रतिशत था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो, वर्ष 2020-21 का आंकड़ा था, जो जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. की बात करते हैं, केन्द्र सरकार का -7.7 प्रशित था जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस घाटे को रोका, वह घाटा कैसे रूका, इस बात को सोचा है ? हमारे समय में जब केन्द्र सरकार का जी.एस.डी.पी. -7.7 प्रतिशत था, तब हमारे प्रदेश का जी.एस.डी.पी. -1.7 प्रतिशत था। क्यों, क्यों ऐसा हुआ है, हम किस प्रकार से बचा पाए, इसको सोचने की बात है। इसलिए बचा पाए कि जिस पर हम सबसे ज्यादा नाज करते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा अपनी बात का प्रचार करते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हैं, वह बात अगर है तो वह छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसे हम पेश करते हैं। उसके कारण यह सब होता है। लोग निंदा करने लगते हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल ये हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिंका हो रहा है, आप इसकी बात कर रहे हैं। आप आगे जाकर अपने प्रदेश की गरिमा को बढ़ाईए ना। आप आगे जाकर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? यह आपका काम है। आप छत्तीसगढ़ के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। आपको छत्तीसगढ़ का सम्मान, अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए। आपको केन्द्र में जाकर छत्तीसगढ़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपने प्रदेश की गरिमा को कभी नहीं बढ़ाया, उल्टा कितना घाटा हो सके, कितना हमारा अनुदान कम हो सके, कितना हमको कम कर मिल सके, आपने यह काम जरूर किया। आप वही को नहीं किये और बहुत सारे काम किये। आपको सिर्फ यही दिखता है कि जल जीवन मिशन में यह हो गया, फलाने में आपने यह कर दिया, ढेकाने में आपने यह कर दिया। आपको इतना ही दिखता है। आपको छत्तीसगढ़ की व्यवस्था, छत्तीसगढ़ के विकास

से कोई लेना-देना नहीं है। हम एक-एक बिंदु पर आएंगे। हम एक-एक बिंदु पर बात कर सकते हैं। आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जितनी बातें बोली हैं उनके एक-एक बिंदु का जवाब दिया जा सकता है। आप अपने आंकड़े सामने रखिये और हमारे आंकड़ें भी सामने रखिये। आप अपनी व्यवस्था दिखाइये और हमारी व्यवस्था दिखाइये। आप हमारे काम देखिये और आप अपने काम बताइये। आपने कितने स्कूल खोले? आपने कितने बच्चों को पढ़ाया? आपने छत्तीसगढ़ का स्तर कितना बढ़ाया? आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए क्या किया? आप बताइये? आप यह भी बताइये कि आपने छत्तीसगढ़ को क्या बनाकर रखा था?

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक कोई भी काम बिना पैसे के होता ही नहीं था। हर आदमी जुगाड़-पानी करने में लगा हुआ था। आपके पहले पांच साल कैसे गुजरे? आपके पहले 5 साल सिर्फ बदले की भावना में गुजरे। आप 5 साल तक यही करते रहे कि उनकी सरकार में यह होता था कि इसको पकड़ो, इसको ठीक कर दो, उसको पकड़ो, उसको ठीक कर दो। यह उनका आदमी है, वह उनका आदमी है। आप पहले 5 साल तक यही करते रहें और आपने बचे हुए समय में आप शुरूआत के ढाई-तीन साल तक मकान-बंगले बनाते रहें और कुछ नहीं हो रहा था। आपको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही थी। फिर आपको किसी ने आइडिया दिया कि आप चाऊर वाले बाबा बन जाओ। आप थोड़ा चावल बांटिये। आप ऐसा करो, वैसा करो। यह सब चलेगा। आप मोबाइल वगैर: बाद में अपने तीसरे कार्यकाल में बांटे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि इस सरकार के मुखिया आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, पता नहीं वह इस विधान सभा सत्र में किसी को पॉवर ऑफ अटार्नी देकर कहां म्यूट मोड में चले गये हैं। वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि 1 साल कमीशन नहीं खाओगे तो 30 साल तक सरकार बनी रहेगी। उन्होंने रायगढ़ में यही बात कही थी।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, कहां माने।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसका प्रमाण दिया। आपने अपनी सरकार को प्रमाणित किया है। यह मुख्यमंत्री जी की बात थी। उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि आप कमीशन के बिना जी नहीं सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ को कमीशन का अड्डा बना दिया था। आपने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। चंद्रा जी कहां चले गये?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- 10 गुना ज्यादा चल रहे थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय प्रमोद भाई, आपके क्षेत्र में तो केवल और केवल आबकारी विभाग की ही समस्या है, बाकी सब ठीक है। सबसे पहले आप यह बताइये कि 36 हजार करोड़ रूपये का जो धान घोटाला हुआ था, वह क्या था? आपके जमाने में जो घोटाले हुए, क्या आपने कभी इसका जवाब दिया?

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव आता था तो राशन कार्ड बनते थे और चुनाव खत्म होता था तो राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता था। क्यों? आपने कितने लोगों को अन्न दिया और कितने लोगों को राशन दिया? आपने अपनी पीठ तो बहुत थपथपाई। आपने देश में पी.डी.एस. सिस्टम के लिए बहुत पीठ थपथपाई। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह जाकर बहुत पीठ थपथपाई। लेकिन यदि आप अंत में देखेंगे तो आपने कितने लाख परिवार को अन्न दिया? आप केवल बी.पी.एल. परिवार को अन्न देते थे। 54 लाख, 56 लाख, 57 लाख राशन कॉर्ड का जो भी फिगर था, आप केवल उतने परिवारों को उसमें रखते थे। आपके इतने लाख राशन कॉर्ड थे, लेकिन इतने परिवार नहीं थे और वह भी केवल।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, एमन जो नून देवय, तेहा बासी मा नइ घुरे।

श्री शैलेश पाण्डे :- हां।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे जी, जब आप भ्रष्टाचार वाली बात बोल रहे हैं तो आप यहां पर गीता की कसम खाकर बोल सकते हैं। आप भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी-बड़ी बात बोल रहे हैं। आप यहां पर गीता की कसम खाकर बोल सकते हैं कि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।

श्री शैलेश पाण्डे :- क्या?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है करके।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप ही लोग खाइये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप लोग गीता की कसम खाकर बोल दो।

श्री शैलेश पाण्डे :- ऐसा है कि हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि पहले आप इसको देखिये कि 15 साल में क्या-क्या हुआ और उस 15 साल को बदलने में, उन चीजों को खत्म करने में हमें समय लगेगा। हम यह नही कह रहे हैं। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने आपसे यही कहा है कि आज सदन में बात हो रही थी। मैंने भी इस बात को कहा, माननीय धर्मजीत भैया और आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी इस बात को कहा कि बिलासपुर में 193 करोड़ रूपए की सीवरेज परियोजना थी, जिसको बढ़ाकर 423 करोड़ रूपए कर दिया गया था। मैं सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 193 करोड़ रूपए की योजना 423 करोड़ रूपए की योजना हो सकती है क्या ? कैसे हो जाती है, आपने इसके पीछे कैसा जादू किया ? जब आपने बिलासपुर के ड्रेनेज सिस्टम की 193 करोड़ की योजना बनाई थी तो आपको पता नहीं था । मूल्य में वृद्धि होती है, ब्रीज में या किसी काम में 10-15 करोड़ रूपए की वृद्धि होती है । आप भी 15 साल मंत्री रहे हैं, आपको भी पता है, लेकिन 193 करोड़ की योजना 423 करोड़ की योजना हो जाएगी । ऐसा जादू कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती, वह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- पांडे जी, जिस दिन से आप विधान सभा के सदस्य बनकर आये हैं, तब से आपके भाषण में सीवरेज के बारे में 400-800 करोड़ रूपए की बात हम लोग सुन रहे हैं । अभी 4 सालों से आपकी सरकार है, इन 4 सालों में आपने जांच क्यों नहीं करवाई, इसका उत्तर दीजिए ।

श्री शैलेश पांडे :- करवाएंगे । आज जांच की घोषणा हुई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चला, चली की बेला में जांच की घोषणा करवा रहे हैं ।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय शिवरतन भैया, हम लोग आपके 15 सालों के पापों को ढो रहे हैं । मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है ।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, ड्रेनेज सिस्टम को आप धन्यवाद दे दो, नहीं तो आप विधायक नहीं बन पाते ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शैलेश जी, एक मिनट । माननीय सदस्यों के लिए स्वलपाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें ।

श्री शैलेश पांडे :- उपाध्यक्ष महोदय, दर्जनों लोग मौत के घाट उतर गए । इस प्रदेश के चीफ जस्टिस ने बिलासपुर शहर के बारे में बयान दिया था कि सीवरेज परियोजना के चलते हुए मेरा मन बिलासपुर आने का नहीं करता, शहर में घुसने का मन नहीं करता, शहर में जाने की इच्छा नहीं होती । यह कितनी बड़ी बात है । आपने बिलासपुर शहर को इतना खोद-खोद के रख दिया था । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस पूरे मामले को जानते हैं, वे जांच कर ही रहे हैं कि इनकी सरकार आई, उसमें सीवरेज के गड्डे खोदे गए, गड्डे खोदने के बाद उसकी भराई रेती से करनी थी, वह रेती से नहीं की गई, वह मिट्टी से की गई । यह वर्ष 2008 की योजना थी और 4 सालों से सड़कों को खोद-खोदकर बना दी, मिट्टी से पाट दी गई, जब 2014 में बिलासपुर की सड़कें धंसने लगी, बिलासपुर की सड़कें अचानक धड़ाम से धंस जाती हैं, बिलासपुर में सीवरेज के कारण बहुत खतरनाक स्थिति है । वह गड्डे बनती गई, धंसाई होती गई, तब इनको समझ में आया कि हमने सड़कों की भराई मिट्टी से कर दी है । आप फाईल उठाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि रेती खरीदने के लिए 30 करोड़ रूपए का बजट फिर से और लिया गया कि हमसे गलती हो गई । बिलासपुर की जनता को इस बात को नहीं बताया गया। बिलासपुर शहर मतलब संभाग का मुख्यालय है । सरगुजा, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा से भी लोग आते हैं। सड़कें आज भी धंस रही हैं, क्यों धंस रही हैं ? क्योंकि आपने 6 साल तक खोदा, खोद-खोदकर आपने मिट्टी डाली, आपको नहीं पता था । आप उसकी टेक्निकल डिजाईन नहीं समझ पाये, जिस सामग्री की जरूरत थी, वह आप समझ नहीं पाये । आपने किस कम्पनी को ठेका दिया, आपने किन [xx] को, [xx] को ठेका दिया, आप बताईए कि आपके अधिकारीगण [xx] थे, आपके सलाहकार कौन थे, कौन सचिव थे, उस वक्त डायरेक्टर कौन थे, उस वक्त नगर निगम में कौन थे ? आपको किसने कहा था कि शहर में

मिट्टी भरनी है ? आप जांच क्यों नहीं करते ? 2008 से लेकर आज 2023 आ गयी है, बिलासपुर की सड़कें धंसती हैं, बिलासपुर में आज भी गड्डे हैं । परसों आदित्य वैष्णव नाम के 17 साल के बच्चे की मौंत हुई । 17 साल का बच्चा क्या होता है, यह माताएं बैठी हुई हैं, इनसे आप पूछिए । 17 साल के बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा करते हैं । वह मामा के घर होली खेलने गया था, मेरे ही क्षेत्र में बंधुआ पारा में उसका पिता रहता है और मेरे ही क्षेत्र में दूसरी जगह उसका मामा रहता है, वहां पर होली खेलने गया, उसको पता नहीं था कि वहां सीवरेज का गड्डा है । वह गड्डे में गिर गया । वहां बड़ी-बड़ी राडें उसकी सिर में घुस गईं ।

श्री ननकीराम कंवर :- एक मिनट। इस विषय पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? आपको वहां पर धरने पर बैठ जाना चाहिए था कि यह काम जल्दी पूरा हो।

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- जब आपकी सरकार थी, तब ऐसा होता था। आपको बैठना पड़ता था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार में हम लोगों को धरने में बैठना पड़ता था, धरने से ही काम हुआ है।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं धरने में बैठ जाता। अगर मेरे क्षेत्र में होता तो बतला देता कि सरकार कैसे काम करती है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि यह सीवरेज काण्ड सिर्फ बिलासपुर का काण्ड नहीं है, यह केवल छत्तीसगढ़ का काण्ड नहीं है, यह सीवरेज का काण्ड हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा काण्ड है, जिसमें ना जाने और कितने लोग मरेंगे, कितनी गाड़ियों की दुर्घटना होगी, कितना गड्ढा-गड्ढा करते हुए उसमें क्या-क्या पाप दफन किया हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इनकी सरकार का पाप बता देता हूं कि 235 किलोमीटर सीवरेज लाईन है, उसमें गंदा पानी या कोई सा भी पानी जायेगा। उसमें मात्र एक किलोमीटर हाइड्रोलिक टेस्टिंग हुई है। क्यों 1 किलोमीटर की टेस्टिंग हुई है ? अगर आप 235 किलोमीटर सीवरेज में पानी जायेगा तो 235 किलोमीटर सीवरेज की टेस्टिंग क्यों नहीं कर पाये ? आप केवल 235 किलोमीटर में केवल 1 किलोमीटर की टेस्टिंग की ? टेस्टिंग क्यों नहीं कर पाये ? इन्होंने भ्रष्टाचार की, यह इनका एक और भ्रष्टाचार था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं के समय में नसबंदी काण्ड हुआ। उनका क्या दोष था ? यह आपकी योजना थी, सरकार की योजना है कि महिलाओं की नसबंदी की जायेगी, यह सरकार की योजना है। तो उस पर सरकार क्या दायित्व होता है। आप चूहामार दवा खिला देंगे, क्या सरकार का यह दायित्व होता है ? सरकार का यह दायित्व नहीं होता है। हमारे प्रदेश में आपकी सरकार किस प्रकार की सरकार थी, जिम्मेदार सरकार थी या लापरवाह सरकार थी ? आपकी सरकार ने महिलाओं को क्या दवाईयां दी,

उनकी कैसे नसबंदी की गई, किस गंदे स्थान में की गई और उसके बाद 12-15 महिलाओं की मौत हो गई।

श्री रामकुमार यादव :- आंखी के आपरेशन होइस हे महाराज, ओखर आंखी दिखबेच नइ करिस।

श्री शैलेश पाण्डे :- उस पर आ रहा हूं न। इसके बाद आंखफोड़वा काण्ड पर आ रहा हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिम्मेदारी की बात करते हैं। आपको यह फटी हुई जेब दिखती है, आपको यह छोटी जेब दिखती है, आपको यही सब दिखता है। आप उसी में घुसे रहे, आप अपने कार्यकाल का बताईये। नसबंदी काण्ड कितना बड़ा काण्ड था। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री गजब, मैं उनका हंसता हुआ फोटो रखा हुआ हूं। मरीजो को हंसते हुए देखने गये, कितनी लज्जा की बात है। यह इनकी सरकार थी, वहां मौत हो गई है और इनके सरकार के मंत्री वहां अस्पताल में जाकर हंस रहे हैं और वही हंसता हुआ फोटो पूरे देश में देखा गया। यह इनकी संवेदनशीलता थी। इनकी सरकार की संवेदनशीलता थी, इनकी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना-देना नहीं था। राम-राम जपना.., ये था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक आकड़ा पढ़ रहा था, बीच में बात इधर से उधर हो गई। अगर हम वर्ष 2017-18 की बात करते हैं तो उस समय 6.65 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. था। पिछले साल 11.54 प्रतिशत था और आज उससे भी ज्यादा है। जी.एस.डी.पी. कैसे बढ़ता है। आपने सेवा की बात की, आपने उद्योग की बात की, आपने कृषि की बात की, आपने बहुत सारी बातें कीं। आपको भी पता है कि जी.एस.डी.पी. कैसे बढ़ता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में इसकी गणना कैसे की जाती है, आप जानते हैं। लेकिन आपने विधानसभा में सिर्फ असत्य बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ असत्य बोलना है ताकि वह अखबार में बड़ा-बड़ा असत्य छपे, बढ़िया-बढ़िया छपे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, मेरे पास आपके भाषण की एक कापी है। सरकण्डा, तारबाहर थाना के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में आक्रमक हुए कांग्रेस विधायक, बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डे ने कहा पुलिस वसूली कर रही है, यहां रेट लिस्ट टंगवा दें, गृहमंत्री ने कहा कि शिकायत लिखकर दें, यह आपने ही कहा था। यह आपके भाषण की कापी है। रेट लिस्ट टंग गई क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, आपको इसका जवाब देंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस का कर्मचारी गलती करता है तो उसकी गलती के लिए उस शहर के विधायक ने उस बात पर डांटा है, उस बात को कहा है तो क्या गलत किया है, आप बताईये ? आपका भी यही धर्म है। आपने यह धर्म नहीं निभाया। छत्तीसगढ़ को लूटो, छत्तीसगढ़ को लूटो, छत्तीसगढ़ को लूटो, आप यही सब करते रहे। आपने इसको कभी रोका ही नहीं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देंगे, बरबाद नहीं होने देंगे, हम अपनी संवेदनशीलता में रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पाइंटेड बात रखिये ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि पर यदि ध्यान देते हैं, लगभग 44 प्रतिशत हमारे पास जंगल है । आदरणीय धर्मजीत भईया लोरमी से आते हैं, जंगल की बहुत बात करते हैं । आप उनसे पूछिये, हमारे प्रदेश में कहां-कहां गांव है ? जंगलों के बीच में गांव है । कितनी जगह गांव है, कितने सारे गांव है ? आप यहां पर मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा कि आपने 27 जिले बनाये, हमने 33 जिले बनाये, हमने उसको और डिवाईड किया, लेकिन उससे भी बड़ा काम जो हुआ है, आपके समय में 150 तहसीलें थी, हमने उसको 233 तहसील किया है, यह हमारा बड़ा काम था । उपाध्यक्ष महोदय, हमने सबसे छोटी यूनिट को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, आज हमारे पास 83 तहसीलें हैं । प्रदेश में 233 तहसीलदार खड़े हुये हैं, प्रदेश में 120 एसडीएम खड़े हुये हैं, प्रदेश में 33 कलेक्टर खड़े हुये हैं, जो प्रशासनिक इकाईयां हैं, वह नीचे काम कर रही है, इसीलिए राजस्व व्यय बढ़ रहा है । उपाध्यक्षमहोदय, आपने 15 साल शासन किया और केवल 150 तहसीलें थी, हमने 4 साल की सेवा में 233 तहसील कर दी है । राजस्व व्यय तो बढ़ना ही था ना ? राजस्व तो कहीं न कहीं खर्च करना पड़ेगा ? हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिये, उन्होंने छत्तीसगढ़ को पिछले चार साल में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना दिया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसान की बात करते हैं, सबसे खास आदमी की बात करते हैं, उस हीरो की बात करते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ का हीरो है। हम लोग यहां बैठे हुये छत्तीसगढ़ के हीरो नहीं हैं, छत्तीसगढ़ का हीरो हमारा किसान है, जिसके कारण आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल में कितने किसान पंजीकृत हुये हैं, केवल 12.5 लाख किसान पंजीकृत हुये हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हुये हैं ? आपके कार्यकाल में कितना धान खरीदा जाता था, 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता था, आज कितनी हो रही है ? आप रकबे की बात करते हैं, रकबा कम हो गया, अगर सनसनी कैसे फैलानी है, इसकी ट्रेनिंग हमें लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेना चाहिये । एकदम बवाल हो गया ? आपने रकबा कम कर दिया, आपने ये कम कर दिया, आपने वो कम कर दिया, तीन साल हो गये एक आवाज नहीं उठती है, एक किसान शिकायत नहीं करता है, एक किसान आत्महत्या नहीं करता है ? आपके समय में किसान आत्महत्या करते थे, आप क्या बोलते थे कि वह शराब पीकर मर गया, अखबारों में आता था कि शराब पीकर किसान की मौत हो गई, किसान फांसी में लटक गया । उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गरमागरमी हुई, सरकार का स्टेटमेंट क्या था, पति-पत्नी के झगड़े में उसने आत्महत्या कर ली । यह स्टेटमेंट हमेंशा अखबार मे पढ़ा जाता था । आपने कभी किसान का दर्द नहीं समझा कि किस प्रकार से वह किसानी करता है, उसके अंदर कितना बोझ था ? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल तक कांग्रेस ने तपस्या की है, गांव-गांव घूमें, हमने जनघोषणा पत्र बनाया, हमने योजनायें बनाई, आज हमारे मुखिया यहां बैठे हुये हैं । हमारी सरकार ने सबसे पहला वादा जो जनता से किया था, जो हमारा छत्तीसगढ़ का हीरो है, जो छत्तीसगढ़ का अन्नदाता है, उसके हमने 17

लाख 96 हजार किसानों का 8744 करोड़ रूपये ऋण माफ किया । आपने ऋण कब माफ किया है ? आपने किसानों को कंगाल बना दिया ? आपने किसानों को भूखा मरने के लिये मजबूर कर दिया और कुछ नहीं मिला तो किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दिया ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष महोदय, अडाणी को धनवान बना दिया, वह भी तो बता दीजिये। अडाणी को सबसे ज्यादा पैसे वाला बना दिया।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह तो हमारे देश के ग्रेट सुल्तान है, जिल्ले इलाही। वह जिल्ले इलाही का काम है। कंट्रीमैन, स्टेटमैन।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किसानों की कर्जमाफी की। क्या काम किया ? क्या यह कोई नेतागिरी थी ? 17 लाख 96 हजार किसानों को 8 हजार 744 करोड़ रूपये माफ करना, यह कोई बच्चों का काम नहीं था। यह दबंगई का काम था। यह उस कमिटमेंट का काम था, जिस कमिटमेंट में जनता ने सरकार को सहयोग दिया। यदि वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता ने आपको झाड़ू लगाकर साफ किया है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसके बाद लगातार साफ कर रही है। हम लोग 68 से 71 हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, 31 मिनट हो गये हैं और कितना समय लेंगे ?

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जितना वह बोले उससे थोड़ा 10 मनिट और दे दीजयि।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करता हूं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिये। हम किसानों की बात कर रहे थे। आपने छत्तीसगढ़ में किसानों को किस स्थिति में ला दिया ? आज छत्तीसगढ़ में लगभग-लगभग सभी किसान हमारे पंजीकृत किसान है। आपको हमारी योजनाएं अच्छी नहीं लगती। आज छत्तीसगढ़ में 12.5 लाख पंजीकृत किसान हुआ करते थे, आज 4 साल में वह 23 लाख 50 हजार कैसे पहुंच गये ? केवल चार साल में। आप बताईये। सरकार काम कर रही है, सरकार किसानों का एक-एक अन्न खरीद रही है। सरकार किसानों का विश्वास अर्जित करके बैठी हुई है, सरकार ने यही सबसे बड़ी चीज करी। आज 4 साल में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम 23.5 लाख किसानों का पंजीकरण कर चुके हैं। उन परिवारों का पंजीकरण कर चुके हैं। हम जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। आज यदि हम अपने राज्य को सरप्लस रेवेन्यू वाला राज्य कह रहे हैं तो उस पर हमको गर्व है। क्योंकि हमने उन किसानों की जेब में पैसा डाला। पैसा तो टिकता नहीं है। पैसा तो चलता रहता है, वह घूमता है। हमारी सरकार ने किसानों को पैसा दिया। हमारी सरकार ने 23.5 लाख किसानों को हजारों करोड़ रूपये दिया है। वही पैसा मार्केट में आया है उसी पैसे के कारण आज मैं जिस बात पर खड़ा हुआ था कि हमारी जी.डी.पी. जब -1.7 प्रतिशत पर था, उस वक्त केन्द्र की जी.डी.पी. -7.7 प्रतिशत थी। तब हमारा इसमें था। क्यों ? इसीलिये क्योंकि हम किसानों की जेब में, आदिवासियों की जेब में, छत्तीसगढ़

की जनता की जेब में पैसा डाल रहे थे। हम उसका सम्मान कर रहे थे। ताकि वह आत्महत्या न करें, ताकि वह लड़ाई-झगड़ा न करें, ताकि प्रदेश अच्छा चले। सरकार आपने भी चलाई है, सरकार हम भी चला रहे हैं। उस बात को बताना जरूरी है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। यही है छत्तीसगढ़ मॉडल, जो लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, हमारे प्रदेश में लोगों को शक्तिशाली बना रहा है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा है। यह है छत्तीसगढ़ का मॉडल।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वास्थ्य विभाग में आते हैं। आपके समय में क्या हुआ करता था ? आपके समय में स्वास्थ्य का क्या हाल-चाल था ? आपने किसने सी.एस.सी., पी.एस.ई. खोले ? आपने कभी हमर क्लिनिक खोला ? आप कभी जनता के बीच में गये ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि चार-पांच दिन पहले बिलासपुर में आपने हमर क्लिनिक के लिये 25 लाख रूपये दिये हैं। मैं उसका उद्घाटन करने गया, उसका भूमिपूजन करने गया और मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं उस केवल 25 लाख के हमर क्लिनिक का, जो बिलासपुर में 14 सेंक्शन हुए हैं, उसका भूमिपूजन कर रहा था, उसको देखने के लिये 5 सौ लोग आये हुए थे। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है। केवल भूमिपूजन में 5 सौ लोग आये थे। जो सरकार की सराहना कर रहे थे। जो बोल रहे थे कि सरकार स्वास्थ्य की सेवाओं के प्रति कितनी सजग है, जो लोगों के बीच में जा-जा कर वह छोटी-छोटी स्वास्थ्य की यूनिटें खोल रही है। उनको विश्वास है कि हमर क्लिनिक से हमारा कुछ-न कुछ फायदा होगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपकी यह योजना नीचे जाकर सफल हो रही है (मेजों की थपथपाहट)। लोगों में इस बात की प्रशंसा है। यदि हम स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करते हैं। आप स्वास्थ्य की सेवाएं कहां से लाओगे ? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके जमाने में क्या होता था ? बंगले से फोन जाता था, यह वाला मटेरियल उसको दे देना, यह वाला मटेरियल उसको दे देना, यह वाला ठेका उसको दे देना।

समय :
5.00 बजे

श्री रामकुमार यादव :- इसकी टोपी उसके सर।

श्री शैलेश पाण्डे :- देखिए, यह पहले होता था। अभी यह नहीं होता है। पहले यही होता था।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अब तो 5 लाख रूपये के लिए भी फोन आता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे बना पाएंगे। चलिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय पाण्डे जी, आपकी बाकी बातें सही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बताना चाहूंगा...।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह हमारे प्रभारी मंत्री थे। आप असत्य मत बोलिए। फालतू बात है। आप उनके बहकावे में आ गये हो। आप गलत, असत्य बोल रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय पाण्डे जी, एक मिनट। क्या है हमारे मिनिस्टर जी क्या करते हैं, यह पूरा प्रदेश जानता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारे प्रमोद शर्मा जी पहले अच्छे विधायक हुआ करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में इतने ज्यादा आ गये हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय शिवरतन जी, अडानी पूरे देश को लूट रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं ? पूरा देश लूटा जा रहा है क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय पाण्डे जी, आप इधर देखकर मत बात करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह संगति का असर है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय शर्मा जी, छत्तीसगढ़िया में कहे गे हे ते परबुधिया मत होवव मालिक। आप परबुधिया हो जावत हवव।

श्री प्रमोदकुमार शर्मा :- अब सत्य के ज्ञान होगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय प्रमोद जी, आप घर बैठेंगे तो ठीक हो जाएंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वास्थ्य की सेवाओं की बात कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे बहाल कर पायेंगे। हम स्वास्थ्य की सेवाएं नीचे कैसे पहुंचा पायेंगे ? केवल वहां मशीन भेज देने से सेवा होती है। केवल मशीन भेज देने से नहीं होता। केवल कहीं मशीन खरीद लेने से नहीं होता। चलिए, आपने कमीशन खाया। आपने खाया ही होगा। (हंसी) आपने कमीशन खाकर मशीन खरीद दी, आप डॉक्टर कहां से लाएंगे ? आपने डॉक्टरों को सेवा में लाने के लिए क्या किया ? वह लोग एकदम अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिमान हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिमान जो यहां पर हम लोगों को अपना ज्ञान देते हैं, उनके आभारी हैं, लेकिन उस समय मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति थी ? उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे ? उस समय 6 मेडिकल कॉलेज खुले हुए थे। उन 06 मेडिकल कॉलेज में से 3 चालू थे और 03 मेडिकल कॉलेज चालू ही नहीं थे। आप 03 मेडिकल कॉलेज में कितने डॉक्टर निकालोगे? फिर कितने डॉक्टर नीचे भेजोगे? उनकी कितनी बड़ी-बड़ी गर्दन फंसा देंगे? ऐसे करके(हाथ के ईशारे से) 2-2 लाख रूपये का बाण्ड होता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पाण्डे जी, एक सेकण्ड। मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ आप शिक्षा क्षेत्र के आदमी हो। एक मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना खर्च आता है?मुझे बताईये? नहीं तो आपके नेता जी से पूछ लीजिए। दूसरा जो केन्द्र सरकार ने स्टेट कम्पोनेंट के साथ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किये हैं तो स्टेट कम्पोनेंट कितना है? उसकी बिल्डिंग- विल्डिंग बनना शुरू हो गई? क्या है आप थोड़ा पूछ लीजिए और हमको भाषण में बताईये? हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- यहां थोड़ी जलन की बू आ रही है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, महाराज जी, एक मिनट सुनव। ए मन ला कई ठन योजना चलावय तो छत्तीसगढ़ी में कहावत हे। 4 नग घाघर अउ बारा नग के पुदगऊनी। एमन के ओसन रहाए। एमन योजना चलावए तो थोकन काला कहिया एमन के दु:ख ला।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है। आपके समय भी केन्द्र में सरकार थी। आपके समय में केन्द्र में आप सिंगल इंजन की सरकार चलाते थे। वहां 10 सालों तक डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आपको कितना पैसा आता था आप बताईये? आप उस पैसे का उपयोग करते क्या थे, यह आपके ऊपर था। आप कौन सी योजना बनाकर दिल्ली भेजते थे यह आपके ऊपर था। आप वहां पर क्या करने जाते थे, क्या योजना लाते थे? आप कहां पैसा लगाते थे? जनता को क्या मिलता था, यह आपके ऊपर था। 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक आपने केन्द्र में विपक्ष की सरकार दी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के साथ केन्द्र में बैठी हुई उस समय कांग्रेस की सरकार ने कभी अन्याय नहीं किया। कभी मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं बोला कि हमको पैसा कम दिया। हमको यह कम दिया, हमको वह कम दिया। आज की स्थिति और पहले की स्थिति में अंतर है। मैं स्वास्थ्य की सेवाओं की बात कर रहा था। हम स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे लाएंगे? हमारे पास डॉक्टर्स होने चाहिए, हम डॉक्टर्स कहां से पैदा करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर देखिए। आप उधर मत देखिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका लगभग आधे घण्टे से ज्यादा हो गया।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर देखते हैं तो अच्छे लगते हैं। आज हमारी सरकार में हम कहते हैं कि 10 मेडिकल कॉलेज हुए। 10 मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि 10 में से 05 मेडिकल कॉलेज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में है और 05 मेडिकल कॉलेज रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग में है। दोनों संभागों, चारों संभागों में बराबर- बराबर का डिविजन है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 04 मेडिकल कॉलेज की और घोषणा की, जिसमें 02 मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, सरगुजा संभाग में दिये हैं और 02 मेडिकल कॉलेज हमारे रायपुर और बस्तर के संभाग में दिये हैं। हमारे पास 14 मेडिकल कॉलेज हुए। आदरणीय धर्मजीत भईया, इन 14 मेडिकल कॉलेज में हम मानते हैं कि 100 सीटें भी होंगी तो हमारे पास 1400 डॉक्टर तो होंगे। आज हम 1400 डॉक्टर तक तो पहुंचे। छत्तीसगढ़ 300 डॉक्टर से 1400 डॉक्टर तक पहुंच रहा है जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। यह संवेदनशील सरकार है। अगर 14 मेडिकल कॉलेज हैं तो सरकार अच्छा भी काम कर रही है कि सरकार ने 14 मेडिकल कॉलेज खोला है। उसमें अच्छे डॉक्टर बनेंगे। छत्तसीगढ़ का हमारा आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का बच्चा डॉक्टर

बनेगा। आज उसके पास अवसर तो बहुत हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय शैलेश पांडे जी समाप्त करिये, बोलने वालों की और भी लंबी सूची है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे 10 मिनट और समय दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आदरणीय बाबा साहब, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज नहीं थे। उतने मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस मेरे पिता नहीं दे सकते थे। वह तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी नहीं दे सकते थे। ये स्थिति थी। लेकिन मैंने क्या किया ? 11वीं में मैंने विज्ञान का विषय नहीं लिया, गणित का विषय लिया। मैंने कहा कि ये विषय ज्यादा ठीक है। इंजीनियर बन जाऊंगा, सस्ते में बन जाऊंगा। इंजीनियर तो बन ही जाऊंगा और इंजीनियर बन कर कुछ न कुछ तो अच्छा काम करूंगा ही, जीने के लिए कुछ आमदनी अर्जित कर ही लूंगा। यह इच्छा थी। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं। आज छत्तीसगढ़ का गरीब आदमी, हर वयक्ति यह सोच सकता है कि वह अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा सकता है और अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है। क्योंकि ऐसी योजना सरकार की रही है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना चलाई जा रही है। स्वास्थ्य की योजनाओं को हम और कितने नीचे तक ले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाट बाजार क्लीनिक योजना में 1 लाख 45 हजार शिविर लगाये गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय, आप बस यह बताईये कि जो 1 हजार करोड़ रुपये अभी नगरपालिकाओं, नगरनिगमों को मिला है, उसमें 50 करोड़ रुपये बिलासपुर को मिला है। यह पैसा मिल जायेगा न और आपके हिसाब से काम हो जायेगा? बस आप इतना ही बताईये, हां या ना।

श्री अरूण वोरा :- आप बिलासपुर का तो बोल रहे हैं, दुर्ग में वह पैसा पहुंच गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दुर्ग में तो पहुंच गया है। वहां तो पहुंच ही रहा है। पर मैं यहां का पूछ रहा हूं जहां बेचारे दुखी रहते हैं। बिलासपुर में 50 करोड़ रुपये पहुंचेगा या नहीं और यदि पहुंचेगा तो आपसे सलाह-मशविरा करेंगे या नहीं?

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भैया ने जो बात बोली है, पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति आ गई है और दूसरी बात यह है कि उसके टेंडर भी लग चुके हैं। क्योंकि वह 50 करोड़ रुपये जो आया है, उसके टेंडर पहले से ही रेडी थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपकी सलाह से?

श्री शैलेश पांडे :- हॉ, मेरी सलाह से। इसमें एक बात और जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नये क्षेत्र, नये वार्ड जोड़े हैं, उनके लिए डेढ-डेढ़ करोड़ रुपये एक वार्ड में दिया है और जो पुराने क्षेत्र हैं उसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये अलग से दिया है। टोटल लगभग-लगभग 80 से 85 करोड़ रुपया बिलासपुर नगर निगम में आया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लीनिक योजना के संबंध बता रहा था कि 1 लाख 45 हजार शिविर लगाये गये जिसमें कि 42 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लीनिक योजना के तहत हॉट बाजार में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री स्लम योजना के अंतर्गत झुग्गी-झोपडियों में हम लोग डॉक्टर को भेज रहे हैं। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी कहां चये गये। मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना के तहत 1 लाख 42 हजार महिलायें लाभांवित हुई हैं। इस योजना के तहत हम पूरे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर को भेज रहे हैं। वह सड़कों में, बाजारों में जा रहे हैं। ऐसा पहले कहां हुआ, ये बताईये न। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह हमारी सरकार ने किया। यह हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल ने किया। आप कहते हैं कि आपने शराब में 6 हजार करोड़ रुपये कमा लिये। आपने क्या किया था ? आपने शराब माफियाओं की सरकार चलाई। शराब माफिया लोग सरकार चलाते थे। जब आपने कमीशन मांगा, आपने ज्यादा पैसा मांगा। आपको कमीशन नहीं मिला तो आपने शराब का सरकारीकरण कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें। सौरभ सिंह जी।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बातें बहुत सारी हैं। हम लोग बात कर सकते हैं। मैं आपके कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के बारे में दो मिनट और अच्छा-अच्छा बोल दूं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ की वह माताएं व बहनें जो आंगनबाड़ी में बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, उनको ध्यान देते हुए उनका जो मानदेय है, वह 6.5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है, यह सबसे बड़ी बात है। (मेजों की थपथपाहट) मैं अभी होली मिलन कार्यक्रम कर रहा था। उसमें मितानीन बहनें, हमारी ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, 45 मिनट हो चुका है। अभी और भी लंबी सूची है। नये लोगों को भी मौका देना है। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहला वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- 45 मिनट से अधिक हो गया है।

श्री शैलेश पांडे :- आप बोलेंगे तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, अभी और भी लोगों को मौका देना है। एक मिनट के बाद सौरभ सिंह जी, आप बोलेंगे।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आंगनबाड़ी के बहनों, हमारी मितानीन बहनों का जो मानदेय बढ़ाया है, इससे छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों का सम्मान बढ़ा है। क्योंकि आज यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हर घर में कौन जाता है? हर घर में डॉक्टर नहीं जाता है। हर घर में यदि कोई जाता है तो मितानीन जाती है। हर घर में कौन जाता है, हमारी आंगनबाड़ी में कौन जाता है, हर बच्चे से कौन जुड़ा हुआ है, हर माता से कौन जुड़ा हुआ है, इन सभी से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें जुड़ी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने उनका जो 10 हजार रूपये मानदेय बढ़ाया है और 2200 रूपये मितानीन बहनों को दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बहुत-बहत आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बाते हैं। आप समय नहीं देंगे, मुझे डाटेंगे। इसलिए बाकी वक्ताओं के लिए मैं अपनी बात बंद कर देता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना अंतिम बजट पेश किया गया, उसके आय-व्ययक के चर्चा पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है, यह छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे का बजट है और उस पैसे का पारदर्शी हिसाब-किताब होना चाहिए। उसको घूमा-फिराकर आंकड़ों की बाजीगरी में पेश नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन हो और इस बजट में उस 5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत की 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। किसी पार्टी की इकॉनमी नहीं होगी। वह भारत की 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। उस 5 ट्रिलियन की इकॉनमी में छत्तीसगढ़ सरकार का क्या कन्ट्रीब्यूशन होगा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अंग्रेजी में बोलथस ता समझ नइ आवय, हिंदी में बोल न।

श्री सौरभ सिंह :- मैं अंग्रेजी में बोल देथो अउ छत्तीसगढ़ी में भी बोल देथो। अर्थव्यवस्था में हम पांचवें नंबर पर पहुंचेंगे और हमारा आगामी क्या प्रयास होगा। बहुत सारी चीजों की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में एक शब्द का प्रयोग किया। केन्द्र सरकार की ग्रोथ रेट और हमारी ग्रोथ रेट। सरकारों की ग्रोथ रेट नहीं होती है, राज्यों की ग्रोथ रेट होती है। यह छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट है और वह भारत की ग्रोथ रेट है। इन शब्दों को अलग करना चाहिए। वह भारत का ग्रोथ रेट है और यह

छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट है। छत्तीसगढ़ में शैलेश पांडे जी बोल रहे थे कि पिछले साल 11 प्रतिशत ग्रोथ रेट हुई थी, इस बार 8 प्रतिशत क्यों अनुमानित है? आप केन्द्र सरकार से तो तुलना कर रहे हैं कि 7 प्रतिशत ग्रोथ हुई है। आप यहां 8 प्रतिशत ग्रोथ क्यों कर रहे हैं? आप 11 प्रतिशत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना performance क्यों repeat नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि आपकी performance क्यों repeat नहीं हो रहा है? आप 11 को 12 प्रतिशत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय शैलेश पांडे जी बोल रहे थे कि 1 लाख 6 हजार करोड़ रूपये पैसा आयेगा। मैं तो आग्रह करूंगा कि यह बजट के ऊपर सभी विधायकों का एक क्रैश कोर्स होना चाहिए और आई.आई.एम. एक क्रेश कोर्स करता है, हमारे रायपुर में आई.आई.एम. खुला था । आई.आई.एम. एक क्रेश कोर्स करता है । जो लोग बड़े-बड़े एक्जीक्यूटिव्स होते हैं, बजट की समझ के लिये विधायकों का भी क्रेश कोर्स होना चाहिए । यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े जनता के आंकड़े हैं । इन आंकड़ों को हमको समझना पडेगा । उन आंकड़ों में क्या खेल हो रहा है उसको समझना पड़ेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 6 हजार करोड़ रूपये आपकी आमदनी हुई और आपने 1 लाख 21 हजार करोड़ रूपये खर्च किया तो बाकी 15 हजार करोड़ रूपये कहां से आयेगा ? कर्जे से ही आयेगा न । 15 हजार करोड़ रूपये कर्जे से ही आयेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूं । वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक जो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर इस प्रदेश का है, कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब सैलरी का भुगतान, पेंशन का भुगतान, उस कमिटेड एक्सपेंडिचर में 74 परसेंट की ग्रोथ हुई है और इसी समय के दौरान जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 33 परसेंट ग्रोथ हुई है, हम किस रास्ते पर छत्तीसगढ़ प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं ? हम हमारे लिये भविष्य में खर्च करने के लिये कोई पैसा बचायेंगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017, 2018, 2019 में हमने 14,370 करोड़ रूपये कर्जा लिया, आप कर्जा ले रहे हैं तो उसकी अलग कहानी है । मैं उस पर आऊंगा, अगर कर्जा ले रहे हैं तो उसको केपिटल एक्सपेंडिचर करिये न, तन्ख्वाह बांटने के लिये क्यों कर्जा ले रहे हैं, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिये क्यों कर्जा ले रहे हैं ? 14 हजार 370 करोड़ रूपये आपने कर्जा लिया, उसका केवल 8903 करोड़ रूपये आपने केपिटल एक्सपेंडिचर किया । वर्ष 2019-20 में आपने 19,787 करोड़ रूपये कर्जा लिया और आपने 8,567 करोड़ रूपये केपिटल एक्सपेंडिचर किया । वर्ष 2020-21 में 21, 581 करोड़ रूपये आपने कर्जा लिया और आपने केवल 9 हजार करोड़ रूपये खर्च किया । वर्ष 2021-22 में आपने 15 हजार करोड़ रूपये कर्जा लिया और आपने केपिटल एक्सपेंडिचर में केवल 10 हजार करोड़ ही खर्चा किया । आप कर्जा लीजिये लेकिन केपिटल एक्सपेंडिचर में उस कर्ज को खर्च कीजिये । रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा करना मानो यह सरासर पाप है, जो आप इस बार कर रहे हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर रहे हैं ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- क्या अडानी को एल.आई.सी. का पैसा देना अच्छा है ? बैंक का पैसा, जनता का पैसा लूटने के लिये अडानी पूरे देश को लूट रहा है क्या वह अच्छा कर रहा है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त सचिव के स्मरण पत्र में 99 हजार 172 करोड़ का कर्जा है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री जी, यह टेक्निकल बात है । आप नहीं समझ रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्जा पटाने के लिये 7 हजार 542 करोड़ रूपये देने पड़ेंगे । हम किस तरफ जा रहे हैं ? नाबार्ड का लोन, बाजार का लोन सारा लोन ले रहे हैं और माननीय अजय चंद्राकर जी इस बात को कह रहे थे कि वर्ष 2026-27 में हमारा सारा का सारा लोन मेच्योरिटी पर आयेगा । हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुराने राज्य में चौथी बार एक ही महीने में कर्जा लिया है थोडा झांक-झांककर देखिये न । अडानी पूरे देश को लूट रहा है उसको भी बोलो न । यह क्या हो रहा है ? गाढ़ी कमाई का पैसा है, जनता का पैसा है, बीमा कंपनी में जमा किया था उसको लूट लिया ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 99 हजार 172 करोड़ रूपये लोन लिया है और जो लोन लिया है । वह जो लोन है, वह लोन आपके जी.डी.पी. का 20 परसेंट है और इंटरेस्ट चुकाने के लिये भी आपको लोन लेना पड़ेगा और आपने जितना लोन लिया है उसका 25 परसेंट लोन वर्ष 2023-24 और 81 परसेंट लोन वर्ष 2026-27 तक पटाना है । आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया और जब शॉर्ट टर्म लोन लिया तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया और नाबार्ड से आपको जो सस्ता लोन मिलता है वह लोन पर न लेकर आपने शॉर्ट टर्म बाजार से लोन लिया । परिसंपत्ति को लगाकर आपने लोन लिया और अगर छत्तीसगढ़ की जनता को परिदृश्य बराबर दिखाना है तो 20 हजार 600 करोड़ रूपये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लोन है । पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो लोन है उसके भी तो गारंटर हम हैं, यह सरकार है । अगर फेल हो जायेगा तो पैसा तो राज्य के बजट से देना पड़ेगा। तो टोटल लोन कितना हो गया, 1 लाख 20 हजार करोड़ और आपके बजट का साइज 1 लाख 21 हजार करोड़ रूपये है। जितना बजट का साइज है 1 साल में जितना आप खर्चा कर रहे हैं, मैं खर्चा की बात कर रहा हूं। जो बजट का टिकट साइज है, उसकी बात कर रहा हूं। न कि आपका जो रिसीट है, उसकी बात कर रहा हूं। आपका उतना ही कर्जा है।

श्री अमरजीत भगत :- जिसने आपको सिखाया है, उसने गलत सिखाया है। ऐसा नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- सौरभ सिंह जी, लोग ये आंकड़े नहीं समझते। लोग काम देखते हैं। काम समझते हैं। कितना काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है? आप तो आंकड़ों की बाजीगरी में उलझ गये और प्रदेश की जनता को उलझा रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा कि आप आंकड़ों की बाजीगरी में जा कहां रहे हो? इस चीज को आपको समझनी पड़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे बजट की चर्चा है। मैं एक चीज पर जाना चाहता हूं।

श्री कवासी लखमा :- इतना जानकार हैं तो मोदी और अडानी के जानकार को समझाओ न भाई। कितना गिर रहा है? कितना हाई हो रहा है? देश को लूटा जा रहा है, उसे बताओ।

श्री सौरभ सिंह :- दादी, यहां पर सदन की मर्यादा है। मैं बोलना नहीं चाहता। जिस चीज को आप बोलवाना चाहते हैं, वह सदन के बाहर बता दूंगा कि यहां अडानी का क्या-क्या हुआ है? अडानी का क्या-क्या हुआ है? सदन की मर्यादा है। सदन में जो लोग यहां के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। तो मैं उसे बोलना नहीं चाहता हूं। सदन के बाहर बता दूंगा। टी.वी. के सामने बता दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप अपने विभाग के दारू का हिसाब-किताब कर लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- आप उधर खड़े हो रहे हैं न टिकट मिलेगा करके। आपको नहीं मिलेगा प्रमोद शर्मा जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का रेवेन्यू जनरेशन कहां से आता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, अडानी के ट्रांसपोर्टर कौन-कौन कांग्रेस के नेता हैं, कौन-कौन बाहरी नेता हैं, वह राजा साहब पूरा बता देंगे अंबिकापुर के। आप पूछ लीजिए। फिर वे अडानी-अडानी बकना बंद कर देंगे।

श्री कवासी लखमा :- राजा साहब अभी मीटिंग में पूरा घूमकर आये हैं कि कहां क्या-क्या होता है? पूरा पोल खोलकर आये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- लखमा जी, वर्ष 2018 के चुनाव में अडानी का भेजा हुआ कितना माल आपके पास पहुंचा, ये भी राजा साहब बता देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बजट पर चर्चा करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारे नेता जी के लिए कुछ बचाएंगे या नहीं?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार का राजस्व जनरेशन बढ़ना चाहिए। यह सबकी चिंता है। टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए और टैक्स बराबर आना चाहिए। पर इस पर क्या काम हो रहा है? अचानक इस साल दादी बोल रहे थे, उनका लिकर का जनरेशन बढ़ गया। फट्ट। लिकर में जनरेशन बढ़ गया। अचानक माइनिंग से जो हमारा राजस्व आता था, वह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ई.डी. की रेड पड़ी न। इनकम टैक्स की रेड पड़ी न। 2 पेटी का धंधा चल रहा था, जो 2 नंबर का माल बिक रहा था, वह माल बिकना बंद हो गया और सरकार के खाते में पैसा आना चालू हो गया। तो 19 प्रतिशत बढ़ा। वह 19 प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा था?

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, सय्या भाई कोतवाल तो काहे का डर। इसीलिए तो अडानी तरक्की कर रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ सरकार का जो पैसा आता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक आंदोलनकारी ने माननीय मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में समानांतर दारू कौन-कौन बेचता है ? कहां से आकर होता है? आप कहें कि जांच करायेंगे, आश्वासन देंगे तो वह पत्र मैं आपको फारवर्ड कर देता हूं। नाम समेत दिया है। पटल में रखना है? आप बोलिए तो पटल में रखूंगा? आप व्यवस्था मान लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- दादी को तो कुछ मालूम ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पटल पर रख दूंगा और अकबर जी आपको बता देता हूं जो क्राउन प्रिंस है न, उनके भाई का नाम है। क्राउन प्रिंस के भाई का नाम है। उनकी नामजद शिकायत है कि यहां-यहां से दारू आकर बिकता है। मुख्य सचिव महोदय को संबोधित और ये सरगना आदमी हमें अडानी के बारे में भाषण दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार के पास सबसे बड़ा रेवेन्यू की जगह है, वह है जी.एस.टी.। जी.एस.टी. की बहुत लोग आलोचना कर रहे थे कि जी.एस.टी. गलत है, सही है, क्या है, पर जी.एस.टी. का सबसे बड़ा कलेक्शन यहां पर है। हमारे सबसे बड़े राजस्व की जगह जी.एस.टी. है। नंबर एक। और जी.एस.टी. का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन पर भी वृद्धि हुई है। उसका कारण भी वही ई.डी. और आई.टी. की रेड है। जो जी.एस.टी. की चोरी होती थी। सेकण्ड नंबर पर माइनिंग है। आज भी माइनिंग की चोरी हो रही है। 25 रूपये कोयले के टन की जो ई.डी. की चार्जशीट है न, वह चार्जशीट के बाद क्या हो रहा है? कवासी लखमा जी उस पर क्यों बात नहीं करते? जो चार्जशीट लगी हुई है, वह चार्जशीट पब्लिक डोमेन में आ गई है। उसके बारे में क्यों बात नहीं करते कि 25 रूपये कोयले के टन के माइनिंग लीज का क्या हो रहा था? वह माइनिंग का पैसा कहां जा रहा था?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, आप लोग भाषा शास्त्री भी हैं । आप लोगों ने मुहावरे बदल दिये । कोयले की दलाली से अब हाथ काले नहीं होते, कोयले की दलाली से हाथ उजले होते हैं । आप लोगों ने मुहावरे का अर्थ ही बदल दिया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसी को तो सारा देश जानना चाहता है । ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाकर, जिस नाम का ज़िक्र सदस्य कर रहे हैं । उससे आपके क्या रिश्ते हैं, यही प्रश्न तो पार्लियामेंट में था । दूसरा, अभी सौरभ जी कह रहे थे जी.एस.टी. के बारे में, महाराज साहब से पूछ लेना, छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है जिस तरीके से नीति है, छत्तीसगढ़ को जी.एस.टी. से एक साल में सात हजार करोड़ का नुकसान है, इसी साल। आदरणीय सौरभ जी, इस बारे में आप हमसे ज्यादा समझादार हैं । लेकिन उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा ?

श्री सौरभ सिंह :- जी.एस.टी. पर टोकाटाकी नहीं करेंगे तो जी.एस.टी. पर पृथक बहस भी हो जाएगी । जी.एस.टी. काउंसिल में सार्वजनिक निर्णय हुआ था, आप उत्पादक राज्य थे इसलिए आपको पांच साल का कंपन्सेशन दिया था और पांच साल का कंपन्सेशन बंद हो गया । जी.एस.टी. कंपन्सेशन का जो पैसा आना था उसके विरूद्ध सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लोन भी दिया और उसके बाद वित्त मंत्री जी का यह बोलना है और उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा की है कि आप ऑडिट कराकर दे दीजिए, उसकी व्यवस्था की जाएगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वित्त मंत्री जी की घोषणा का कितना पालन होता है, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई थी । 20 नया पैसा नहीं आया ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग में आज भी चोरी हो रही है । आज भी अवैध रेत खदानें चल रही हैं । आज भी रेत खदानों का टेंडर नहीं हुआ है । वहां पर से सरकार वसूली क्यों नहीं करती ? अपना रेवेन्यू जनरेशन क्यों नहीं करती? छत्तीसगढ़ में माफिया राज बना दिया गया है । यही छत्तीसगढ़ मॉडल है । छत्तीसगढ़ में माफिया राज है । माइनिंग माफिया पूरा एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, वह राज्य सरकार के खाते में नहीं आ रहा है, वह उनके खाते में जा रहा है । कवासी लखमा जी बात कर रहे थे, 6700 करोड़ रूपए का इनका बजटेड एस्टीमेट है कि अगले साल आपको आबकारी में इतना पैसा मिलेगा । 2021-22 में आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, 2022-23 में आपने आरगेट अचीव नहीं किया । 2022-23 में आपने जम्प किया । पिछले 3 सालों से आपने टारगेट अचीव नहीं किया । आप पैरलल इकोनॉमी चला रहे थे । आपको 10 परसेंट, 15 परसेंट ऊपर टारगेट सेट करना था, वह टारगेट आप सेट नहीं कर रहे थे । आप 10 परसेंट के टारगेट पर रोक देते थे । टारगेट के ऊपर 52 परसेंट आपका 92 परसेंट अचीवमेंट था । क्यों 92 परसेंट अचीवमेंट था, इस साल 17 परसेंट जम्प क्यों आ गया ? आई.टी. के रेड पड़ी तो 17 परसेंट जम्प आ गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आबकारी में 500 से 5000 करोड़ का जो मुनाफा कमाए थे, उसमें तो आप लोगों को इंटरनेशनल पुरस्कार मिलना चाहिए ।

श्री सौरभ सिंह :- 6700 करोड़ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अक्ल वाला बात मा तैं कहां बीच बीच में खड़े हो जाथस। ये टोकेटाके के नइ, ये अक्ल वाला बात हे ।

श्री सौरभ सिंह :- 6700 करोड़ एक्स्ट्रा जम्प आ गया । 17 परसेंट एक्स्ट्रा जम्प कर रहे हैं । कहां से, वह पैरलल इकोनॉमी बंद हो गयी । आई.टी. और ई.डी. की रेड पड़ी तो पैसा सरकार के खाते में आने लगा । आने दीजिए ना, कौन मना कर रहा है ? लेकिन इसके ऊपर व्यवस्था होनी चाहिए । ये पैरलल इकोनॉमी बंद होनी चाहिए । यह माफिया राज बंद होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ का पैसा है, यह लूट से बाहर नहीं जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, सौरभ जी 20 मिनट हो गए ।

श्री रामकुमार यादव :- भले ही तुमन सारा पइसा अडानी, अंबानी ला दे दौ ।

श्री सौरभ सिंह :- राजस्व सचिव ने अपने स्मरण पत्र में लिखा है कि बराजों से जो पैसा राज्य सरकार को आना चाहिए, वह पैसा राज्य सरकारों को नहीं आ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सौरभ सिंह :- बराजों से वह पैसा नहीं आ रहा है, वह करोड़ो रूपये क्यों छोड़े जा रहे हैं । उद्योगपतियों से वह पैसा क्यों वसूला नहीं जा रहा है । उद्योगों के लिए जो बराज बने थे । उनका पैसा क्यों वसूला नहीं जा रहा है ?

श्री रामकुमार यादव :- किसानों के लिए, तुमन उद्योग के लिए बनाए रहेव ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, 2 हजार करोड़, उसके बाद इस साल और 2100 करोड़ रूपए इस साल स्टाम्प ड्यूटी से आपको आएगा । आपने 30 परसेंट और 40 परसेंट रेट क्यों कम कर दिया ? भारत माला प्रोजेक्ट में किसानों को लैंड एक्वीजीशन में नुकसान हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? लोगों को कर्जा नहीं मिल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जो स्टाम्प ड्यूटी में पैसे का नुकसान हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा । आप रेट नीचे गिरा रहे हैं, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो गाइड लाइन में लैंड का रेट नीचे गिराता हो । गाईडलाईन का रेट ऊपर होता है। उससे लोगों को पैसा मिलता है, उससे किसान को लोन मिलता है, उससे लोगों को हाऊसिंग लोग मिलता है। उसका गाईडलाईन रेट नीचे नहीं गिराया जाता। आप गाईडलाईन रेट नीचे गिरा रहे हो और वहां की (व्यवधान) कर रहे हो।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सौरभ जी, यह बताईए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों का कितना कर्ज माफ किया और किसानों का कितना कर्ज माफ किया ? आप एकतरफा बात करते हो, बात को सुनते नहीं हो।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी आप लोग सी.एस.ई.बी. का 3400 करोड़ माफ किए हो। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में इनको अगर सबसे ज्यादा प्राफिट मिल रहा है तो 30 प्रतिशत प्राफिट बिजली से मिल रहा है। इनका 3 हजार करोड़ सिर्फ इलेक्ट्रीसीटी से आएगा जो छत्तीसगढ़ की जनता से अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है। आपका तीन हजार करोड़ रूपया राजस्व इलेक्ट्रीसीटी से आएगा। एक तरफ आप बोल रहे हो कि रोज बिजली का रेट बढ़ता जा रहा है। बिजली में कोयले का सेस जोड़ा जा रहा है। कभी वह एक रूपये 10 पैसे हो जाता है, कभी 78 पैसा हो जाता है, कभी 62 पैसा हो जाता है तो यह 3 हजार करोड़ रूपए जनता से क्यों ले रहे हो ? आपका इलेक्ट्रीसीटी सेस 30 प्रतिशत है। आपका 6,643 करोड़ रूपए वैट से आएगा। 35 प्रतिशत इंक्रीज होगा,

आप जो राजस्व इंक्रीज की बात कर रहे थे ना, वह 35 प्रतिशत वैट पर होगा और वैट किस पर लगता है ? दारू और डीजल पेट्रोल पर लगता है।

श्री रामकुमार यादव :- जैसे ये अडानी के पईसा तिजोरी में कम होईस गैस के कीमत हा साय ले 50 रूपया बढ़ गे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बईठ जा यादव जी।

श्री रामकुमार यादव :- हमन एकर बइठे-बइठे कतिक लबारी ला सुनबो।

सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ गैर भाजपा शासित राज्यों में अकेला राज्य है, जहां पर पेट्रोल में प्रति लीटर 27 रूपये लिया जा रहा है और 25 रूपये प्रति लीटर डीजल पर लिया जा रहा है तब 102 रूपये में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी इस वैट को कम नहीं कर देते।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- केन्द्र क्यों कम नहीं करते तो।

श्री सौरभ सिंह :- केन्द्र ने कम कर दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- कहां कम किया है ? सवाल ही नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- आपका वैट सबसे ज्यादा है। आप 28 प्रतिशत ले रहे हैं। सबसे ज्यादा वैट लेने में छत्तीसगढ़ है। आप 30 प्रतिशत ले रहे हैं। आज इस बजट को जो एडिशनल सपोर्ट है, अगर आपको उसका उदाहरण देखना है तो आप उड़ीसा जाकर देखिए। 1 हजार करोड़ रूपये से उपर की डी.एम.एफ के पैसे की बंटरबांट और चोरी आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष आज बोल रहे थे। वह एक हजार करोड़ जनता के लिए होना चाहिए, स्कूल बनाईए, आंगनबाड़ी का केन्द्र बनाईए, कौन मना कर रहा है, बजट में जोड़िए सड़क बनाईए। उसको दीजिए। वह सप्लाई में चोरी में कहां जा रहा है ? सी.एस.आर. के पैसे का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ का बजट है, उसके लिए उस पैसे का एडिशनल सपोर्ट में उपयोग होना चाहिए। उसके लिए आपकी कोई नीति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके 30 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके जवाब में जानना चाहूंगा, कितने अंडरटेकिंग प्राफिट में हैं, कितने अंडरटेकिंग में राज्य सरकार को कितना डिवीडेंट दिया है ? आज जो आपका डाटा है, उस डाटा में सिर्फ छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी प्राफिट पर है। राज्य भंडार निगम प्राफिट पर है। अध्यक्ष जी बैठे हैं। उन्होंने कितना डिवीडेंट दिया है, वह बता दें। उन्होंने कितना पास करके कितना डिवीडेंट दिया है, बता दें। अगर उनके प्राफिट में हैं तो कितना डिवीडेंट दिया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- बताना नहीं है, बताना नहीं है, जितना बताओगे उतना मोदी जी कंपनियों को बेच देंगे।

श्री अरूण वोरा :- मैं नहीं चाहता कि भंडार निगम बेचें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नुकसान में हैं तो आप उनको बेचिए ना। आपको किसने रोका है ?

श्री कवासी लखमा :- पूरे देश में उद्योगपतियों को उद्योग बेचा जा रहा है। आधा बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। जमीन को गिरवी रख दिया है। (व्यवधान) उसको बताईए ना।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी पर्यटन मंडल के 12 होटल बेचे हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें कांग्रेस के नेताओं को बेचे हैं। किसी बड़े को लेकर आते। कोई एजेंसी लेकर आते। आप इंडियन होटल लाते, आप ताज की एजेंसी लाते, आप टाटा (व्यवधान) लाते बेचते, वह छत्तीसगढ़ का टूरिज्म प्रमोशन करता। अपनी प्रापर्टी को बेचते तो टूरिज्म प्रमोशन होता। अनुग्रहित करने के लिए मत बेचिए। इसको भी राजीव मितान क्लब मत बनाईए।

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, रेल्वे को क्या हमने बेचा है, एयरपोर्ट को हमने बेचा है, एल.आई.सी. को हमने बेचा ? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप असत्य मत बोलिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मद बताना चाहूंगा। एस.डी.आर.एफ. मद में कितना पैसा खर्च किया ? यह एस.डी.आर.एफ. मद का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण कोष में यह पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। श्रम उपकर, जो श्रम कल्याण मंडल का लगता है, उसमें खाते में कितना पैसा बचा हुआ है, आप खाते के पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप कहां से असत्य का पुलिंदा लाये हैं?

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट को देखकर बोल रहा हूं और एक भी असत्य का पुलिंदा होगा तो आपके सेक्रेटरी बैठे हैं। एक भी असत्य का पुलिंदा होगा तो, एक-एक फिगर सही है और मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट देखकर बोल रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह पढ़े-लिखे लोगों की समझ में नहीं आएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, वह अंग्रेजी में पढ़कर उसको समझकर हिंदी में बोलते हैं। आप जबरदस्ती उनसे पंगा क्यों ले रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- my dear friend, totally false is speaking. all speaking are false.

श्री ननकीराम कंवर :- आप अंग्रेजी में पढ़िये।

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, मैं इस सदन में आपके जैसे और आपकी सरकार के जैसे असत्य नहीं बोलता हूं। एक बोर्ड लगा है उसमें आप लिखे हैं कि आप कितना क्या कर रहे हैं। मैं आपको उस बात को बोलना नहीं चाहता हूं कि केन्द्र से आपके विभाग में कितना पैसा आ रहा है और क्या आ रहा

है। आपके लिए इस सदन का एक-एक मिनट खराब होगा, लेकिन मेरे लिए समय है। आपके लिए टीका-टोकी के लिए खराब होगा, मेरे लिए खराब नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, आप बहुत लंबी-लंबी बात कर रहे हैं। आप केवल इतना ही बता दीजिए कि केन्द्र से यहां जितना बजट फंडेड हो रहा है उसमें केन्द्रांश क्या है और राज्यांश क्या है ?

श्री सौरभ सिंह :- सभी सदस्य का समय निर्धारित है। वह सब जीत कर आ रहे हैं। समय टीका-टिप्पणी के लिए नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की जनता का सदन है। यह छत्तीसगढ़ की जनता की बात का सदन है। यह टीका-टिप्पणी का सदन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप सीधे मुझसे बात कीजिए। मंत्री जी।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुना करिये। पहले केन्द्रांश कितना रहता था और आज कितना दे रहा है ? केन्द्रांश और राज्यांश क्या है ? पहले केन्द्रांश कितना रहता था और अब कितना केन्द्रांश रहता है ?

श्री सौरभ सिंह :- आप जिम्मेदार मंत्री हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप आवास की बात करते हैं, पहले केन्द्र से कितना पैसा आता था और आज कितने पैसे आता है ? आप केन्द्रांश का परसेंटेज बताइये।

श्री सौरभ सिंह :- सुनिये।

श्री अमरजीत भगत :- पहले केन्द्रांश कितना आता था और आज कितना आ रहा है ? आप इसे बताइये, उसके बाद हम आगे बात करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिर्ची लगना स्वाभाविक है। जो मिलिंग का पैसा है वह नहीं आ रहा है इसलिए इनको मिर्ची लग रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सीधे इधर बात कीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र पूरा पैसा नहीं देता है और यह बात करते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम डाटा दे रहा हूं। वित्त सचिव के स्मृति पटल में जो कागज दिया गया है उसमें पेंशन में 12 परसेंट इन्क्रिस हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- गलत है।

श्री सौरभ सिंह :- यह उसको भी गलत बोल रहे हैं। यदि 12 परसेंट इन्क्रिस नहीं हुआ है तो आप अपने सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए। वह डाटा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस ढंग से टीका-टिप्पणी न करें। मैं यहां कोई गलत डाटा नहीं दे रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- दरअसल, आप समाज सुनते नहीं हैं इसलिए आपको सही बात की जानकारी नहीं मिलती है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 साल के बाद आपको 21 हजार करोड़ रूपये पेंशन में देना पड़ेंगे। यह जो आप तरह-तरह की बात कर रहे हैं न, छत्तीसगढ़ की जनता को यह पता चलना चाहिए कि यह जो बजट आ रहा है यह चुनावी बजट है, यह आंकड़े का बजट है, यह गुमराह करने का बजट है और पैसे के दुरूपयोग का बजट है।

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्रीय वित्त मंत्री का 20 हजार करोड़ रूपये का बजट है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अरूण वोरा जी।

श्री सौरभ सिंह :- आपने जितने में दिया, उतने में लिया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी, यह किस तरह की भाषा है ?

श्री अमरजीत भगत :- 20 हजार करोड़ रूपये का घोषणा हुआ था, उसमें कितना मिला ?

श्री सौरभ सिंह :- आप यह बताइये कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- 20 हजार करोड़ रूपये का घोषणा होता है, उसमें कितना मिलता है ?

श्री रामकुमार यादव :- साबर के चोरी अउ सूजी के दान।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय चौबे जी, हमें माननीय अमरजीत भगत भाई साहब से बहुत सहानुभूति है। सी.एम.आर. के लिए जो 1 हजार करोड़ रूपये है उसमें जो भी हो रहा है उसमें सीधे मंत्री का दखल होना चाहिए, उसमें बाहरी तत्वों का दखल नहीं होना चाहिए। हम सब सदन में उनके साथ हैं कि उसको बाहर तत्व मत वसूले और वह सीधे मंत्री के दखल में रहे।

श्री अमरजीत भगत :- आप यह बताइये कि वित्त मंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रूपये की घोषणा की थी उसमें से यहां कितने पैसे आये ? क्या केवल कागज में false घोषणा करने से होता है ?

श्री सौरभ सिंह :- आप यह बता दीजिए कि गरीब कल्याण अन्न योजना में आपने कितना चावल चोरी कर लिया ?

श्री अमरजीत भगत :- आप आवास योजना का बहुत दम भर रहे हैं। उसमें आपका केन्द्रांश क्या है ?

श्री सौरभ सिंह :- आप यह बता दीजिए कि आपने गरीब कल्याण अन्न योजना में कितना चावल गायब किया ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए मन बहस करथे। हवई जहाज अउ साइकिल में चघाथे। 20 हजार करोड़ के बजट में...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- पूरा सदन आपके साथ हैं। पूरा विपक्ष आपके साथ हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप इसको स्पष्ट कीजिए कि आवास योजना में केन्द्र पहले कितना परसेंट देता था और आज कितना दे रहा है ?

श्री रामकुमार यादव :- कोरोना काल मा तुमन दुनिया भर में थारी पिटवात रहे हों। थारी ला पिटो, ए करो, ओ करो।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय वोरा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, अजय चंद्राकर जी के प्रस्ताव से आप सहमत हैं या नहीं हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो आवास योजना की बात कर रहा हूं कि पहले केन्द्र से कितना मिलता था और आज कितना मिल रहा है ? उसमें कटौती क्यों हुआ ? घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं होगा। केन्द्र से कटौती क्यों हुआ ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग छत्तीसगढ़ के इतने हितैषी हैं तो आप लोग 40 हजार करोड़ रूपये का कर्जा छोड़कर क्यों गये ?

श्री सौरभ सिंह :- सिर्फ छत्तीसगढ़ की कटौती थोड़ी न हुई है राजस्थान की भी कटौती हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी जी, इसके बाद आपका भी नंबर है। चलिये, वोरा जी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 घण्टे से।

श्री शिवरतन शर्मा :- वोरा जी, क्या आप बोल रहे हैं ?

श्री अरूण वोरा :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मोहन मरकाम जी से कुछ शिक्षा लिये या नहीं लिये ?

श्री अरूण वोरा :- जी, मैं लिया हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने उनसे क्या शिक्षा ली ?

श्री अरूण वोरा :- मैंने उनसे अच्छी शिक्षा ली है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दूसरी आ गई। दूसरी आ गई करके। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, आपने उनसे शिक्षा क्यों ली ? मोहन मरकाम जी अभी दो दिन से आ ही नहीं रहे हैं। जब से बयान छपा है कि वह सरगुजा वाला बनने वाला करके।

श्री ननकीराम कंवर :- आया था बेचारा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, इन्होंने कहा कि इन्होंने उनसे शिक्षा ली है तो मैंने इनसे पूछा कि क्या दूसरी आ गई ?

श्री धर्मजीत सिंह :- यह रायपुर में बता रहे हैं कि मोहन मरकाम जी की फोटो नहीं थी तो ले जाकर वहां अलग से पोस्टर जैसे चिपकाये थे। वहां मोहन मरकाम जी का पुतला जैसे अलग से दिख रहा था। पेंट लगा कर चिपकाये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- विभाग की शुरू करके भाग गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोगों को बृहस्पत सिंह की भी बहुत कमी महसूस हो रही है, उनको खोजवाओ और बुलाओ ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम 2 घंटे से विपक्ष का भाषण सुन रहे हैं । उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है । मुझे तो असत्यता दिखाई दे रही है । इस बात को प्रदेश की जनता भी महसूस कर रही है । जोर-जोर से बोलकर सच को नहीं झुठलाया जा सकता ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भरोसे का बजट है । हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार 5वां भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है । आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। जिसको दो बार प्रथम मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला हो ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- कल तारीफ किये थे, अजय चन्द्राकर जी ने कहा था कि भूपेश है तो भरोसा है । बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मोर से शिक्षा ले ले ।

श्री अरूण वोरा :- मैं आपसे शिक्षा नहीं लेता । (हंसी)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उन्होंने 12-13 बच्चे पैदा कर दिए, तुम क्या करोगे ?

श्री अरूण वोरा :- मुझमें उतना हार्स पॉवर नहीं है । उनका हार्स पॉवर ज्यादा है ।

रविन्द्र चौबे :- परम पूज्य मोहले जी, सब शिक्षा देना, लेकिन वह शिक्षा बच्चों को नहीं देना । परिवार नियोजन लागू हो गया है । आप 12-13 बच्चे पैदा कर दिए, ये कहां से कर पाएंगे ? (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- मेरे में ताकत नहीं है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उसकी शिक्षा मैं दे चुका हूं, वह ट्रेनिंग ले चुके हैं ।

श्री अरूण वोरा :- चौबे जी, मैं पहले ही सरेंडर हो चुका हूं । दो के बाद सरेंडर। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- बगल में शिवरतन जी बैठते हैं, कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि भूपेश बघेल जी को देश में दो बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का खिताब मिला है । अब तो इनको यह मानकर चलना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेताज बादशाह हैं, आप कुछ भी कर लीजिए । भूपेश जी इस प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे भाई साहब संसदीय कार्यमंत्री जी पागा बांध रहे थे। उन्होंने आपकी बात सुनी तो पागा खोल दिए ।

श्री अरूण वोरा :- वे पागा इसलिए बांध रहे हैं कि वे फिर से मजबूती से आएंगे। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है । बजट में जो बातें कही गई है, उसके बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने जिक्र नहीं किया । उनको इस बात को सोचना चाहिए कि इस बजट में पहली बार किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, ग्राम पटेल, कोटवारों, ग्रामीण, शहरी अधोसंरचना और अर्थव्यवस्था के

साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा एवं सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा गया है । आज से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था और लोग इस बात को महसूस करने लग गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं । प्रदेश के लोगों ने 4 साल पहले बहुत विश्वास करके कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी और मुखिया के रूप में भूपेश बघेल जी आये । धर्मजीत भाई, भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके का कार्य किया है, वह आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं । उन्होंने सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा, आपका ध्यान रखा, हमारा ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कितना ध्यान रखा कि अमितेश शुक्ल के दर्शन के लिए हम बेताब हैं, वे दिख ही नहीं रहे हैं । कहां हैं, क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष जी, इस सत्र में मैं देख रहा हूं कि जब से आदरणीय चौबे जी जो ट्रेनिंग देकर भेजे हैं, उपाध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं । माननीय चौबे जी, एक बार शहंशाह अकबर ने अपने बीरबल को रात को खाने में बुलाया और कहा कि बीरबल, भटे की सब्जी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है तो बीरबल बोले कि बहुत अच्छा है, चिकना भी है, चमक भी रहा है, बहुत टेस्टी है । उसके बाद खाना खिलाकर भेज दिए । 15 दिन बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल को फिर से खाने में बुलाया कि बीरबल जी आईए, फिर खाना खाएंगे । फिर भटे की सब्जी लाये और अकबर ने कहा कि ये भटा बहुत बेकार है बीरबल । पैर दर्द करता है । तो बीरबल ने कहा कि बिल्कुल साहब, उसका इतना बड़ा पेट भी है, उसके सिर में जो ताज है, उसमें कांटा भी है । तो अकबर ने बड़ा ताज्जुब किया कि अभी 15 दिन पहले बीरबल भटे की तारीफ कर रहा था और बड़ी बुराई कर रहा है । अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम तो 15 दिन पहले भटे की तारीफ किये थे तो बीरबल ने कहा कि जी हां साहब, तारीफ किया था । अकबर बोले कि अभी आप बुराई कर रहे हो तो बीरबल बोले कि जी हां साहब, बुराई किया था । ऐसा क्यों ? बीरबल बोले कि साहब, मैं भटे की नौकरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूं । जो आप बोलोगे, वही बोलूंगा । अच्छा बोलोगे तो अच्छा बोलूंगा, बुरा बोलोगे तो बुरा बोलूंगा । (हंसी) अभी इस तरफ से यही चल रहा है ।

श्री अरूण वोरा :- ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, बाकी का तो समझ में आ रहा है । आप किधर हैं ?

श्री अरूण वोरा :- आप किधर हैं ? आप क्या सोच रहे हैं, वह मैं बिलकुल नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि केन्द्र सरकार ने 4 साल तक कितनी भी अड़चने लगाई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं नहीं डिगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दम पर अपनी योजनाएं बनाईं। अभी आपने सुना कि कहीं से लोन नहीं लिया गया है। जब हम लोग विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुना करते थे कि कई हजार करोड़ रूपये का लोन लिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बगैर लोन लिए, जैसा हमारे पाण्डे जी ने कहा कि अपने दम पर यह सरकार काम कर रही है

और आगे भी काम करेगी। तो ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने में यह राज्य अग्रणी रहा है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय नारायण दास जी बोलकर पूरे लोग सदन से चले गये, आपके यहां कोई सुनने वाले नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आज ब्रम्हकुमारी संस्थान में गये थे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इसीलिए तो मैंने उनको नारायण दास जी कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय चरणदास जी थे। उन लोग चरणदास की तरह इनको नारायण दास जी बना दिए। जो भी वक्ता आते थे, इनको बार-बार नारायण दास जी, नारायण दास जी कहते थे। इसलिए आज से इनको नारायण दास मान लिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, वोरा साहब।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, ये धर्मजीत भाई मुझको भटका देते हैं। बहुत सीनियर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बजट पर आईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप भटक क्यों रहे हैं, अरूण जी आपका मन नहीं भटकना चाहिए।

श्री अरूण वोरा :- युवा मन है, कभी भटक भी सकता है। क्यों धर्मजीत भाई ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके पूरे परिवार में बाबू जी का भी, बहुत सम्मान कर रहा था और आपका भी सम्मान करता हूं। हम तो चाहते है कि आपके बाबू जी के सरीखे नाम दिल्ली तक हो। लेकिन, आप वहीं से नहीं उठ रहे हो।

श्री अरूण वोरा :- आपका आशीर्वाद रहेगा तो उठ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, 10 मिनट हो गया है। समाप्त करें। अब अगले वक्ताओं के लिए 10 मिनट का समय रहेगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाएं हैं। हम लोग पिछले सत्र में थे तो किसानों की आत्महत्या का समाचार सुनते थे। उस समय धर्मजीत भाई नहीं थे, 4 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन अभी हमारी सरकार आई है, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, आप कहीं भी आत्महत्या की घटना नहीं देखेंगे। मैं कृषि मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार उस योजना को मूर्त रूप देने में दिन-रात लगे हुए हैं, जिसका फायदा हमारे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। नरवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी के बारे में बात करते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ आगामी समय में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आज प्रदेश के कर्मचारी प्रसन्न हैं। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पाण्डे जी कह रहे थे कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 10 हजार रूपया..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आप ही का भाषण सुनने के लिए आया हूं।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण तो अब खत्म होने को आ रहा है। मैंने आपकी प्रशंसा की है कि आज आपने बहुत सत्य बात कहा है। लेकिन प्रदेश की जनता उसको असत्य मान रही है। आप इतने जोर-जोर से बोलेंगे तो नहीं मानेगी, आप कुछ ज्यादा चिल्ला दिए। कमजोर दिल वाले भी रहते हैं। आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका दिल कमजोर हो गया है ? आप एक सत्र में बोले थे कि मैं उत्तेजित रहता हूं और अभी दिल कमजोर हो गया है, बोल रहे हो।

श्री अरूण वोरा :- अभी आप नहीं थे, अभी रविन्द्र चौबे जी, मामा जी के बारे में कह रहे थे। रविन्द्र भाई, मामा जी के बारे में बोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको उत्तेजित होना बता दूंगा। उत्तेजित होने का ढंग वही है न। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- आप अभी भी उत्तेजित होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, ये कौन से डॉक्टर की सलाह लेते हैं ? अच्छा पोट-पोट होता है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, मैं इस बजट के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, सभी ने बजट पढ़ा है, सुना है और कार्यरूप में परिणित होते हुये भी देखा है । यह बजट इतना लोकप्रिय था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट के बारे में बोल रहे थे तो हमारे विपक्षी नेताओं को इतना अच्छा लग रहा था कि "चू" तक नहीं बोले हैं । ये बजट छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं की बजट है, ये बजट छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है, इस बजट में जो बातें कही गई है, बजट में जिन नियमों के क्रियान्वयन की बात कही गई है, वह पूर्ण रूप से संविधान के भाग (3) और भाग (4) को पालन करते हुये बनाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट लक्ष्मी जी । आय-व्ययक के सामान्य चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की सूची है, अभी केवल 4 सदस्य ही अपनी बात रख चुके हैं, 17 और सदस्यों को अपनी बात और रखनी है । समय को देखते हुये वक्ताओं से अनुरोध है कि 10-10 मिनट में अपनी बात रखें । सभी से सहयोग की अपेक्षा है । डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अपन सिहावा के बजट मा का-का मिले हे, तौन ला बखान करबे तव बहुत अच्छा रहि ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- विधायक महोदय, आ रही हूँ ना । आप मेरा टाईम खराब मत करो ना । हम लोगों को कम टाईम मिलता है । उसी में ही बात रखनी है । उपाध्यक्ष महोदय, जब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, केन्द्र सरकार से तुलना की जाती है, चाहे सकल घरेलू उत्पाद की बात हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, चाहे राज्य के राजस्व की बात की जाये, निश्चित तौर से केन्द्र की अपेक्षा राज्य के बजट की स्थिति बहुत अच्छा है, सुदृढ़ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो रहा है, छत्तीसगढ़ी मॉडल को पूरा देश जो है, वह स्वीकार कर रहा है और छत्तीसगढ के लोग बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं । इस बजट में किसानों के लिये, महिलाओं के लिये, किसान कल्याण के लिये, चाहे लोक निर्माण की बात कहें, चाहे पुल-पुलिया की बात हो, चाहे नवयुवकों की बात कहें, चाहे अधोसंरचना की बात हो, चाहे नगरीय निकाय की बात हो, ग्रामीण एवं पंचायत की बात हो, सभी के लिये विकास की बात कही गई है, वह बिल्कुल सच है और इस सच्चाई से कोई आंख नहीं मोड़ सकता । उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये जो बजट पारित किया गया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कहें और उसके आधार पर 9 हजार आदान जो किसानों की जरूरत थी, इसी 9 हजार के सहारे किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल रहा है । इससे किसान अपनी अन्य योजनायें बना रही है । चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे कोदो, कुटकी, रागी के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे भूमिहीन किसान योजना की बात हो, चाहे गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई हो, किसान को इस बजट में सबसे ज्यादा मजबूत बनाया गया है । उसके लिये गुणवत्तायुत जैविक एवं रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भी राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की बात कहें, चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में भी नवीनतम तरह से करने की बात कहें, चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में भी नवीनतम तरीकों के प्रदर्शन करने की बात कहे, इसके लिये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। हाई-टेक नर्सरी एवं छुईखदान और गंडई में पान अनुसंधान केंद्र की बात कहे, चाहे कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन की बात कहे, चाहे छात्रावास निर्माण की बात कहे, इसको आगे अनुसंधान करने के लिये, चाहे किसानों की सुविधा के लिये किसान सुविधा केंद्र की बात कहे, चाहे राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला की बात कहे, इन सारी चीजों को इसलिये लिया गया है ताकि किसानों का ऋण माफ करके उनको आगे बढ़ाने का जो रिस्क लिया है, नौ हजार रूपये आदान राशि देकर, ताकि किसान को धीरे-धीरे मजबूत बनाये, ताकि छत्तीसगढ़ का व्यापार व्यवसाय भी फले-फूले और यहां का हर वर्ग आगे बढ़े और उनको पुन: इस चीज की आवश्यकता न पड़े कि उनका ऋण बार-बार माफ किया जाये, उनकी कीमत उनको बराबर मिलनी चाहिए इसके लिये हर

संभव हर तरह से किसानों को सहायता देने का काम हमारे माननीय मुखिया ने किया है। इसके लिये मैं सिहावा विधान सभा की ओर से, ऐसे ही कोई भी मुख्यमंत्री बने, किसानों के लिये ऐसा ही कार्य करें क्योंकि इस प्रदेश में हर व्यक्ति किसानी काम से जुड़ा हुआ है। उनका कहीं न कहीं किसानी कार्य से रिश्ता है तो इनको और कभी नीचे न ले जाये, हमेशा ऊंचा और आगे बढ़ाने का कार्य करें। आजकल तो तरह-तरह की मजबूत खेती की जा रही है, चाहे फसल हो, चाहे सब्जी हो, आधुनिक तरीके से यदि वह जैविक खाद के माध्यम से खेती करते हैं तो निश्चित तौर से किसान बहुत आगे बढ़ेंगे बहुत तरक्कती करेंगे। यदि इस चीज के लिये किसी ने सोचा है तो माननीय भूपेश बघेल। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा है और उनके इस कदम की पूरे राष्ट्र ने प्रशंसा की है।

दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की दिशा में भी काम किये हैं। अभी हमारी सारी बहनें, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे मितानिन हो, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चाहे रसोईयां हो, सब लोग हड़ताल पर बैठे थे। उनको भी लग रहा था कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ भी हमारे माननीय मुखिया ने न्याय किया है। सभी के वेतन और भत्ते को बढ़ाया गया है और उनके जब वेतन और भत्ते की बढ़ोत्तरी को डिक्लियर किया गया तो उनकी खुशियों को कोई ठिकाना नहीं था। आप टी.व्ही. में देखे होंगे, व्हाट्स एप में देखे होंगे, वे कितने खुश होकर, उछल-कूद और गाना के साथ माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया है। उनको भी लगने लगा है कि यह सरकार ही हमारे साथ न्याय कर सकती है क्योंकि पिछले कई सालों से वह मांग कर रहे थे लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। यदि इनके साथ न्याय करने का काम किसी ने किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इसके साथ ही साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी वेतन बढ़ाया गया है, संस्थागत प्रसव का भी पैसा बढ़ाया गया है। यह एक मूल बात है जो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिये आवश्यक है। वर्षों से, सदियों से कोटवार, जो गांव की सुरक्षा करते हैं, जो गांव की सरकारी प्रशासनिक तंत्र, कोई भी आते थे, उनके लिये सूचना या उनकी सेवा, कार्य संपादित करते थे, उनके लिये भी उन्होंने न्याय किया है। उन्होंने ग्राम पटेलों के लिये भी न्याय किया है। साथ ही साथ स्वावलंबन गौठान समिति के माध्यम से गौठान समिति के जो अध्यक्ष है, उनको भी 750 रूपये देने की बात कही है और उनके सदस्यों को 5 सौ रूपये। ताकि हमारा जो गौठान है, एक दिन एक कुटिर उद्योग का रूप ले सके और गांव के नागरिक कहीं भटके नहीं, गांव के नागरिक कहीं पलायन न कर सके, उनको खेती के साथ-साथ इससे भी आमदनी मिले और गांव के सारे व्यक्ति खेती के साथ-साथ इसमें रम जाते हैं। इससे किसी भी प्रकार की पलायन जैसी समस्या नहीं रहेगी और सबको रोजगार मिलेगा। मैं पशु चिकित्सा क्षेत्र की बात कहूं तो हमारे यहां खेती के साथ-साथ हर किसान पशु पालन भी करते हैं और पशु की रक्षा की स्थिति आप देख चुके हैं। पहले गौ-सेवा आयोग होता था, उनकी क्या कहानियां है, उसको आप सब लोग पेपर में पढ़े हैं, आये दिन पढ़े हैं। यहां तक उनकी हड्डियां भी नहीं बची थी, उनका चारा भी नहीं बचा। लेकिन हमारे माननीय मुखिया ने जिस

तरह से गौठान, जिस तरह से गरूवा की बात कही है, उन्होंने उसी तरह से पशु गृह और पशु पालन के लिये भी व्यवस्था की हैं। 25 नये पशु औषधालयों के साथ-साथ 14 पशु औषधालय का उन्नयन किया गया है।

समय:

6.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17 नवीन पुश रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्पलेक्स का भी निर्माण किया है ताकि हम पशु पालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। जैसे उनको धान से आमदनी होती है वैसे ही इनकी भी आमदनी हो सके। जो पशु हैं वह उन्नत किस्म के हों, उससे उनको आमदनी मिले। एक तरह से किसानों की आमदनी पशु पालन के माध्यम से भी बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी तरह से उन्होंने मछली पालन के लिए भी प्रयास किया है। बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जायेगी। मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, आपके सरगुजा में मानसिक चिकित्सालय खुल रहा है, उस पर बहुत चर्चा हुई। आप उस समय नहीं थे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- रायपुर की चर्चा नहीं हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :-नहीं-नहीं। हमने तो एक को पाटन में खोलने की मांग की हैं और सरगुजा में कोई जरूरत नहीं है, यह बोले। उनका दिमाग तो ऑलरेडी उड़ गया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं जल संसाधन के विकास के बारे में कहूं तो मेरा क्षेत्र जो है ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- महत्वपूर्ण बात यह है यह प्रस्ताव आपका है या अमरजीत जी का प्रस्ताव है। यह सदन के सामने स्पष्ट होना चाहिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोंढूर, मॉडनसिल्ली, दुधावा यह तीन बड़े जलाशय हैं और वहां भी वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना हो, चाहे मध्यम सिंचाई योजना हो, चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे एनीकट स्टॉप डेम की बात हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण के संबंध में बात हो, इसको बढ़ावा दिया है और मेरे क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसमें बजट दिया है मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहती हूँ। उसी तरह से छत्तीसगढ़ का शौर्य नई दिल्ली में भी बढ़े, उनका भी गौरव बढ़े उनका नाम हो, इसलिए उन्होनें चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ की व्यवस्था हेतु प्रावधान किया है। मैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में कहना चाहूंगी। मेरे यहां बहुत सारी आपदा प्रबंधन की समस्याएं हैं क्योंकि वहीं से महानदी निकलती है और उसके लिए भी बजट दिया

है यह बहुत अच्छी बात है। ई-धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से पुन: सर्वेक्षण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। मैं जनसंपर्क विभाग के बारे में कहूं तो पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ हैं उनके हित का भी ख्याल रखा है और पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत 25 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। चूंकि मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जंगल क्षेत्र है वन अधिकार, वन पट्टा, वन संसाधन अधिकार दिया है तो वहां जो अधिकार दिया है तो समितियों को कैसे सुदृढ़ किया जाये, उसके लिए भी माननीय मुखिया ने बजट दिया है ताकि जो अधिकार दिये हैं उसको वहां की जनता उसका उपयोग करे, विकास करे, उससे उनको आर्थिक लाभ हो, इसके लिए प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी जी, अब आप समाप्त करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और चाहूंगी। मैं संस्कृति और पर्यटन की बात कहूं तो मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी ताकि हमारे विद्यार्थी अपने इतिहास को जाने। विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान की सुविधा दी जायेगी। उसी तरह से चंदखुरी जिला-रायपुर में कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। रामलीला का मंचन किया जायेगा। मानस गान और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है क्योंकि आप देख रहे हैं गांव-गांव में मानस गान बहुत लोकप्रिय हो गया है। हर गांव में चाहे महिला हो, बच्चे हों, पुरूष हों, चाहे बूढ़े हो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनमें ऐसे बहुत सारे संस्कार की बातें बतायी जाती हैं उसको बहुत ध्यान से सुना जाता है। तो यहां पर भार

मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कहूं। अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खोला गया है तो आगे चलकर बच्चे कैसे पढ़ेंगे ? उसके लिए 04 इंग्लिश माध्यम के कॉलेज खोले जाएंगे और 04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय और कुल 23 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। ताकि स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे पढ़कर आगे बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर स्थापित हों। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है, वह बहुत ही सुन्दर प्रयास है क्योंकि भिलाई शहर के बहुत हिन्दी माध्यम के स्कूल बंद हो रहे थे और लोगों की मांग हो रही थी जो यहां पैसे वाले अमीर लोग हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े और हमारे बच्चे हिन्दी माध्यम में पढ़े तो स्कूल की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। जब मैं विधायक बनकर आई तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 स्कूल ऐसे थे जो dismantle करने लायक थे। 150 स्कूल ऐसे थे जिनकी मरम्मत करने की आवश्यकता थी। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा बजट दिया है। मैंने भी विधायक निधि से, डी.एम.एफ. फंड से स्कूल बनवाया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा की ओर जो ध्यान दिया गया है, अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ रही थी, उसको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण जनता के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरे घर में भी एक बच्चा पढ़ता है। उसका सिलेबश भी बहुत अच्छा है। उसके टीचर भी बहुत अच्छी पढाई करा रहे हैं। अगर आरक्षण बिल में हस्ताक्षर हो जाता है तो वहां की व्यवस्था को और दुरस्त, सुदृढ़ करना है, वह हो जायेगी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल्पना की है, छत्तीसगढ़वासियों को दिया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं सिहावा विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे यहां भी 02 स्वामी आत्मानंद स्कूल बने हैं, वह बहुत ही सुंदर बना है। लोग उसको देखते हुए थकते नहीं हैं और सब वहां इंट्रेस्ट से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री भूपेश बघेल जी की सरकार का यह पांचवा और अंतिम बजट है। माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने बजट भाषण की शुरूआत की है, उस बजट भाषण का जो पहला पैरा था उसमे लिखा है कि- प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चार वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खराब उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वयं को संतोष हो रहा है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। मैं उनके पहले पैरे में ही आता हूं। पहला बिन्दु " गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में इनने उल्लेख किया है कि किसानों को 06 हजार 22 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है । हमारे दो वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। एक तो जन-घोषणा पत्र के जनक हैं और दूसरे कृषि मंत्री जी हैं। मैं अपनी चर्चा की शुरूआत किसानों से ही करता हूं। अपने जन-घोषणा पत्र में किसानों के लिए 03 घोषणायें प्रमुख रूप से की थी। जन-घोषणा पत्र की कापी है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, डॉ. रमन सिंह की सरकार जो दो साल का बोनस नहीं दे पाई, वह बोनस हम देंगे और 2500 रुपये क्विंटल में किसानों का धान खरीदेंगे। मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या आपने पूरे किसानों का कर्ज माफ कर दिया ? आपने पूरा कर्ज माफ करने की बात की थी। सिर्फ सहकारी समितियों का अल्पकालीन ऋण माफ किया, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने ऋण लिया, उन किसानों का 40 प्रतिशत पैसा माफ हुआ, बाकी पैसा माफ नहीं हुआ, लोगों को पटाना पड़ा। तो जो लोग बोलते हैं न कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो छत्तीसगढ़ को धोखा है। भूपेश है तो छत्तीसगढ़ में छल है। ये सरकार है तो छत्तीसगढ़ में फरेब है। ये सरकार है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जालसाजी है।

आपने किसानों की कर्ज माफी में जालसाजी की। कांकेर में आपके नेता का भाषण हुआ था। डॉ. रमन सिंह बोनस नहीं दे पाये, हमारी सरकार बनेगी तो हम बोनस देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, घोषणा पत्र में सभी दल अपनी-अपनी बात कहते हैं। कुछ काम अगर रूक गया होगा तो जालसाज कहना उचित नहीं है। क्योंकि देश ने देखा है कि मंहगाई कम करने का वादा भी कुछ लोग किये थे। 02 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी बात किये थे। क्या आप उनको जालसाज कह दोगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनके नेता दिल्ली में उस विषय पर चर्चा करें न, किसने रोका है? आपके जिले में ही सभा हुई थी। डॉ. रमन सिंह ने दो साल का बोनस नहीं दे पायें, हम देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आज ऑस्कर अवार्ड शो में नाटू-नाटू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है तो छत्तीसगढ़ से इनके जो तीन छत्तीसगिढ़या सांसद गये हैं, वह दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं या नाटू-नाटू कर रहे हैं, आप यह बताईये? (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- बोलते हैं, लेकिन माईक बंद हो जाता है।

श्री अजय चंद्राकर :- तैं हर फेर दादागिरी करबे।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस दो साल के बोनस का क्या हुआ? यह तो अंतिम बजट है। आपने दो साल के बोनस का प्रावधान किया है क्या? तीसरा विषय, किसानों को धान की कीमत 2500 रूपये देना। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं। जिस समय आपने घोषणा की थी। धान का समर्थन मूल्य 1750 रूपये था। केन्द्र सरकार ने लगातार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो धान के समर्थन मूल्य को केन्द्र ने बढ़ाया। आप उसको अपने खाते में क्यो जोड़ रहे हैं। इस साल आपको किसानों को 2800 रूपये देना चाहिए था, क्योंकि 2040 रूपये तो केन्द्र ने समर्थन मूल्य दिया है। आप छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। आज तक समझ में ही नहीं आया कि छत्तीसगढ़ का कौन सा मॉडल है। हम लोगों को तो लगता है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल घोटाले का मॉडल है, माफियाओं का मॉडल है, लूट का मॉडल है। लूट का इतिहास बनाने का काम यह सरकार कर रही है। आज क्या हो रहा है? कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया, यही छत्तीसगढ़ का मॉडल बना है क्या? और अब तो एक और नया माफिया पैदा हो गया, गोबर माफिया और गौठान माफिया। छत्तीसगढ़ मॉडल माफियाओं का मॉडल बनकर रह गया है। आज गोबर खरीदी को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था। माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक बयान आता है कि हमारे यहां के चरवाहे गोबर गोधन योजना से इतने प्रसन्न हैं कि भाषण में कहते हैं कि हमारे यहां का चरवाहा भी 30 से 35 हजार रूपये कमा रहा है। मोटर-सायकल खरीद रहा है। मैं दूर की बात नहीं करता हूं। यहां

हमारे तीन वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। आपके विधान सभा में एकाध चरवाहा बताईये, जिसने गोबर बेचकर 30-35 हजार रूपये महीना गोबर बेचकर कमाया हो और मोटर-सायकल खरीद लिया हो।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- हमारे विधान सभा में है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आप तीनों मंत्रियों से ही निवेदन कर लेता हूं। सिर्फ गप्प मारना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोरोजगारी भत्ता। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नहीं तो ढाई हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। माननीय अजय चंद्राकर जी ने उस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखा है। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैक्स लगा था, उसमें लिखा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार से साढ़े तीन वर्षों में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। बिलासपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण हुआ, उसकी क्लिपिंग मैंने पहले प्रस्तुत करने की बात की थी। मुझे उसकी अनुमति नहीं मिली थी। 2 लाख 40 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। बिलासपुर में भाषण हुआ था।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम दोनों मंच में थे। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन भाई, तुमन आपस में तय कर लेवा कि 3 बोलना हे या 5 बोलना हे। क्या तय हुआ था? तय हुआ था उसके हिसाब से आप बात करिये न। कोई 3 बोलता है, कोई 5 बोलता है। का बोलना हे, एला तय करके तो तुमन आय करा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज विधान सभा में मेरा और धरमलाल कौशिक जी का प्रश्न था। प्रश्न के जवाब में आया है कि 4 साल में 20,292 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है और अभी इसी सत्र में मेरा प्रश्न था तो माननीय उमेश पटेल जी का जवाब आया कि हमने 4 साल में 33,333 लोगों को शासकीय कार्यों में समायोजित किया है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले लोग, 33 हजार लोगों को रोजगार दे पाये। अब आज ढाई हजार रूपये देने की बात हो रही है। उसमें भी इतने नियम-शर्तें बना दी गयीं कि जो पंजीकृत हैं उनको तो अब बेरोजगार मानना भी बंद कर दिया । पहले जब हम प्रश्न करते थे कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है तो उसमें संख्या लिखकर आती थी कि इतने पंजीकृत बेरोजगार हैं लेकिन अब क्या लिखा जाता है कि इतने लोगों ने रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन किया है, उनको बेरोजगार नहीं मानते । यह भाषा बदल गयी ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शिवरतन भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को देने की बात की थी उसमें से कितना इम्प्लीमेंट हुआ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आपके 3 सांसद नाटू-नाटू कर रहे हैं ? अब वे नाटू-नाटू कर रहे हैं तो आप लोग वहां तबला बजाने चले जाओ ।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, मैं वह नहीं बोल रहा हूं । मैं यह बोल रहा हूं कि 2 करोड़ की हर साल की बात हुई थी तो कितने लोगों को मिला ?

श्री शिवरतन शर्मा :- तो उसका जवाब तो सदन में आयेगा न । इनके तीनों सांसद कर क्या रहे हैं भई ? और नहीं कर रहे हैं तो वे नाटू-नाटू कर रहे हैं, तबला बजाने के लिये अमरजीत भगत जी को भेज दो । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता...।

श्री धर्मजीत सिंह :- 3 सांसद भी बहुत जोरदार हैं भैया । एक बंबई वाला है, एक बिहार वाला है और एक तो सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आया था । शिवकुमार डहरिया जी सर्टिफिकेट लेकर गये थे । वकील साहब का, के.टी.एस. तुलसी जी का आप ही ले गये थे न । सर्टिफिकेट लेने नहीं आये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह अपनी सुरक्षा के लिये पहुंचा के आये हैं भैया । कल केस बनेगा तो वही इनकी जमानत लेंगे, वही इनकी ओर से लड़ेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई लोग प्रेक्टिस करके रखे थे गमछा रखकर ऐसे इधर वाला कि हम बनेंगे करके लेकिन गये काम से ।

श्री अमरजीत भगत :- आप ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया है । बजट भाषण के नवें पाइंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और बड़े जोरदार तरीके से सत्तापक्ष के लोगों ने टेबल थपथपाई कि हम पेंशन को साढ़े 300 से बढ़ाकर 500 रूपये कर रहे हैं । माननीय राजा साहब, साढ़े 300 को 500 में मेज थपथपा रहे थे और आपने 1000 लिखा है । आप इस विषय में क्या कहेंगे ? क्या आप कुछ कहेंगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी । हमारे पांडे जी बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी का पेमेंट बढ़ा दिया गया है । एक में 10,000 रूपये किये हैं न ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल में पूछ चुके हैं उसी को फिर बोल रहे हैं । डबल-डबल रिपीट कर रहे हैं। आप इनको 10 मिनट का समय दीजिये, 10 मिनट से ज्यादा मत करिये । इसमें 11 मिनट नहीं होना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या ये शिवडहरिया जी आपको निर्देशित करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं । ऐसा असत्य बोलने वालों को ज्यादा समय मत दीजिये, यही तो कह रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने 10,000 रूपये करने की घोषणा की । आपके जनघोषणा पत्र में क्या था ? आपने जनघोषणा पत्र में कहा था कि इनको कलेक्टर दर दिया जायेगा । कलेक्टर दर का क्या हुआ ? कलेक्टर दर कितना है ? इनको नर्सिंग व्याख्याता के रूप में प्रमोट किया जायेगा, आपने कितने लोगों को प्रमोट किया है ?

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन भाई क्या 10,000 रूपये दे रहे हैं तो क्या इसमें आपको आपत्ति है ? आपत्ति है तो स्पष्ट बोलिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो यह सरकार अपने बजट के माध्यम से धोखा दे रही है । रसोईयों का 300 रूपये बढ़ाया गया । आपकी घोषणा क्या थी कि सारे नियमित, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी सबको रेगुलर करेंगे, आप 300 रूपये बढ़ाकर के क्या छत्तीसगढ़ के उन हजारों रसोईयों को धोखा नहीं दे रहे हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप होमगार्ड का 6300 से बढ़ाकर 6420 रूपये वेतनमान कर रहे हैं, क्या मजाक है ? केवल होमगार्ड ही नहीं, प्रदेश की पुलिस के साथ भी मजाक किया गया। जनघोषणा पत्र में तो बहुत सी घोषणा थी कि साप्ताहिक छुट्टी देंगे, आवास की व्यवस्था करेंगे, भत्ता बढ़ायेंगे । आपने क्या किया ? मेरा विधानसभा में प्रश्न था कि साप्ताहिक छुट्टी होगी तो कितने लोगों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगी और जो बल की कमी होगी उसकी पूर्ति कैसे होगी ? दो बार लगाया, दोनों बार अस्वीकृत होकर आ गया यानी सामान्य जनता के साथ-साथ आपने छत्तीसगढ़ के पुलिसवालों को भी, होमगार्ड को भी धोखा देने का काम किया है । हां, इस बजट में एक काम जरूर हुआ है कि अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तनख्वाह बांध दो। गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये । गौठान समिति छत्तीसगढ़ में बनी कैसी हैं? गौठान समितियों का कंसेप्ट भी यह दिया गया था कि ग्रामसभा से प्रस्ताव आयेगा और ग्राम सभा से जो प्रस्ताव आयेगा, उसमें प्रभारी मंत्री नाम छांटकर गौठान समिति घोषित करेंगे। इस सदन में चर्चा हो चुकी है। ग्रामसभा में प्रस्ताव भेजा, पर गौठान समिति बनी किनकी? वो ग्राम सभा के प्रस्ताव किनारे रख दिये गये। अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समिति इनने घोषित कर दी और यह वास्तव में गौठान समिति को रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, ये अपने कांग्रेस के कार्यकताओं को 500 रूपये महीना और 700 रूपये महीना देने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या इससे छत्तीसगढ़ का भला होगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 25000 रूपये से बढ़ाकर 50000 कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला आपत्ति हे का भाई?

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा आपत्ति है।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब ला पइसा मिलथे, तेमा आपत्ति हे?

श्री शिवरतन शर्मा :- के ठिन बिहाव करहौ, जरा ए बता देवौ? माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां शादी-ब्याह मुहूर्त में होते हैं। कभी कोई बिना मुहूर्त के शादी करता है क्या? अभी होलाष्ठक लगा था होली के पहले।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका 15 मिनट हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- और महिला बाल विकास मंत्री ने शादी का कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसी शादियां भी हो गईं जो एक बार पहले शादी हो चुकी थी, उसे दोबारा बैठाकर शादी कर दी गई। (शेम-शेम की आवाज) केवल पैसा निकालना। केवल भ्रष्टाचार करना, इसके लिए आपने काम किया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। पहले हर ब्लॉक में फूड पार्क के स्थापना की बात थी, अब आप शहरी क्षेत्र में आप औद्योगिक पार्क बनाने वाले हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बनायेंगे न।

श्री शिवरतन शर्मा :- 5 साल में कितने फूड पार्क बना लिये। जब चुनाव के समय औद्योगिक पार्क बना लोगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 15 साल में के ठन बनाये रहे हो। कुछ करे हो का?

श्री शिवरतन शर्मा :- हमन घोषणा ही नहीं करे रहन। तुमन तो घोषणा करथौ न तो पूरा करवौ न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप घोषणा करेव रहेव कि जरसी गाय देबो करके। ननकी राम कंवर जी ला आज तक गाय नहीं मिले हे। बेचारा देखथे। जरसी गाय मिलिसी ना? बता दे। ननकीराम कंवर जी हा बता देवे। गेरूवा भर धरके बेचारा हा खोजथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये कुछ कर नहीं सकते। पर सिर्फ घोषणा। औद्योगिक पार्क बनायेंगे। दुर्ग तक लाइट मेट्रो शुरू करने का प्रस्ताव है।

श्री रामकुमार यादव :- डीजल नहीं अब खाड़ी से और डीजल मिलेगा बाड़ी से। तूही मन कहे रहव।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनना, अगर गड़बड़ होये रहिस तो वो समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री रहिस। कार्यवाही काबर नहीं करव भाई? मिली-भगत रहिस का? ए कारण कार्यवाही नहीं करथव का? माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ हो नहीं सकता। पर बजट में पढ़ा गया कि हम लाइट मेट्रो शुरू करेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात की गई। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके नाम से जो संस्थान यहां संचालित हो रहा है, वह संस्थान भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। डी.एम.एफ. से ज्यादातर खरीदी आत्मानंद स्कूल में हो रही है और वहां सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो संविदा नियुक्ति हुई है, आप जांच कराकर देख लीजिए। केवल पैसा लो और पैसा लेकर लोगों को सर्विस दो। यह काम किया जा रहा है। माने स्वामी आत्मानंद जैसे महान व्यक्ति के नाम को भी बदनाम करने में यह सरकार पीछे नहीं रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। सेन्ट्रल की स्कीम है। आपका क्या है इसमें?

श्री रामकुमार यादव :- अच्छा होही तो तुम्हर हे, जतका खराब होही ते हमर हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका तो 40 प्रतिशत ही है। 60 प्रतिशत तो सेन्ट्रल देने वाला है। यह सेन्ट्रल के स्किम के अंतर्गत ही बनना है। कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। मैं आपसे ही पूछता हूं कि 4 साल में आपने कितना विद्युत उत्पादन बढ़ाया है? जरा, आप यह बता दो। 4 साल में विद्युत उत्पादन कम हुआ है। अब आप नई स्थापना की बात कर रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का उल्लेख है। माननीय बाबा साहब, प्रत्येक परिवार को एक रूपए में 35 किलो चावल देने का उल्लेख है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अरे, फ्री में दे रहे हैं भइया । एक रूपया भी नहीं ले रहे हैं । आप क्यों चिंता कर रहे हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके आर्थिक सर्वेक्षण में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में 9 लाख 22 हजार सामान्य कार्ड बने हुए हैं जिनको आप 10 रूपए प्रति किलो में चावल दे रहे हैं । आपकी घोषणा 1 रूपए किलो में देने की थी लेकिन आप दे कहां रहे हो ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, इसमें लिखा है । कहां है, क्या है । पूछते भी [XX] आनी चाहिए । कहां है पूछता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सबको थोड़े ही मिलेगा, तुमको भी मिल जाएगा क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रत्येक परिवार को एक रूपए किलो में चावल देने की घोषणा और इनके आर्थिक सर्वेक्षण में स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- घोषणा में ये अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं। इनको एक रूपए में चाहिए तो दे देंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- पेपर के बात ला नइ पतियाव ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- गरीब परिवार मन ला मिलेगा चावल ।

श्री लखेश्वर बघेल :- वह चावल गरीबों के लिए है, आप जैसे धन्ना सेठ लोगों के लिए 10 रूपए किलो वाला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना की शुरूआत की ।

श्री रामकुमार यादव :- ये थारी अउ लोटा ला कौन पिटवाय रिहिस हे ? सफ्फा थारी टूट गे । अइसे प्रधानमंत्री, वो सूजी के सेती थारी ला पिटवाय रिहिस ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रत्येक परिवार के व्यक्ति के पीछे 5 किलो चावल फ्री में देने की योजना है । उसमें भी भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया ।

डॉ. रशिम आशिष सिंह :- वह झोला में अपनी फोटो छपवाकर चावल दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का अगर एक सदस्यीय परिवार का कार्ड बना है तो उसको 10 किलो चावल मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- 20 मिनट हो चुका है, कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 5 मिनट और । उनको यदि 5 किलो अतिरिक्त मिले तो कुल 15 किलो मिलना चाहिए । लेकिन ये कितना दे रहे हैं, 10 किलो, 5 किलो चावल खा गए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, यहां पर कितना असत्य रिकार्ड करेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- 2 सदस्यीय परिवार है तो उनको 20 किलो का कार्ड है उनको 30 किलो मिलना चाहिए, लेकिन उनको 20 किलो मिल रहा है, उनका 10 किलो खा गए । 3 सदस्यीय परिवार है उनको 35 किलो मिलता है, उनको मिलना चाहिए 50 किलो, लेकिन उनको 35 किलो दे रहे हैं उनका भी 15 किलो खा गए । उपाध्यक्ष जी, 5 हजार करोड़ का घोटाला प्रधान मंत्री अन्न कल्याण योजना में करने वाली ये सरकार...।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह गलत है उपाध्यक्ष जी, इसको विलोपित किया जाए । इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- सपने में देखे रहते हैं, वही राशि को बोल देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आज अभी इनकी पार्टी की मीटिंग है वहां डांट पड़ेगी इसलिए बोलना पड़ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लेता हूं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, विलोपित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चालिए, डायरेक्ट सवाल जवाब न करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- प्रत्येक परिवार का जनधन के नाम से खाता खुलवाए, 500 रूपए लिए और बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ किया गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं 5 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाता हूं तो दर्द होता है । मैं चुनौती देता हूं, सारे लोगों को चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना में एक, दो, तीन सदस्यीय कार्डों में भ्रष्टाचार हुआ है उनको जो चावल मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मैं चुनौती देता हूं, अगर आरोप लगाया है तो उसको साबित करके दिखाओ । नहीं तो माफी मांगों । [XX] बात करते हो आप । जितना आवंटन मिला, उतना वितरण हुआ है । [XX] बात करते हैं आप । [XX] बात करते है । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- एक दिन प्रश्नकाल में आया था कि केवल 72 हजार परिवारों ने चावल नहीं लिया । (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- ऐसा आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, मैं आपका दर्द अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा कोई दर्द नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर किसान का चेहरा चमक रहा है तो आपका दर्द झलक रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी की पीड़ा वे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं । उनके विभाग में उनकी चलती तो है नहीं, फाइल कहीं और जाती है, पैसा कहीं और जाता है ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर इनमें दम है तो प्रमाणित करें । अगर वह गलत होगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये तो केवल नाम के मंत्री रह गए हैं । इनके विभाग का संचालन कहीं और से हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया बजट पर बात करें । इधर उधर की बात मत करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूं।

श्री ननकीराम कंवर :- चलिए, मैं आपको बतलाउंगा कि कितना गबन किये हैं। चावल देते नहीं हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आपको तो शोभा ही नहीं देता आप इतने सज्जन आदमी हैं कि आपकी तो विभाग में चलती ही नहीं थी । आप तो सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। नान घोटाला किसके राज में हुआ, यह सब जानती हैं, यह सब बताने की जरूरत नहीं है ?

श्री ननकीराम कंवर :- जांच कराईए ना, सब पता चल जाएगा।

श्री गुलाब कमरो :- कंवर जी, आप सीनियर हैं, सबको मालूम है। पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है। आपको बताने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में बात ना करें। माननीय शर्मा जी, आप भाषण जारी रखिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवार इस सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गये और यह बात मैं नहीं कहता। (शेम-शेम की आवाज)

श्री ननकीराम कंवर :- लज्जा करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सरकार के मंत्री आदरणीय टी.एस.सिंहदेव ने जब ग्रामीण विकास मंत्रालय से पद छोड़ा तो इन्होंने जो पत्र लिखा, वह पत्र को सार्वजनिक भी किया और उसमें स्वीकार किया कि लगभग 8 लाख लोगों को मैं प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं करा सका। अगर मेरी बात गलत लगती है...।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सरकार हा इंदिरा आवास के नाम पे पीढ़ी दर पीढ़ी सब के आवास ला बनाय हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- केन्द्र सरकार के गलत नीति के कारण।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, माननीय शिवरतन जी, आप पूरी चिट्ठी पढ़े हो। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, माननीय महाराज साहब ने चिट्ठी में ऐसा लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, 25 मिनट हो गया, अब समाप्त करें। मैं अब अगला नाम पुकार दूंगा।

श्री ननकीराम कंवर :- अगर वह गलत था तो कोई नीति बना लेते ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्य मंत्री जी, महाराज साहब ने जो पत्र लिखा है, वह सार्वजनिक है, आप बोलो तो पत्र की कॉपी आपको अभी यहीं उपलब्ध करा देता हूं, कंटेंट पढ़कर बता देता हूं कि उन्होंने जो लिखा है, वह कॉपी मेरे पास है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मानसिक चिकित्सालय सरगुजा में खोल रहे हैं, उसको हटाईए, उनका दिमाग वैसे ही उड़ चुका है। समझ रहे हैं। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, डॉ. विनय जायसवाल जी।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- भैया, रायपुर में निमैंस क्यों आ रहा था ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आवास, आपने 3,238 करोड़ रूपए की व्यवस्था की। (व्यवधान) लगभग 2 लाख 3 हजार ग्रामीण आवास। इसके बाद भी 14 लाख परिवार बच जाएगा, उसका क्या होगा ? यह वर्ष 2022 तक पूरा होना था और 2022 तक इसको पूरा करके जो बाद में आवास प्लस टू की सूची बनी थी, उसका काम होना था। इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है। जन घोषणा पत्र में तो लिखा है ना, हम पांच सदस्यीय परिवार को दो कमरे का मकान बनाकर देंगे। उनको बाड़ी देंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देंगे ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- कब दोगे, सपनों में ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, अभी दे रहे हैं। थोड़ा सा रूकिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो प्रधानमंत्री आवास मिलना था, वह तो दे नहीं पा रहे हो।

श्री बघेल लखेश्वर :- भैया जी, यह भी बता दीजिए, यू.पी.ए. सरकार के समय आवास के लिए 90 प्रतिशत पैसा मिलता था, आपके द्वारा 60:40 प्रतिशत का रेशियो कर दिया। उसको भी थोड़ा बता दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 लाख परिवार के सर से छत छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है और यह बोलते हैं कि भूपेश बघेल है तो भरोसा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां बिल्कुल भरोसा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब उसके बाद लज्जा नहीं आती तो भगवान ही मालिक है। उसके बाद आपको लगता है कि भरोसा है तो भगवान मालिक है। माननीय डहरिया जी, आपकी बुद्धि पर तरस भी आता है। माननीय डहरिया जी, पांच साल में एक मांग पूरा नहीं कर पाए। जिस दिन बजट पेश हुआ तो दो दिन पहले से चल रहा था, क्या चल रहा था, भरोसे का बजट। भरोसे का बजट आने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले लाईव चल रहे थे। अनियमित कर्मचारी का एक टिप्पणी बता देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- बजट पेश होईस ता तुमन बेहोस हो गे रेहेव।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब-जब भरोसा किया है जनता ने, तब-तब भरोसा तोड़ा है कांग्रेस ने। अब तो कांग्रेस और उनके नेताओं पर भरोसा करने का मन नहीं करता। देख लिया आपके भरोसे का बजट। अनियमित संविदा कर्मचारियों ने भरोसे के बजट पर यह ट्वीट किया। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सम्मान कर रहे हैं, इनको तो इस बजट के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। माननीय, शराबबंदी का क्या हुआ ? समिति बिहार जाकर आ गयी। गंगाजल उठाकर शपथ लिये थे।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अभी मध्यप्रदेश भी जाएंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब तो कुल 6 महीने बच गये। शराबबंदी का क्या हुआ? आपके शराब के कारण क्या हो रहा है ? छत्तीसगढ़ दुर्घटना का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक अपराध करने वाला क्षेत्र बन गया है। आप कर क्या रहे हैं? किसानों को छल रहे हैं, बेरोजगारों को छल रहे हैं, ग्रामीणों को छल रहे हैं, सबको छलने का काम किए हैं, उसके बाद भरोसे का बजट बोलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भरोसे का बजट नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने वाला बजट है। मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा होती है तो यूजवली दो तरह की चर्चा होती है। जब सरकार किसी बजट में डिलेवर करती है, अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है तो वह सीधे।

श्री अजय चंद्राकर :- डॉ., मैं एला रख के आवत हो, जब घण्टी बजही तब मैं जाहुं। (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- आप बैठिये, थोड़ा सुनिये। आप जल्दी आइये।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब, ओला घलो सूजी दे दुहुं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है और जनता को उसको डिलेवर करती है तो उसकी बात करती है और जब विपक्ष के पास बजट पर चर्चा के लिए कोई भी विषय नहीं बचता है तो वह केवल आंकड़ों की बाजीगरी करती है। आज जो संपूर्ण बजट की चर्चा हो रही थी, उसमें शिवरतन शर्मा जी हो या सौरभ जी हो, जितने लोगों ने भी चर्चा में भाग लिया, किसी ने भी बजट, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ ने भूपेश के भरोसे का बजट माना। जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक स्लोगन है कि भूपेश है तो भरोसा है। आज इस सरकार ने उस भरोसे को कायम करने का बजट प्रस्तुत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और [XX]की हद होती है। शिवरतन शर्मा जी, [XX]की हद होती है। वर्ष 2003 के घोषणा पत्र में यह बोले कि हम हर जरूरतमंद बेरोजगार को, जो बारहवीं पास युवक-युवती हैं उनको 500 रूपये मासिक।

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉ. साहब, यह वर्ष 2003 के बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। यह वर्ष 2023 के बजट पर चर्चा हो रही है। आप क्या देखेंगे?

डॉ. विनय जायसवाल :- आप भी तो वही चर्चा कर रहे हैं। आप घोषणा पत्र की बात सुन लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके कृत्यों पर भी तो चर्चा होगी।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। आपने तो...। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- जब मैं बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बारहवीं पास युवक-युवतियों को 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने 2500 रूपये देकर इसको पूरा करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) यह क्रियान्वयन है। यह डिलेवरी है। यह आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। इस अप्रैल से बारहवीं पास युवक-युवतियों को 2500 रूपये बेरोजागरी भत्ता मिलने वाला है। माननीय अमरजीत भगत जी बोल रहे थे कि हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देंगे। गाय भी नहीं दिखी और जर्सी भी नहीं दिखा।

श्री रामकुमार यादव :- कई जगह हमन ला इही मन हैं करके धर दे तो हमन छोड़ा के भागे हन।

डॉ. विनय जायसवाल :- लेकिन आज।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि यह जर्सी गाय और सांड की बात कर रहे हैं तो उसको हमारे सत्तू भैया ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। (हंसी) सत्तू भैया, आप इनको बताइये, यह गाय और सांड की बात कर रहे हैं। आप इनको थोड़ा समझाइये।

डॉ. विनय जायसवाल :- देखिये, मैं अभी डिरेल नहीं होऊंगा। आप और अजय चंद्राकर जी बार-बार बोलते हैं कि आप कितना भी टोको, मैं डिरेल नहीं होऊंगा। मैं डिरेल नहीं होने वाला हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस गोधन न्याय योजना के लिए बजट का प्रावधान है जिसकी day one से, योजना के

प्रारंभ से लगातार अजय चंद्राकर जी हो या पूरा का पूरा विपक्ष हो, इन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाने का काम किया है। इन्होंने उसको हमेशा मजाक का विषय समझा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी यह बोल रहे थे कि आप यह बताइये कि इस योजना से किसको इंकम हुआ है, आप चलिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गौ पालक है उसने अपने बच्चे को 3 लाख रूपये देकर कोटा में जाकर कोचिंग कराया और आज वह बच्चा कवर्धा मेडिकल कॉलेज, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला है इस गोधन न्याय योजना से उस बच्चे ने कोचिंग किया और मेडिकल के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कवर्धा में जो मेडिकल कॉलेज खोला है आज उस कॉलेज में वह फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। यह डिलेवरी है। यह योजना है कि गोधन न्याय योजना से हमारा एक गरीब परिवार इतना मजबूत हुआ कि वह बच्चा कोटा में जाकर महंगी पढ़ाई (कोचिंग) किया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बजट में यह भी प्रावधान है कि कोटा में जो बड़ा मेडिकल कोचिंग होता है इस बजट में यह प्रावधान है कि वहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार बच्चों के लिए एक बड़ा हॉस्टल खोलने जा रही है जिससे हमारी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वहां पर जाकर अच्छे से रहकर वहां पर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो यह सब योजनाएं हैं। आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, अभी हमारे शैलेश पाण्डे जी ने बहुत सारी बातें बताईं। आज मनेन्द्रगढ़ जैसे सुदूर क्षेत्र, जहां का मैं विधायक हूं, जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं कभी सपने में भी वहां के लोगों ने नहीं सोचा था कि वहां मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। आज इस बजट में पूरे प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है, उसमें से एक मेडिकल कॉलेज का प्रावधान मनेन्द्रगढ़ में किया गया है। आपने यह बात नहीं बताई । आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- केन्द्र सरकार के द्वारा खोला जाता है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- केन्द्र सरकार किसी के अब्बा का है क्या, वह भी हमारे टैक्स का पैसा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ का बजट किसके अब्बा का है, वह भी बता दो ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी केन्द्र और राज्य की बात करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उधर ध्यान मत दीजिए । आप इधर देखकर बात करिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उधर नहीं देख रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- दोनों माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं मतलब आप समझ जाईए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी केन्द्र और राज्यांश की योजनाओं की बात करते हैं । अभी इन्होंने बताया कि मनरेगा से लेकर जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, सभी योजनाओं की बात हुई कि किस तरह से करटेल किया है । जब यू.पी.ए. की सरकार थी, उस समय

का राज्य परिवर्तित योजनाओं का केन्द्रांश क्या था और आज क्या है ? यह बात भी इन लोगों को कहनी चाहिए । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में ये कहते हैं कि केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत दे रही है, लेकिन One Time Investment के लिए दे रही है, One Time Infrastructure Development के लिए दे रही है । हॉस्पिटल कहां से आएगा, डॉक्टर कहां से आएंगे, मेडिकल कॉलेज कैसे चलेगा ? ये सारे का सारा प्रावधान अगर साहस के साथ किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करें तो इन्होंने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया । जिन्होंने लगातार 15 साल भ्रष्टाचार किया है, उनको सपने में भी भ्रष्टाचार दिखता है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । मैं जिस दिन विधायक बनकर मनेन्द्रगढ़ में गया था, वहां पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं थे, वहां पर एक मात्र केन्द्रीय विद्यालय था । उस विद्यालय में एडमिशन के लिए मेरे पास 1000 आवेदन आते थे । आज नगर निगम, चिरमिरी में दो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मनेन्द्रगढ़ में 1 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और खड़गवां, जो हमारा पंचायत है, वहां 1 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है । आपको बताना चाहूंगा कि मुझे विधायक बने चार साल हो गए हैं । इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए 1 हजार आवेदन आते थे, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यह केन्द्रीय विद्यालय के लिए आवेदन आते थे, आज वहां डीएव्ही स्कूल है, जो प्रोजेक्ट स्कूल हैं, एस.ई.सी.एल. जो प्रोजेक्ट स्कूल हैं, उसके एडमिशन के लिए आवेदन मेरे पास नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परिवर्तन क्या हुआ है? इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो 1 हजार आवेदन आते थे, वह आज मात्र 10 आवेदन आते हैं । यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । आप कहते हैं कि वहां पर डेप्युटेशन से शिक्षकों को लाकर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया । आपको तो पता ही नहीं है, आपका रिसर्च ही नहीं है । आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भर्तियां हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में आप देखेंगे और जो सलेक्शन पद्धति आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है । जो बच्चा के.जी. और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और बी.एड तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए बच्चे हैं, उनका सलेक्शन वहां किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि मछली का कांटा गले में फंस जाये तो उसका ईलाज अस्पताल में होता है, आत्मानंद स्कूल में नहीं होता । इनके गले में मछली का कांटा फंस गया था तो डॉ. विनय बड़ी मुश्किल से बचे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, उसके लिए भी इस बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल

और 96 पदों की स्वीकृति इसी बजट में की गई है । अब मछली का कांटा फंसेगा तो कहीं इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं निकल जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गए, अपनी बात समाप्त करें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मेरा संकल्प था, उसमें पिछली बार भी आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया था, आज भी ऐसा कह रहे हैं। समय दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांटा कौन सी मछली का था डॉक्टर और सिर्फ मछली था या उसकी नीचे में थोड़ा बहुत कुछ और था ? डॉ. सच, सच बताओ कि थोड़ा बहुत और कुछ था या सिर्फ मछली था ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग मछली के पीछे क्यों पड़े हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, कांटा एक तरफ दो लोगों को एक साथ फंसाया था। एक तरफ इनको और दूसरी तरफ कवासी लखमा को डोंगरगढ़ में फंसाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- टोका-टाकी न करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसी का कांटा फंस रहा है तो आपको क्या दिक्कत है ?

संसदीय सचिव (खाद्य मंत्री से सम्बद्ध) (श्री कुंवर सिंह निषाद) :- महाराज मन ला कांटा से का मतलब हे ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा किया। 500 रूपया देने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि सन् 1990 तक वनभूमि पर काबिज हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनको पट्टा दिया जायेगा। लेकिन कहां पट्टा बंटा ? आज लाखों की संख्या में वन अधिकार पट्टा बांटने का काम हमारी सरकार ने किया है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, डाक्टर समेत 2-3 लोगों को मछली का कांटा फंस रहा है। एकाध अस्पताल में विभाग खुलवाओ कि आपके विधायक, मंत्रियों के गले में कांटा ना फंसे।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक तो कांटा-वांटा के बारे हमारी समझ कम है। लेकिन आप बता रहे हैं कि कई लोगों के गले में कांटा फंस गया था। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि जिन्दा मछली ना खाया करें। (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले बजट भाषण की चर्चा याद आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने, ..

श्री धर्मजीत सिंह :- चौबे जी, मछली का ..

डॉ. विनय जायसवाल :- भईया, मुझे बोलने दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको पूरा टाईम दिलायेंगे। हम अपना टाईम दिलवा देंगे, चिंता मत करिये। चौबे जी, मछली का एक सिद्धांत है। बहुत इत्मिनान से खायेगा तो कांटा धीरे से निकलेगा और

हडबड़ी करेगा उसके गले में फांस फंसता ही है। आप देख भी लीजियेगा। छत्तीसगढ़ में भी यह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आराम से खाईये। 2 पैग के साथ वह गला भी देता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो यह सलाह इधर मत दो, उधर दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- सवाल यह है कि जो कांटा फंसा, इनका कहना है कि दो पैग लेने से कांटा नहीं फंसेगा। इसको तसदीक किया जाये कि 2 पैग के साथ कांटा नहीं फंसता।

श्री कुंवर सिह निषाद :- मछली के प्रीपेशन के ऊपर घलो हे। तै कतका प्यार से मछली ला रांधे हस, तेखर ऊपर हे, फेर कांटा नइ फंसय।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग तो पहली बार विधायक बनकर आये हैं। आप पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के भाषण की चर्चा निकालकर देखियेगा, जब सरकार ने अपना वादा पूरा किया और 10 घंटे के अंदर 9 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया और 2500 रूपया समर्थन मूल्य तय किया। मैं उस समय उनका भाषण सुना था कि इतना-इतना प्रावधान करना, कैसे इसका वित्तीय प्रबंधन होगा, वित्त के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा कहा गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार को बने 4 साल हो गए हैं। हम इस साल तो किसानों को 2640 रूपया धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमने किसानों का कर्ज भी माफ किया। आज राज्य का इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन है कि 350 से अधिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। हमने इस बजट में 4 मेडिकल कॉलेज, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कालेज हो गए, मैं आपको यह बात बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा वित्तीय प्रबंधन है। आज आप जाकर देखिये, पूरी सड़कें बन गई हैं। आज सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं। ये अधोसरंचना की बात करते थे कि अधोसरंचना के ऊपर काम नहीं हो रहा है। इस सरकार ने अधोसरंचना के ऊपर जितना काम किया है, उसका आधा काम इन्होंने 15 साल में नहीं किया है, आपको यह बात मैं बोलना चाहता हूं। निश्चित रूप से जो भरोसे का बजट प्रस्तुत किया गया है, वह किसान के हित के लिए है, वह हमारे युवाओं के हित के लिए है, वह हमारे विद्यार्थियों के हित के लिए है। सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए बजट की प्रस्तुति हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तुलनात्मक अंतर करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार का भी बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें बताया गया कि हमको 50 साल में इसका ग्रोथ दिखेगा। मोदी जी ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, मोदी जी की सरकार ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है कि इसका रिजल्ट 25 साल, 50 साल बाद दिखेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो भरोसे का बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है, मैं आपको यह बात बोलना चाहूंगा। आपने बोलने का मौका, बाकी सदस्यों ने डिरेल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी लगभग बातों को रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मैंने मेरे क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मेडिकल कालेज को इस बजट में स्थान देने का काम किया। मैं उसके लिए

उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा उन्होंने सौ बिस्तर का सिविल अस्पताल की बड़ी सौगात दी। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा क्षेत्र गौरवान्वित है कि वहां बच्चे को उद्यानिकी महाविद्यालय में पढ़ना है, पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय में पढ़ना है या उसको डॉक्टर बनना है, उसको रायपुर या बिलासपुर जाने की जरूरत नहीं है । मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में हमारा बच्चा पढ़ाई कर लेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, अपनी बात को समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्ष 2023 का यह अंतिम बजट यहां पेश हुआ है, यहां पर पक्ष के माननीय सदस्य बजट की बहुत तारीफ कर रहे थे और यहां विपक्ष के द्वारा आलोचना भी की गई । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी सौरभ सिंह जी अपनी बात कह रहे थे, यूपीएससी पास किये हुये आईएएस के पद को छोड़कर आये हुये हैं, वह डीजीपी और ग्रोथ के बारे में बता रहे थे, मेरा मानना है कि आधे विभाग को समझ में नहीं आया होगा । यह बात सही है कि पक्ष वालों को मेज थपथपाना है, उनका पक्ष लेना है, आधे से ज्यादा विधायकों को यह भी नहीं मालूम है कि बजट का अनुमान और जो टेक्नीकल बात बता रहे थे, उसमें बहुत सारे दो-चार मंत्री लोगों को भी नहीं मालूम है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- प्रमोद भईया किधर बोलना चाह रहे हैं, इधर बोलना चाह रहे हैं या उधर बोलना चाह रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- न मैं इधर बोलूंगा, न उधर बोलूंगा । सौरभ सिंह जो बता रहे थे 17 परशेंट ई.डी. के आने के बाद जो ग्रोथ हुआ, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर सदस्य बैठे हुये हैं, सुनियेगा । बलौदाबाजार जिले में शराब की बिक्री पर डे 50 लाख रूपये से 55 लाख रूपये थी, जिले की बात कर रहा हूँ ।

डॉ.विनय जायसवाल :- प्रमोद भईया एक मिनट । सिर्फ 30 सेकण्ड । सदस्य की बड़ी चिंता है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जब से ई.डी. का रेड हुआ, वह डेढ़ करोड़ को पार कर गया है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, न कोई होली है, न कोई दीवाली है, ई.डी. का रेड पड़ने से 1 करोड़ पर डे का बलौदाबाजार जिले में शराब की बिक्री बढ़ जाती है। तो सोच लो, ई.डी. का तो छत्तीसगढ़ में स्वागत करना चाहिये, जो यहां राजस्व का लाभ दे रहा है । अचानक बिक्री कैसे बढ़ा है ?

डॉ.विनय जायसवाल :- 30 सेकण्ड बोल लेने दो, फिर बोलना । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पम्मू भाई को बड़ी चिंता है । क्या है, जो इनका बड़ा वाशिंग मशीन है, उसमें सीबीआई, आई.टी. ई.डी. वगैरह सब है, वह मशीन में घुस गये हैं । डर है कि कहीं उधर न आ जाये ।

सुश्री शकुंतला साहू :- इनको चमका-चमका कर अपनी तरफ कर रहे हैं क्या ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मेरा एक ही सवाल है, ईमानदारी से अपने मन में हाथ रखकर बोलियेगा, ई.डी. का छत्तीसगढ़ में आने के बाद हमारे जिले में शराब की बिक्री अचानक 1 करोड़ कैसे बढ़ गया ? अधिकारी हड़बड़ा गये हैं । शराब दुकान को बंद कर नहीं सकते हैं और बिक्री को रोक नहीं सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट्राचार तो चरमसीमा पर है । माननीय चन्द्राकर जी शायरी में जो शरम वाली बात बोले हैं, मैं तो बोलता हूँ कि इस सरकार को हमारे नवजवान साथी लोग नये-नये हैं..।

श्री अमरजीत भगत :- प्रमोद भाई, वह जो बात आप बोल रहे हैं ना, उसमें आप चन्द्राकर जी को गुरू गलत चुन लिये हैं । वह आपको हमेंशा गलत शिक्षा देंगे। उसके चक्कर में आप उलझेंगे, फंसेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- गुरू बनाले जान के, पानी पीले छान के । जान के गुरू बनाववं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :-उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत सी बातें करनी है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पहला गुरू बनाये जोगी जी को, वह नहीं रहे । दूसरा गुरू बनाये देवव्रत भईया को, वह नहीं रहे, अब तीसरा ...। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय श्री गणेशशंकर बाजपेयी जी मेरे गुरू थे, वह सही बात है, जो तीन साल तक नहीं टिके । माननीय जोगी जी थे, वह भी नहीं टिके, हमारे देवव्रत भईया थे, वह भी नहीं रहे । अब धरमजीत भईया का तबियत खराब रहता है । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मोर चन्द्राकर भईया, वईसन नोहे ।

सुश्री शकुंतला साहू :- कल से पम्मू भईया, अकेले-अकेले घुमेंगे । इनके पास कोई नहीं फटकेगा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे समय में वृद्धि करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सीधे इधर बात करिये ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धरमजीत जी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें । हमारी शुभकामनायें हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमारे आदरणीय है, सब चीज है, हमारे भगवान है वो । ऐसा नहीं है । (हंसी) एक हास्य था, माननीय । क्षमा चाहूंगा ।

डॉ.विनय जायसवाल :- आप धरमजीत भईया को डरा दिये हो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बजट जो पेश हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । जैसा कि सभी वर्ग के लिये बात कर रहे हैं..। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी को परेशान होते देख रहे हैं, लग रहा है कि अगला गुरू आप ही हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मोला बोलन दो ना। बजट पेश हुआ और यहां पर सभी ने बोला कि यह सभी वर्ग के लिये है। सहायक शिक्षक की जो बात है, आज उनकी 4 सालों से लगातार मांग है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनके वेतन विसंगती को दूर करने की बात हुई थी। लेकिन वह बजट में कहां है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के लिये भले ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज चौथा साल है और उनके लिये एक-एक दिन भारी है। महंगाई का जमाना है। वर्ग-एक, वर्ग-दो और सहायक शिक्षकों की, सबकी डिग्री सेम है। उनकी वेतन विसंगती को दूर करने के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इनकी यह मांग को पूरा कर दें। हमारे जितने भी विधायक साथी है, वे इस बात को याद रखिये कि एक-एक विधान सभा में इनकी संख्या कम से कम 3-3 हजार की है। मैं सहायक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि यदि वे 50-50 लोग भी खराब करेंगे तो 15 हजार वोट हो रहा है। यह पूरा कांग्रेस पार्टी का नुकसान रहेगा। आप लोग भी अपनी सरकार से मांग करिये और सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगती है उसको दूर करे। अभी-भी समय है, आप लोग जाग जाईये और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मांगों को पूरा कर दें। नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।

श्री भूपेश बघेल :- आपको हमारी बहुत चिंता है। उसके लिये धन्यवाद्। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले आपके एक सदस्य ने गुरूओं के बारे में बताया है। यह आपका चेला बनेगा तो आपको गुरू बनने का बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ऐमा सहायक शिक्षक मन हो भयंकर बड़ा नुकसान होथे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे प्रमोद शर्मा जी हमेशा बाहर में स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जैसे साहसी आदमी कोई नहीं है। लेकिन हमको अंदर तो बोलना पड़ता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमोद शर्मा जी को 5 साल में सभी दलों का अनुभव हो गया है। वह 5 साल पहले मेरे साथ पद यात्रा कर रहे थे। उसके बाद जोगी कांग्रेस से आये। पहले वह जिला पंचायत सदस्य थे, अब विधायक बने। अब वह इनकी संगत में पड़ गये हैं। उनको पांच साल में तीन-तीन पार्टियों का अनुभव है। यदि वह अपना अनुभव साझा कर रहे हैं तो सबको सुनना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे। डॉक्टर साहब, मुझे यह बोलने में कोई संकोच नहीं है। मैं यह सदन में भी बोल सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दबंग, दमदार है। इस बात को पूरा छत्तीसगढ़ स्वीकार करता है (मेजों की थपथपाहट)। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब लिस्ट बनी थी तो जो उनके दोस्त यार, जो उनके संघर्ष में साथ दिये, उनको उपकृत किये। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा नाम दुश्मनों की लिस्ट में था तो हमको उपकृत नहीं मिल पाया। मैं

बाहर बोलता हूं और अभी-भी बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दबंग, दमदार मुख्यमंत्री तो है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में यह सरकार सबसे आगे है, मुझे यह बोलने में भी कोई संकोच नहीं है।

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। चलिये शर्मा जी बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत सारे समय को डिस्टर्ब कर दिये इसलिये मुझे थोड़ा-सा बढ़ा कर समय दीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसीलिये तो बढ़ाया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या करूं जब मेरे समय में सब बोल दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा था। लोकतंत्र की हत्या। जैसे की हर पार्टी बोलती है कि हम अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। मैं बहुत छोटा-सा उदाहरण बताता हूं। हमारे तिल्दा ब्लॉक में एक सिरोधा गांव है। वहां पूरे के पूरे पंच लोग अपने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये। कांग्रेस के एक-दो नेता इसको खसका-खसकाकर 55 दिनों तक खींच लिये। यह लोकतंत्र का नियम है कि यदि कहीं से अविश्वास प्रस्ताव आये तो वहां से नियम से उनको हटाने के लिये या चुनाव कराने के लिये अनुमति देना ही पड़ता है। वे उसको 55 दिनों तक खींच दिये। अंतत: इनको 55 दिनों के बाद समय देना पड़ा और 55 दिन के बाद वह सरपंच का वहां से हटना तय नहीं हुआ, वहां चुनाव हुआ और वह सरपंच हार गया। उसके बाद कलेक्टर साहब की जानकारी के बिना अपर कलेक्टर 5 लाख रूपये लेकर स्टे ऑर्डर दे दिये, यह है लोकतंत्र (शेम-शेम की आवाज)। रायपुर के कलेक्टर साहब को मालूम ही नहीं है कि स्टे ऑर्डर कैसे मिला, यह है बिक्री। सरकार कहां गयी ? यहां सरकार नहीं चल रही है, यहां दुकान चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक दुकान है, जहां पर प्रमोशन के नाम पर, पदोन्नति के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर धंधा हो रहा है और इसकी पूरी फीस भी निर्धारित है। ट्रांसफर करने का यह रेट है, इसका यह रेट और पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा छत्तीसगढ़ गर्त में जा रहा है। जहां तक डी.एम.एफ. की बात है ।

समय :

7.00 बजे

माननीय मोहन मरकाम जी ने 7 करोड़ रूपये की बात कही है। मैं खुले रूप से चुनौती देता हूँ। बलौदा बाजार में डी.एम.एफ. का बजट 80 करोड़-100 करोड़ रूपये का है जिसमें 40 से 50 करोड़ रूपये का स्वार्थ पूर्ण बंटवारा किया गया और आप जांच करायेंगे तो अच्छी तरीके से पता चल जायेगा कि वहां पूरे तरीके से लिप्त हैं, जिसमें पता नहीं, रायपुर के कौन से बंगले से ठेका लेने के लिए आते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 लाख रूपये के ठेके के लिए भी लोकल में किसी स्कूल की सफाई करवानी है तो मंत्री महोदय, स्कूल में सेप्टीक को साफ करने के लिए फिनाईल गोली, डामर गोली का ठेका निकलता है तो रायपुर से आते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी के यहां से आये हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बंगला कहां है और वहां रायपुर से 5 लाख रूपये ठेके के लिए आ रहे हैं तो यह भ्रष्टाचार का आलम है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को खुले आम बढ़ावा देने के लिए लज्जा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें तो छत्तीसगढ़ मॉडल, यह हिन्दुस्तान के लिए सही में मॉडल है, लेकिन यह भ्रष्टाचार के मामले में मॉडल है। अगर हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा मॉडल भ्रष्टाचार का है यदि अन्य राज्यों में भी सिखाया जाए कि भ्रष्टाचार को कैसे किया जाता है ? कैसे पैसा अंदर से कमाया जाता है यह छत्तीसगढ़ पूरे हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़ा मॉडल है। अगर आप कहें तो मैं आपको सबूत के साथ बता दूं। जैसे कि सी.एस.ई.बी. में बताना चाहूंगा। यहां माननीय मंत्री महोदय, अभी अडानी को छूट देने की बात कर रहे थे। वर्ष 2001 के विद्युत अधिनियम को दरकिनार करते हुए, नियम के खिलाफ में वर्ष 2023 में बालकों में 3400 रूपये विद्युत की छूट दी गई है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप निकाल लें और बोलेंगे तो मैं इस सदन में साबित कर दूंगा। जैसे की कोई टेण्डर होने की बात होती है..।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा साहब, अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जा विभाग है। कोई भी टेण्डर हो, जैसे कोई सब स्टेशन हो, चाहे अभी सेन्टर से जो एक योजना में 12 हजार करोड़ रूपये आया, उसका पैकेज बन रहा है एम. डी. के द्वारा 5 प्रतिशत के बिना ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय प्रमोद जी तैं बैल के दूध दूहे के कोशिश करत हस। बिना पैर सिर के बात करत हस।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबूत दे दौं। आप सुनौं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिस्टल का आवेदन किया था। पिछले सदन में यहां पर चिल्ला-चिल्ला कर बोला कि मुझे पिस्टल का लाईसेंस दिया जाये, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चुड़ैल भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन वहां से विधायक जैसे के लिए भी 5 लाख रूपये की डिमाण्ड हुई। अगर आपने 5 लाख रूपये नहीं दिया तो मुझे पिस्टल का लाईसेंस नहीं मिला। मैं तो बोलता हूँ कि यह सरकार कहां चल रही है, यह दुकान चल रही है और यह दुकान क्या है, यह भ्रष्टाचार की दुकान है। इसमें आप सब पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ। मैं बैल से दूध दूहे के कोशिश नइ करत हों। मैं चेहरा, आईना दिखावत हों। पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार हे। अउ एकर दीया में तेल बुझा गे हे। अब ये बुझाने वाला हे। अब ए आखिरी बजट हे एखर बाद पेश करे के कभु मौका ही नइ मिले। एकर सेती बजट के पूरा-पूरा और घोर विरोध करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(7 बजकर 3 मिनट पर विधान सभा मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 2023) (फाल्गुन 23, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 13 मार्च, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं